भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 1 कार्तिक, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 173, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

सूर्योदय 6:25 सूर्यास्त 5:48

आज का तापमान

शिमला	12.0 न्यू	23.0 अधि
धर्मशाला	15.0 न्यू	25.0 अधि

बाजार

सेंसेक्स	74,729.27
निफ्टी	23,146.15
सोना 1,46,514	चांदी 2,10,000

न्यूज शॉर्ट्स

पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 5 गुना बढ़ी, 2.50 रुपए हुई डीजल पर 7.50 घटाया

एजेंसी, नई दिल्ली। कच्चे तेल की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर 5 गुना टैक्स बढ़ा दिया है। वहीं, डीजल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को लगभग आधा कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने देश में फ्यूल की कमी न हो इसलिए नई दरें 16 अक्तूबर से लागू कर दी हैं। नए टैक्स अगले दो हफ्तों तक लागू रहेंगे। इस टैक्स का असर सिर्फ विदेश बेचे जाने वाले पेट्रोल-डीजल पर पड़ेगा। हमारे देश के पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़लेंगे। सरकार हर 15 दिन में अंतरराष्ट्रीय कीमतों को देखकर यह टैक्स तय करती है।

अमेरिका के स्कूल में गोलीबारी, 4 की मौत

एजेंसी, वॉशिंगटन। अमेरिका के ओरेगन राज्य के बेंड शहर में वीरवार को एक स्कूल में गोलीबारी हुई। इसमें 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। सीएनएन के मुताबिक, हमलावर को एक स्थानीय नागरिक ने गोली मार दी, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर की उम्र करीब 16 साल थी। एजुकेशन वीक की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल में गोलीबारी का यह इस साल का 26वां मामला है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, मारे गए बच्चों की उम्र 5, 8 और 11 साल थी। मरने वालों में एक शिक्षक भी शामिल है। गोलीबारी में घायल 7 साल के एक बच्चे और 54 साल के शिक्षक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

रूस में 7 तीव्रता का भूकंप जापान में 9.9 का अलर्ट, 12 मिनट तक रही अफरातफरी

एजेंसी, कामचटका। रूस के कामचटका प्रायद्वीप में शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे 7 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। इसके कुछ देर बाद जापान की मौसम एजेंसी ने गलती से 9.9 तीव्रता के भूकंप की चेतावनी जारी कर दी। इससे देशभर में अफरातफरी मच गई। हालांकि, एजेंसी ने करीब 12 मिनट बाद अलर्ट वापस ले लिया। जापान की मौसम एजेंसी ने इस गलती के लिए माफी मांगी है। जापान की भूकंप चेतावनी प्रणाली जमीन पर लगे सेंसर से मिले शुरुआती आंकड़ों के आधार पर भूकंप की तीव्रता और उसके असर का अनुमान लगाती है। यह काम कुछ ही समय में किया जाता है। शुरुआत में आंकड़े अधूरे होने के कारण अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन इस बार 9.9 तीव्रता का अलर्ट जारी करना बड़ी चूक थी। इतनी तीव्रता का भूकंप अब तक दर्ज नहीं किया गया है।

'लहरा दो तिरंगा' यात्रा से पहले अभिजीत व नेहा बोरा हिरासत में

समर्थकों ने पुलिस की गाड़ी रोकी; सीजेपी के कार्यकर्ता सेंट्रल पार्क के पास जुटे

एजेंसी, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके और AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दीपके तिरंगा रैली में शामिल होने सेंट्रल पार्क जा रहे थे।

6 दिनों में दीपके को दूसरी बार कस्टडी में लिया गया है। इससे पहले 10 अक्तूबर को जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले दीपके को विमान से हिरासत में लिया गया था, अगले दिन छोड़ दिया गया। नई दिल्ली जिले में बीएनएसएस की धारा 163 लागू है। यानी 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इसके बावजूद कनॉट प्लेस इलाके में सेंट्रल पार्क के पास सीजेपी समर्थक जुटे हैं।



सीजेपी बोली- सरकार को लोकतांत्रिक ताकत से डर है

कॉकरोच जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि अभिजीत दीपके को केवल इसलिए हिरासत में लिया गया, क्योंकि वह राष्ट्रीय ध्वज लेकर निर्धारित स्थान की ओर जा रहे थे। कॉकरोच जनता पार्टी के अनुसार, यह कार्रवाई दिखाती है कि प्रशासन को किसी अव्यवस्था से नहीं, बल्कि आम नागरिकों के हाथों में तिरंगे की शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ताकत से डर है।

सुप्रीम कोर्ट का सीजेपी का प्रदर्शन रोकने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के व्यापारियों की याचिका पर तत्काल आदेश देने से इनकार कर दिया। याचिका में कॉकरोच जनता पार्टी के सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन से कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने प्रदर्शन से जुड़ी अन्य याचिकाओं का जिक्र करते हुए कहा, 'कोई प्रदर्शन करना चाहता है, कोई मूंगफली बेचना चाहता है, कोई कानून-व्यवस्था चाहता है, ये सभी बातें आपस में जुड़ी हैं।' प्रदर्शन के कारण नई दिल्ली नगर परिषद ने सेंट्रल पार्क बंद करने का आदेश दिया है। व्यापारियों का दावा है कि इससे कनॉट प्लेस बाजार में रोजाना 200 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हो सकता है। याचिका दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन ने दायर की है। शुक्रवार सुबह सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की।

2020 दिल्ली दंगे: अदालत ने सात आरोपियों को हत्या के आरोप से बरी किया

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के एक मामले में एक व्यक्ति की जानलेवा पिटाई से जुड़े हत्या और अन्य गंभीर आरोपों से सात लोगों को बरी कर दिया है। अदालत ने उन्हें निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया है। पुलिस के एक गवाह की अकेली गवाही के आधार पर आरोपियों को जानलेवा हमले का दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं होगा। इस गवाही की पुष्टि के लिए अन्य साक्ष्यों की आवश्यकता थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह ने सात आरोपियों को हत्या, घातक हथियारों के साथ दंगा करने और वैमनस्य फैलाने सहित अन्य आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि, उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया। 15 अक्तूबर के आदेश में अदालत ने कहा, किसी भी गवाह की गवाही से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि आरोपियों में से कोई भी घातक हथियार या किसी भी तरह का हथियार लेकर आया था।

सड़क सुरक्षा पर अफसरों को सुप्रीम चेतावनी, कहा-

काम नहीं हुआ तो हाईकोर्ट के गेट पर धरना देंगे, सॉलिसिटर जनरल को घर नहीं जाने देंगे



एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के पास सड़क पार करने वाले लोगों की सुरक्षा के मामले में अधिकारियों को चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि अगर काम पूरा नहीं हुआ, तो दोनों जज दिल्ली हाईकोर्ट के गेट पर धरने पर बैठ जाएंगे और काम पूरा होने तक घर नहीं जाएंगे।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बनर्जी को भी घर नहीं जाने दिया जाएगा। यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट के पास सड़क पार करने वाले लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को केंद्र सरकार से कहा था कि वह दिल्ली हाईकोर्ट और नेशनल जूलॉजिकल पार्क के पास सड़क पार करने वाली जगह पर स्पीड ब्रेकर और रंबल स्ट्रिप्स लगाने पर फैसला ले। सुनवाई के दौरान कोर्ट की मदद के लिए नियुक्त एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने उस जगह रेड लाइट सिग्नल लगवा दिया है। केवल रेड लाइट लगाना काफी नहीं है। वहां स्पीड ब्रेकर और रंबल स्ट्रिप्स लगाने की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय गाड़ियों और पैदल चलने वालों की आवाजाही का अध्ययन करे। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रम बनर्जी ने कहा कि रेड लाइट लगाना पर्याप्त है, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि और इंतजाम की जरूरत है, तो केंद्र सरकार इसके लिए तैयार है। इस पर जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि यह लोगों की जान का सवाल है। हम दोनों वहां जाएंगे। आप भी हमारे साथ चलिए।

सीएम सुक्खू ने धर्मशाला में इंडोर आइस स्केटिंग रिंक व रोलर स्केटिंग रिंक की रखी आधारशिला

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के धर्मशाला स्थित सकोह में 33.78 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले इंडोर आइस स्केटिंग रिंक एवं रोलर स्केटिंग रिंक की आधारशिला रखी।

इस भवन के बेसमेंट में जिम, बिलियर्ड्स रूम और कैफे की सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त धरातल मंजिल में वीआईपी लाउंज तथा ऊपरी बालकनी में 1,079 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इस रोलर स्केटिंग रिंक की दर्शक दीर्घा में 250 लोगों के बैठने की क्षमता होगी, जबकि परिसर में 250 वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला शहर के लिए 982 लाख रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन सुविधा का भी लोकार्पण किया। इस संयंत्र की निर्धारित क्षमता 60 केएलडी प्रतिदिन है। इसके माध्यम से सीवरेज नेटवर्क से वंचित धर्मशाला के सात वार्डों को सुविधा मिलेगी, जिससे लगभग 7,500 परिवार लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के अध्यक्ष आरएस बाली, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (डिजिटल प्रौद्योगिकी, सुशासन एवं नवाचार) गोकुल बुटेल, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, सांसद अनुराग शर्मा, विधायक आशीष बुटेल तथा कांगड़ा कृषि उपज विपणन समिति के अध्यक्ष निशु मोंगरा और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।



सरकार इस माह बुला सकती है संसद का स्पेशल सेशन

एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्र सरकार इसी महीने संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। इसमें लोकसभा सीटें बढ़ाने के लिए संविधान (131वां संशोधन) बिल, परिसीमन (संशोधन) बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल को पास कराया जाएगा। इनके जरिए महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। 6 महीने (16 और 17 अप्रैल) पहले सरकार पहले प्रयास में कामयाब नहीं रही थी और लोकसभा में दो तिहाई बहुमत जुटा नहीं पाई थी। अब कहा जा रहा है कि सरकार ने संख्याबल जुटा लिया है। विशेष सत्र बुलाने से करीब एक हफ्ते पहले इसकी सूचना दी जा सकती है। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को खत्म हुआ था, लेकिन इसका अब तक सत्रावसान नहीं किया गया है।

नारीशक्ति के अदम्य साहस, अटूट संकल्प व अजेय पराक्रम का प्रतीक हैं मां कात्यायनी : मुख्यमंत्री योगी

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र की षष्ठी तिथि की बधाई दी। उन्होंने कहा कि समस्त बाधाओं और आसुरी प्रवृत्तियों का संहार करने वाली मां कात्यायनी नारीशक्ति के अदम्य साहस, अटूट संकल्प और अजेय पराक्रम का प्रतीक हैं।

मुख्यमंत्री ने आस्था, विकास व विरासत के जरिए राज्य में आए बदलाव से अवगत कराते हुए कहा कि प्रदेश में अब 'पदक लाओ, पद पाओ' के तहत खिलाड़ियों की सीधी भर्ती हो रही है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर पोस्ट कर पिछली सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में भय और अराजकता का ऐसा माहौल था, जहां बेटियों के सपनों पर पहरे थे, हौसलों पर बंदिशें थीं और प्रतिभा अवसर के अभाव में दम तोड़ने को मजबूर थी। खेल के मैदान माफिया के कब्जे में थे, संसाधन नदारद थे और बेटियों की उड़ान को पंख देने के बजाय, उनके सपनों को चारदीवारी में कैद कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि ओलंपिक, कॉमनवेल्थ एवं एशियन गेम्स के पदक विजेताओं को लाखों-करोड़ों के पुरस्कार और 'पदक लाओ, पद पाओ' के तहत सीधी भर्ती जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं।

अब सुरक्षा, प्रोत्साहन से लिखी जा रही बदलाव की नई गाथा



मुख्यमंत्री ने 2017 के बाद आए बदलाव को भी इंगित किया। उन्होंने कहा कि विगत साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में बदलाव की नई गाथा लिखी गई है। भय का स्थान सुरक्षा ने लिया है। उपेक्षा का स्थान प्रोत्साहन ने लिया है और संसाधनों के अभाव का स्थान खेल सुविधाओं के विस्तार ने लिया है। गांव के खेल मैदानों और ब्लॉक स्तरीय मिनी स्टेडियम से लेकर जिला स्तरीय स्टेडियम, मंडल स्तरीय स्पोर्ट्स कॉलेज तथा मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय तक, बेटियों को अपनी प्रतिभा निखारने का सशक्त आधार मिल रहा है।

पति की हत्या कर सांप छोड़ने वाली रविता को सजा-ए-मौत

एजेंसी, मेरठ। पति की हत्या करके सांप से डसवाने वाली रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को वारदात के 547 दिन बाद मेरठ जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।

शुक्रवार को सजा सुनाने से पहले कोर्ट ने रविता और अमरदीप का पक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुना। जज ने दोनों से पूछा तुम दोनों को हत्या का दोषी ठहराया गया है। क्या सजा चाहते हो? रविता ने कहा मेरे 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं। उनका ख्याल रखा जाए। फिर वह चुप हो गई। इसके बाद अमरदीप ने कहा मेरे मां-बाप बूढ़े हैं। उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। उनकी देखभाल में कोई कमी न रहे। इसके बाद दोनों फूट-फूट कर रोने लगे। एडीजे-12 जयवीर सिंह नागर ने नीला ड्रम हत्याकांड का नाम लिए बगैर कहा 'केवल काट डालना ही जघन्य अपराध नहीं है।' जज ने फैसले में सती सावित्री का जिक्र किया कहा- 'पति की लंबी उम्र के लिए पत्नी करवाचौथ का व्रत करती है, लेकिन यहां प्रेमी के साथ ये कृत्य किया जो माफी लायक नहीं है।' जज ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना और पेन तोड़कर फेंक दिया। मेरठ कोर्ट ने पिछले 3 दिन में 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इससे पहले 14 अक्तूबर को नीले ड्रम वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई गई थी। सौरभ राजपूत के भाई राहुल और उनकी मां रेनू देवी भी कोर्ट पहुंची थीं।



◆प्रेमी को भी फांसी होगी, मेरठ में 3 दिन में 4 को मौत की सजा

'समर्थक' युद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल

उपराष्ट्रपति ने कारवार नौसैनिक अड्डे पर स्वदेशी पोत राष्ट्र को किया समर्पित

एजेंसी, नई दिल्ली। कर्नाटक के कारवार स्थित कदंब नौसैनिक अड्डे पर स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत 'समर्थक' को भारतीय नौसेना के समुद्री बेड़े में शामिल कर लिया गया।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने यह स्वदेशी पोत कारवार नौसैनिक अड्डे पर राष्ट्र को समर्पित किया। आईएनएस समर्थक से नौसेना की भविष्य की परिचालन आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मिशनों के लिए एक बहुमुखी उपयोगिता मंच के रूप में कार्य करेगा। भारतीय नौसेना को 27 अगस्त को सौंपा गया यह जहाज सारे समुद्री परीक्षणों से गुजर चुका है। भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत चेन्नई के पास स्थित लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में निर्मित इस पोत में 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। बहुउद्देशीय पोत 'समर्थक' उन चार मल्टी-पर्पस वेसल्स (बहुउद्देशीय पोतों) में से पहला है, जिन्हें भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसे समुद्री बेड़े में शामिल किया जाना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।



आधुनिक सेंसरों से लैस है 'समर्थक'

मुख्य रूप से समुद्री निगरानी और गश्त के लिए डिजाइन किया गया 'समर्थक' कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान, लक्ष्य तैनाती और परीक्षण प्लेटफॉर्म, मानवरहित/स्वायत्त प्रणालियों के लिए 'मदरशिप', मानवीय सहायता और आपदा राहत, सीमित अस्पताल जहाज में परिवर्तन और बचाव कार्यों में सहायता जैसे कई अन्य कार्यों में भी सक्षम है। यह पोत एकीकृत कॉम्बैट सूट (युद्ध प्रणाली) स्वदेशी सेंसर, हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों से लैस है, क्योंकि इसे विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण समुद्री वातावरण में काम करने के लिए तैयार किया गया है।

पंजाब में नशा उतना नहीं, जितनी हो रही है बदनामियां : सीएम मान

एजेंसी, चंडीगढ़। फिल्लौर स्थित पंजाब पुलिस अकादमी में शुक्रवार को आयोजित 'युद्ध नशियां विरुद्ध' कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बेहद दो टूक अंदाज में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया।

मानसा में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की निर्मम हत्या के बाद राज्य में हुए 'बंद' के ठीक एक दिन बाद आए मुख्यमंत्री के इस बयान ने राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सोशल मीडिया पर पंजाब सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जाने के बाद सीएम मान ने साफ कर दिया कि ड्रग्स की समस्या को लेकर पंजाब को अकेले निशाना बनाया जा रहा है, जबकि जिम्मेदारी और अधिकार क्षेत्र दूसरे महकमों के पास भी हैं। मुख्यमंत्री ने इस पूरी स्थिति की तुलना पराली जलाने के मामलों से करते हुए कहा कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी पराली जलाई जाती है, लेकिन बदनाम सिर्फ पंजाब को ही किया जाता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पंजाब में उतना नशा नहीं है, जितना इसे दुष्प्रचार के जरिए फैलाकर दिखाया जा रहा है। केंद्र सरकार के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने आंकड़े और व्यवस्थाओं का हवाला दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ का 50 किलोमीटर का अधिकार क्षेत्र सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन आता है।



◆बीएसएफ का 50 किमी क्षेत्र केंद्र के अधीन, जिम्मेदारी भी निभाए

उत्तराखंड के शहरी निकायों को 328.27 करोड़ रुपए मिलेंगे, डीडीहाट में सड़क के लिए 72.63 लाख मंजूर

एजेंसी, देहरादून। उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकायों को विकास कार्यों और जरूरी सुविधाओं के लिए 328.27 करोड़ की धनराशि मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में पंचम राज्य वित्त आयोग के आधार पर अक्तूबर से दिसंबर 2026 की तीसरी किश्त जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा तीन गैर-निर्वाचित निकायों को अक्तूबर 2026 से मार्च 2027 की दूसरी छमाही के लिए 3 करोड़ जारी करने की स्वीकृति दी गई है।

वहीं, पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में तपड़ी घाट से गोलमानू प्राथमिक विद्यालय तक सीसी मार्ग बनाया जाएगा। कुणिया ग्राम सभा में इस सड़क के निर्माण के लिए सरकार ने 72.63 लाख की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दी है। निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए पहली किश्त के रूप में 43.578 लाख जारी करने का शासनादेश भी जारी किया गया है। राज्य वित्त आयोग के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को मिलने वाली धनराशि का उपयोग स्थानीय जरूरतों और संबंधित मदों के नियमों के अनुसार किया जाता है। इससे निकायों के विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद मिल सकती है।

सरकार की ओर से जारी जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 328.278 करोड़ में से किस नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत को कितनी राशि मिलेगी।

डीडीहाट में स्कूल तक बनेगा सीसी मार्ग



पिथौरागढ़ जिले की डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र की कुणिया ग्राम सभा में तपड़ी घाट से गोलमानू प्राथमिक विद्यालय तक सीसी मार्ग बनाया जाएगा। इस काम को मुख्यमंत्री घोषणा के तहत मंजूरी मिली है। निर्माण की कुल लागत 72.63 लाख निर्धारित की गई है। इसमें से 60% यानी 43.578 लाख की पहली किश्त स्वीकृत की गई है। शेष 29.052 लाख कुल स्वीकृत लागत का बाकी हिस्सा है; इसे जारी करने की समयसीमा संबंधित आदेश के बिना स्पष्ट नहीं है। इस मार्ग के बनने से संबंधित क्षेत्र में आवागमन की सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है। हालांकि, सड़क की लंबाई, निर्माण पूरा करने की समयसीमा और काम शुरू होने की तारीख की जानकारी जारी विवरण में नहीं दी गई है।

◆धामी ने अक्टूबर-दिसंबर की तीसरी किश्त जारी की

कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग में किया कन्या पूजन, कक्षा 9 की 1400 छात्राओं को बांटी गईं साइकिलें

कन्या पूजन तभी सार्थक, जब बेटियों को समान अवसर मिलें : रेखा गुप्ता

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शारदीय नवरात्र के अवसर पर शुक्रवार को शालीमार बाग स्थित सीएम श्री स्कूल में कन्या पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा 9 की लगभग 1,400 छात्राओं को साइकिलें वितरित की गईं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कन्या पूजन के अवसर पर कहा कि कन्या पूजन केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि बेटियों के प्रति सम्मान, समानता और उनके महत्व को स्वीकार करने का संदेश है। भारतीय संस्कृति में बेटियों को शक्ति, ज्ञान, करुणा और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। कन्या पूजन की वास्तविक भावना तभी सार्थक होती है, जब समाज बेटियों को सम्मान देने के साथ-साथ उन्हें शिक्षा, सुरक्षा, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने के समान अवसर भी प्रदान करे। उन्होंने कहा कि बेटियां परिवार का गौरव होने के साथ-साथ समाज और राष्ट्र के भविष्य की आधारशिला भी हैं। उनकी प्रतिभा को निखारने, उनके सपनों को साकार करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए परिवार, विद्यालय और समाज को मिलकर प्रयास करने चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज के कार्यक्रम के दौरान 1,400 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई है। यह पहल विशेष रूप से कक्षा 9 की छात्राओं को ध्यान में रखकर की गई है, क्योंकि यह उनकी शैक्षणिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि विद्या वाहिनी योजना के अंतर्गत अब तक दिल्ली में 28,000 साइकिलों का वितरण किया जा चुका है। सरकार का लक्ष्य कुल 1.50 लाख साइकिलें वितरित करने का है।



कोई बेटी शिक्षा से वंचित न रहे समाज निभाए जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने बेटियों की शिक्षा को निरंतर बनाए रखने में अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और उनकी नियमित स्कूल उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए। वहीं, शिक्षकों और विद्यालय प्रमुखों की जिम्मेदारी केवल शिक्षा प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्राओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और अच्छे संस्कार विकसित करना भी है। उन्होंने कहा कि बेटियों का सशक्तीकरण केवल सरकार या विद्यालयों की जिम्मेदारी नहीं है। परिवार और समाज के हर सदस्य को यह सुनिश्चित करने के लिए योगदान देना चाहिए कि कोई बेटी शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य छात्राओं के लिए स्कूल तक पहुंच को आसान बनाना, परिवहन संबंधी कठिनाइयों को कम करना और उन्हें अपनी शिक्षा निरंतर जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री ने कन्याओं का पूजन कर उनके उज्ज्वल भविष्य, सुख-समृद्धि और सफलता की कामना भी की।

राज्यपाल ने मीडिया से जनहित के मुद्दे उठाने का किया आह्वान

डिजिटल दौर में विश्वसनीयता और सामाजिक जिम्मेदारी निभाए मीडिया : राज्यपाल

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने मीडिया से युवाओं में बढ़ते नशे, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, साइबर अपराध, डिजिटल माध्यमों पर भ्रामक सामग्री और सामाजिक सद्भाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों को प्रमुखता से उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का दायित्व जनसमस्याओं को सामने लाना, प्रशासन को जवाबदेह बनाना और उन लोगों की आवाज बनना है, जिनकी बात अक्सर बड़े मंचों तक नहीं पहुंच पाती। स्वतंत्र पत्रकारिता लोकतंत्र की शक्ति है, जबकि जिम्मेदार पत्रकारिता उस शक्ति का विवेक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए दोनों का साथ रहना आवश्यक है।

राज्यपाल बुधवार को शिमला में एक निजी समाचार चैनल की ओर से आयोजित जैम्स ऑफ हिमाचल अवार्ड-2026 समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया।

कविंद्र गुप्ता ने कहा कि किसी भी मीडिया संस्थान की पहचान केवल उसके प्रसारण, पाठक संख्या या दर्शकों से नहीं होती, बल्कि इस बात से बनती है कि उसने समाज की कितनी आवाजों को स्थान दिया, कितनी समस्याओं को जिम्मेदारी के साथ उठाया और कितने सकारात्मक प्रयासों को लोगों तक पहुंचाया। मीडिया नागरिकों को



जैम्स ऑफ हिमाचल समारोह में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करते राज्यपाल कविंद्र गुप्ता

सूचित करने के साथ शासन और समाज के बीच संवाद का माध्यम बनता है। जनहित के मुद्दों को व्यापक मंच प्रदान करने के साथ यह सामाजिक चेतना को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सामाजिक माध्यमों ने समाचारों के प्रसार को अभूतपूर्व गति दी है। अब किसी घटना की जानकारी कुछ ही क्षणों में लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। इससे जनसंवाद के नए अवसर पैदा हुए हैं, लेकिन भ्रामक सूचनाओं, अपुष्ट खबरों, छेड़छाड़ किए गए वीडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार नकली सामग्री जैसी चुनौतियां भी बढ़ी हैं। ऐसी सामग्री लोगों के विश्वास और सामाजिक सद्भाव को प्रभावित कर सकती है। इसलिए वर्तमान समय में पत्रकारिता की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है।

राज्यपाल ने कहा कि समाचारों की प्रतिस्पर्धा में सबसे पहले पहुंचने से अधिक महत्वपूर्ण सही और प्रमाणित जानकारी पहुंचाना है। मीडिया को सनसनी के बजाय सत्य, नकारात्मकता के बीच समाधान और विभाजनकारी विमर्श के स्थान पर संवाद को बढ़ावा देना चाहिए। इसका अर्थ समस्याओं को छिपाना या आलोचना से बचना नहीं है, बल्कि तथ्यों, संतुलन और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए उन्हें सामने लाना है।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी सार्थक होगा, जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों। मीडिया सरकारी योजनाओं और जनकल्याणकारी पहलों की सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने के साथ उनके क्रियान्वयन से जुड़े सवालों को भी जिम्मेदारी से उठा सकता है। समारोह में राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया। राज्यपाल ने कहा कि मीडिया को समाज में हो रहे सकारात्मक बदलावों, जनकल्याणकारी पहलों और जरूरतमंद लोगों के संघर्षों को भी पर्याप्त स्थान देना चाहिए।

इससे समाज में जागरूकता बढ़ेगी और बेहतर कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में निष्पक्षता, संवेदनशीलता और तथ्यों की पुष्टि का विशेष महत्व है। किसी भी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित करने से पहले उसकी सत्यता सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि आम जनता का मीडिया पर विश्वास बना रहे। उन्होंने उम्मीद जताई कि मीडिया अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने, युवाओं को सकारात्मक दिशा देने और समाज में आपसी सहयोग तथा सद्भाव की भावना बढ़ाने में प्रभावी योगदान देता रहेगा।

टैक्सी परमिट बढ़ाने की मांग पूरी, जयराम ठाकुर ने केंद्र के समक्ष उठाया था मामला

टैक्सी परमिट की अवधि बढ़ने से पर्यटन कारोबार से जुड़े वाहन संचालकों को मिलेगी आर्थिक राहत

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में टैक्सी परमिट की अवधि 12 साल से बढ़ाकर 15 साल करने का वादा पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि 28 अगस्त को प्रदेश के टैक्सी ऑपरेटरों के अनशन को समाप्त करवाते समय उन्होंने यह आश्वासन दिया था। इसके बाद टैक्सी ऑपरेटरों की मांग को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया गया। अब इस मांग के पूरा होने से टैक्सी संचालकों को राहत मिलेगी।

जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने टैक्सी ऑपरेटरों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार के समक्ष उनका पक्ष रखा था। अपनी ओर से जो भी संभव था, उन्होंने वह प्रयास किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यदि पहले से ही ईमानदारी और गंभीरता के साथ इस मामले को उठाती, तो टैक्सी ऑपरेटरों को अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन और अनशन का रास्ता नहीं अपनाना पड़ता। सरकार के समय रहते प्रयास करने से इस समस्या का समाधान पहले भी हो सकता था।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन आधारित राज्य है और यहां पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में टैक्सी ऑपरेटरों की अहम भूमिका रहती है। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ ही टैक्सी संचालक हजारों परिवारों की आजीविका का साधन भी हैं। ऐसे में उनकी समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान प्रतिबंधों के कारण पर्यटन कारोबार पूरी तरह प्रभावित हो गया था। पर्यटकों की आवाजाही बंद होने से टैक्सियां नहीं चल पा रही थीं और परिवहन क्षेत्र को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उस समय उनकी सरकार ने टैक्सी ऑपरेटरों की परेशानियों को समझते हुए टैक्सियों, बसों और ट्रकों का दो



नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर

साल का कर माफ किया था।

जयराम ठाकुर ने कहा कि जिन वाहन संचालकों ने पहले ही कर जमा करवा दिया था, उन्हें उनका पैसा वापस भी किया गया था। उन्होंने कहा कि संकट के समय परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों को राहत देना जरूरी था और उनकी सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए थे।

उन्होंने टैक्सी परमिट की अवधि बढ़ाए जाने को ऑपरेटरों के लिए राहत देने वाला निर्णय बताते हुए कहा कि उनकी मांग को पूरा करवाने के लिए लगातार प्रयास किए गए। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे प्रदेश के टैक्सी संचालकों को अपना व्यवसाय चलाने में सुविधा मिलेगी और उन्हें अनावश्यक आर्थिक दबाव से राहत मिलेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि टैक्सी ऑपरेटरों की समस्याओं का स्थायी समाधान होना चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार से परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों की रक्षा के लिए गंभीरता से कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पर्यटन को मजबूत बनाने के लिए टैक्सी संचालकों को सुविधाएं देना जरूरी है, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिले।

हिमाचल में श्रमिक कल्याण योजनाओं पर खर्च 108 करोड़ पार, शिक्षा सहायता में सर्वाधिक लाभ

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने जनवरी 2023 से अब तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को 108 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता वितरित की है। बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने नई दिल्ली में भारत सरकार के संयुक्त सचिव आशुतोष एटी पेडणेकर से भेंट कर श्रमिकों के कल्याण, शिक्षा सहायता और अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की।

बैठक के दौरान संयुक्त सचिव ने बोर्ड की कार्यप्रणाली और ई-केवाईसी के माध्यम से पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें योजनाओं का लाभ पहुंचाने के प्रयासों की सराहना की। कंवर ने बताया कि बोर्ड में अब तक लगभग 4.77 लाख श्रमिक पंजीकृत किए जा चुके हैं, जबकि करीब एक लाख श्रमिकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने इस व्यवस्था को देशभर में लागू करने पर बल दिया, ताकि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंच सके। बैठक में लेबर चौक स्थापित करने के विषय पर भी चर्चा हुई।

कंवर ने बताया कि शिक्षा सहायता योजना के तहत अब तक 15,536 लाभार्थियों को सहायता दी गई है। इस मद में 46 करोड़ 38 लाख एक हजार 225 रुपये वितरित किए गए हैं। श्रमिकों को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए उचित मूल्य की दुकानों, डिजिटल लेबर चौक और सार्वजनिक स्थलों पर एलईडी डिस्प्ले के माध्यम से प्रचार-प्रसार की पहल की जा रही है। इसके साथ ही उपकर संग्रह से संबंधित कार्यों को भी गति दी जा रही है।

बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड की योजनाओं और कार्यप्रणाली की श्रीलंका तथा नेपाल से आए प्रतिनिधिमंडलों ने भी सराहना की है। इन प्रतिनिधिमंडलों ने अपने देशों में भी इसी तरह की कल्याणकारी योजनाएं लागू करने की संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि



ई-केवाईसी से पात्र श्रमिकों की पहचान, डिजिटल लेबर चौक और योजनाओं के प्रचार पर जोर

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में बोर्ड निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बोर्ड का प्रयास है कि पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और प्रभावी तरीके से मिलता रहे।

कुमारसैन में सुलझीं लूट की तीन वारदातें, सोने के आभूषण बरामद



भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कुमारसैन क्षेत्र में महिलाओं की आंखों में मिर्च पाउडर अथवा इसी प्रकार का पदार्थ डालकर सोने के आभूषण छीनने के तीन मामलों में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने तीनों वारदातों में छीने गए सोने के आभूषणों की शत-प्रतिशत बरामदगी सुनिश्चित की है। बरामद आभूषणों में सोने की बालियां और मंगलसूत्र शामिल हैं।

पुलिस थाना कुमारसैन के अंतर्गत ओडी, कण्डयाली और बारूबाग में महिलाओं से आभूषण छीनने की इन घटनाओं के संबंध में अलग-अलग अभियोग दर्ज किए गए थे। मामलों की जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय सूचना तंत्र की मदद से आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार, आरोपी जैल सिंह पुत्र कर्ण सिंह, निवासी जिला डोडा, जम्मू-कश्मीर को 6 अक्टूबर 2026 को नूरपुर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से की गई पूछताछ के आधार पर 10 अक्टूबर को जम्मू स्थित जैन मार्केट के पास एक पुराने मकान से तीनों वारदातों में छीने गए आभूषण बरामद किए गए।

पुलिस ने सभी मामलों में छीने गए आभूषण बरामद कर जांच में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और उसे जिला कारागार कैथू में दाखिल किया गया है।

फॉरेंसिक सेवाओं के 17 नवनियुक्त कर्मियों का प्रशिक्षण हुआ संपन्न

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। निदेशालय फॉरेंसिक सेवाएं, हिमाचल प्रदेश, जुन्गा में विभिन्न विशेषज्ञताओं के 17 नवनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आयोजित एक माह का प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता बढ़ाने के साथ उन्हें फॉरेंसिक विज्ञान की आधुनिक तकनीकों, कानूनी प्रावधानों और व्यावहारिक कार्यप्रणाली से परिचित करवाना था।

समापन समारोह में निदेशक फॉरेंसिक सेवाएं डॉ. मीनाक्षी महाजन ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली में वैज्ञानिक साक्ष्यों की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 176(3) का उल्लेख करते हुए बताया कि निर्धारित श्रेणी के अपराधों में घटनास्थल पर फॉरेंसिक विशेषज्ञों की उपस्थिति और वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करना अहम है। साक्ष्यों का उचित संग्रहण, संरक्षण और विश्लेषण निष्पक्ष जांच तथा प्रभावी न्यायिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है।



जुन्गा में फॉरेंसिक कर्मियों का प्रशिक्षण संपन्न होने पर सामूहिक चित्र।

प्रशिक्षण के दौरान अभियोजन निदेशक राजीव कटोच ने नए आपराधिक कानूनों, न्यायालयों में फॉरेंसिक रिपोर्टों की स्वीकार्यता और विशेषज्ञ गवाही से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दी। केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ की डॉ. सुखविंदर कौर ने विस्फोट एवं विस्फोटकों, जबकि डॉ. राजीव जैन ने निष्कर्षण तकनीकों पर व्याख्यान दिया। सेवानिवृत्त नियंत्रक अजय उपाध्याय ने सेवा नियमों और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की डॉ. सीमा कश्यप ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिनियम के प्रावधानों से अवगत करवाया।

राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जुन्गा तथा धर्मशाला और मंडी की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के विशेषज्ञों ने भी प्रशिक्षण दिया। इसमें डीएनए प्रोफाइलिंग, घटनास्थल निरीक्षण, साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्ष्य, फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स, आगजनी जांच, अंगुलि चिह्न विज्ञान, विवादित दस्तावेजों का परीक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रयोगशाला गुणवत्ता आश्वासन जैसे विषय शामिल रहे।

रोहड़ू में केबल चोरी का आरोपी हुआ गिरफ्तार, 15 बंडल बरामद

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला जिले के रोहड़ू में जल शक्ति विभाग के पंप हाउस से केबल चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई केबल के 15 बंडल बरामद किए हैं। इनमें 70 एमएम केबल के 12 और 16 एमएम केबल के तीन बंडल शामिल हैं। पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

शिमला के एसएसपी गौरव सिंह ने शुक्रवार को बताया कि यह मामला रोहड़ू के पौड़ीताल स्थित जल शक्ति विभाग के पंप हाउस से केबल चोरी होने से संबंधित है। इस संबंध में विभाग के उपमंडल अधिकारी (एसडीओ) की शिकायत पर 13 अक्टूबर को पुलिस थाना रोहड़ू में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 331(4) और 305 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

एसएसपी ने बताया कि चोरी की घटना की जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई की। जांच के बाद पुलिस ने कैलाश चंद निवासी गांव जबल, जिला शिमला को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी की गई केबल के सभी 15 बंडल बरामद किए गए हैं।



पुलिस के अनुसार, बरामद सामान में 70 एमएम केबल के 12 बंडल और 16 एमएम केबल के तीन बंडल शामिल हैं। इस कार्रवाई से चोरी हुए सामान की बरामदगी हुई है। पुलिस मामले में साक्ष्य जुटाने के साथ चोरी की परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी है।

जुब्बल में किसानों ने सीखी प्राकृतिक खेती की तकनीकें

प्रशिक्षण में किसानों को मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और फसलों को रोगों से बचाने के बताए उपाय

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) शिमला, रोहड़ू ने आत्मा शिमला के सहयोग से जुब्बल खंड के 125 किसानों के लिए प्राकृतिक खेती पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को रसायनमुक्त खेती की तकनीकों, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और फसलों में रोगों एवं कीटों की रोकथाम के प्रभावी उपायों से अवगत करवाना था। इस दौरान विशेषज्ञों ने प्राकृतिक खेती अपनाकर खेती की लागत कम करने, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया।

प्रशिक्षण के दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती के चार प्रमुख स्तंभों बीजामृत, जीवामृत, आच्छादन और वापसा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि इन तकनीकों के उचित इस्तेमाल से मिट्टी में जैविक कार्बन बढ़ाने,



प्राकृतिक खेती की नई तकनीकें सीखते किसान।

लाभकारी सूक्ष्मजीवों की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और मृदा उर्वरता में सुधार करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने किसानों को खेती में मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के महत्व से भी अवगत करवाया।

कार्यक्रम में मृदाजनित रोगों, विशेषकर जड़ सड़न और कॉलर रॉट के प्रबंधन पर भी चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि प्राकृतिक खेती में मृदा जैविकी को बेहतर बनाने, जीवामृत और बीजामृत के माध्यम से लाभकारी सूक्ष्मजीवों के उपयोग तथा खेतों और बगीचों में उचित जल निकासी एवं आच्छादन बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इन उपायों से रोगों के प्रकोप को नियंत्रित करने में सहायता मिल सकती है।

वैज्ञानिकों ने किसानों को विभिन्न अस्त्रों के प्रयोग से खेतों और बगीचों में फसलों को प्रभावित करने वाले रोगों एवं कीटों के प्रबंधन की प्राकृतिक खेती आधारित तकनीकों की जानकारी भी दी। उन्होंने किसानों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इन विधियों को अपनाने और फसलों की नियमित निगरानी करने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर आत्मा शिमला के परियोजना निदेशक ने किसानों को प्राकृतिक खेती से संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रसायनमुक्त खेती अपनाने से किसानों को खेती की लागत कम करने, पर्यावरण की रक्षा करने और बेहतर आय प्राप्त करने की दिशा में मदद मिल सकती है। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती की तकनीकों को समझकर उन्हें अपने खेतों और बगीचों में अपनाने का आह्वान किया।

क्योंथल कॉन्वेंट स्कूल में विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। क्योंथल कॉन्वेंट स्कूल, जुन्गा में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता एवं टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निर्धारित आयु वर्ग के विद्यार्थियों का टीकाकरण किया। साथ ही विद्यार्थियों को किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलावों, मानसिक स्वास्थ्य के महत्व तथा नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में हेल्थ एजुकेटर प्रवीण कुमार और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पूनम ने विद्यार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। उन्होंने बताया कि किशोरावस्था जीवन का महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें शारीरिक और मानसिक बदलाव स्वाभाविक होते हैं। ऐसे में इन बदलावों को समझना, संतुलित दिनचर्या अपनाना और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर आशा कार्यकर्ता पूनम और अंजू ने भी कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग दिया। कार्यक्रम में कक्षा छठी से दसवीं तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां प्राप्त कीं।

विद्यालय के प्रधानाचार्य एमके शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग की टीम का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को शैक्षणिक ज्ञान के साथ स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना भी जरूरी है। ऐसे जागरूकता कार्यक्रम बच्चों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाने, अच्छी आदतें विकसित करने और सुरक्षित भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नवोदय विद्यालय में प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा नौवीं और ग्यारहवीं की रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली पार्श्व प्रवेश चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 22 अक्टूबर, 2026 कर दी गई है। जवाहर नवोदय विद्यालय ठियोग के प्राचार्य रोशन लाल ने बताया कि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि सुधारने के लिए 23 से 25 अक्टूबर, 2026 तक का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने जिला शिमला के सभी उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा मुख्याध्यापकों से आग्रह किया कि वे इस सूचना को विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थी निर्धारित समय में आवेदन कर सकें।

टेंडर घोटाला आपदा राहत कार्यों की गुणवत्ता और टेंडर प्रक्रिया पर भाजपा ने उठाए गंभीर सवाल

आपदा राहत टेंडरों में गड़बड़ी के आरोप पर भाजपा ने मांगी जांच

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर आपदा राहत और पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त धनराशि के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कुमारसैन और थानेधार उपमंडलों में आपदा राहत राशि से जारी टेंडरों पर सवाल उठाते हुए विधायक कुलदीप राठौर और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग की है।

भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को आपदा से हुए नुकसान की भरपाई और पुनर्निर्माण के लिए पीडीएनए के तहत सहायता उपलब्ध करवाई थी। आरोप है कि लोक निर्माण विभाग के कुमारसैन और थानेधार उपमंडलों में वर्ष 2024-25 की आपदा राहत राशि से ऐसे कार्यों के टेंडर जारी किए जा रहे हैं, जहां उनकी वास्तविक आवश्यकता नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जिन सड़कों पर मलबा नहीं गिरा और जो यातायात के लिए खुली हैं, वहां भी मलबा हटाने के नाम पर टेंडर लगाए जा रहे हैं।



भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज

भाजपा प्रवक्ता ने किट्टी सड़क का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने चार दिन पहले स्वयं सड़क का निरीक्षण किया था। उनके अनुसार, सड़क पर कहीं मलबा नहीं था, इसके बावजूद मलबा हटाने के लिए नए टेंडर जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कटेड़ी सड़क का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि वहां टायरिंग और सफेद पट्टी की मार्किंग पहले ही हो चुकी है, लेकिन दोबारा मार्किंग के टेंडर लगाए जाने की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि इन मामलों से संबंधित वीडियो प्रमाण भी उनके पास उपलब्ध हैं।

भारद्वाज ने बड़ोगी से केड़ी तक लगभग डेढ़ से दो किलोमीटर लंबी सड़क का हवाला देते हुए कहा कि सड़क पूरी तरह खुली है और वहां आपदा से कोई उल्लेखनीय नुकसान नहीं हुआ है। इसके बावजूद मलबा हटाने के टेंडर जारी किए जाने पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि इस सड़क के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी गई है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ चुनिंदा ठेकेदारों और कांग्रेस से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया प्रभावित की जा रही है। भारद्वाज ने विधायक कुलदीप राठौर और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की।

भाजपा प्रवक्ता ने ओडी से बिथल तक हॉर्टिकल्चर सड़क के लगभग एक करोड़ रुपये के कार्य का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क चौड़ीकरण और कटिंग के दौरान मिट्टी डालने के लिए उचित डंपिंग स्थल की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे जंगल और बगीचों को नुकसान पहुंचा। उनके अनुसार, स्थानीय लोगों ने न्यायालय से स्थगन आदेश भी प्राप्त किया था। इसके बावजूद संबंधित कार्यों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

उन्होंने कुमारसैन क्षेत्र के बड़ागांव में प्रस्तावित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भवन निर्माण के लिए उपलब्ध राशि वापस मंगवाए जाने की जानकारी मिली है। उन्होंने सवाल किया कि जब जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े कार्य लंबित हैं, तो कथित तौर पर अनावश्यक कार्यों पर सरकारी धन क्यों खर्च किया जा रहा है। भारद्वाज ने मुख्यमंत्री से मांग की कि कुमारसैन और थानेधार में आपदा राहत राशि से जारी सभी टेंडरों, भुगतानों, माप पुस्तिकाओं और कार्यों का भौतिक सत्यापन करवाया जाए।

एचपीयू में सौर ऊर्जा की आधुनिक तकनीकों पर कार्यशाला आयोजित

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के सेंटर फॉर ग्रीन एनर्जी एंड नैनोटेक्नोलॉजी की ओर से शुक्रवार को अगली पीढ़ी की सौर ऊर्जा तकनीकों पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी तथा विद्युत अभियांत्रिकी के विद्यार्थियों को सौर ऊर्जा के आधुनिक उपयोगों, तकनीकी विकास और व्यावहारिक अनुप्रयोगों की जानकारी दी गई।

कार्यशाला में भवन एकीकृत फोटोवोल्टिक (बीआईपीवी) और रेल एवं सड़क एकीकृत फोटोवोल्टिक (आरआईपीवी) तकनीकों पर विशेष चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि इन तकनीकों के माध्यम से भवनों और परिवहन से जुड़े बुनियादी ढांचे को सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। इससे पारंपरिक ढांचे का बेहतर इस्तेमाल करने के साथ स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।

कार्यशाला का समन्वय डॉ. अंजलि शर्मा, डॉ. जेसमिन कौर और डॉ. मनीष ने किया। इस पहल को जर्मनी की संस्था डॉयचे गेसेलशाफ्ट फॉर इंटरनेशनेल जुसामेनारबाइट (जीआइजेड) का सहयोग मिला। इसके अलावा ग्रांट थॉर्नटन भारत एलएलपी, सीएसटीईपी, सीएसआइआर-एनआइआइएसटी और उद्योग जगत के साझेदारों ने भी सहयोग किया।

कार्यशाला में उद्योग विशेषज्ञ वरुण सिंह, विनीत भाटिया, निशांत वर्मा, नेहा टिपले, अक्षय भारद्वाज, परेश नाडिग और ऋषभ शर्मा ने विभिन्न तकनीकी सत्र आयोजित किए। इन सत्रों में पारदर्शी सौर सामग्री, भवनों और परिवहन ढांचे में फोटोवोल्टिक प्रणालियों के एकीकरण, सौर ऊर्जा प्रणालियों की रूपरेखा और ऊर्जा दक्षता जैसे विषयों पर जानकारी दी गई।

देहरादून में 20 अक्टूबर को जलेगा 181 फुट ऊंचा रावण



भारतेन्दु संवाददाता, देहरादून। देहरादून के परेड ग्राउंड में इस बार दशहरा पर्व पर 181 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन आकर्षण का केंद्र रहेगा। बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी की ओर से 20 अक्टूबर को 79वां दशहरा पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान लंका दहन, रावण दहन और आतिशबाजी के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। वहीं, 21 अक्टूबर को भरत मिलाप का आयोजन होगा। बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी के प्रधान संतोख सिंह नागपाल ने शुक्रवार को परेड ग्राउंड में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि दशहरा पर्व की शुरुआत 20 अक्टूबर को दोपहर एक बजे श्री गोपीनाथ मंदिर से निकलने वाली शोभायात्रा से होगी। यह शोभायात्रा कालिका माता भवन पहुंचेगी, जहां श्री कालिका मंदिर समिति और संगीत मंडली की ओर से स्वरूपों का स्वागत किया जाएगा। इसके बाद मोती बाजार, राजपुर रोड और ऐश्लेहॉल होते हुए शोभायात्रा शाम 4:30 बजे परेड ग्राउंड पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि परेड ग्राउंड में शाम 5:30 बजे लंका दहन और शाम 6:05 बजे 181 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। इसके बाद शाम 6:30 से 7:30 बजे तक आतिशबाजी होगी। कार्यक्रम के समापन पर शोभायात्रा दर्शनलाल चौक, घंटाघर और पलटन बाजार होते हुए कालिका मार्ग पहुंचेगी। दशहरे के अगले दिन 21 अक्टूबर को भरत मिलाप की शोभायात्रा निकाली जाएगी। यह दोपहर एक बजे श्री गोपीनाथ मंदिर परिसर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए परेड ग्राउंड पहुंचेगी।

सतपाल महाराज ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से की शिष्टाचार भेंट

अनिल थपलियाल

देहरादून। प्रदेश के लोक निर्माण, ग्रामीण निर्माण, सिंचाई, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज और उनकी धर्मपत्नी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत ने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को उनके स्वर्णिम कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड के राज्यपाल पद पर आसीन होने से लेकर अपने कार्यकाल के अंतिम चरण तक लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेश की विकास यात्रा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने राज्य की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए भी निरंतर प्रयास किए हैं।



108 संबोधनों से सजी 'आत्मा के स्वर'

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्यपाल ने विभिन्न अवसरों पर अपने संबोधनों के माध्यम से प्रदेश के विकास, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाया। उनके विचारों और अनुभवों को संरक्षित करने के उद्देश्य से 'आत्मा के स्वर' नामक पुस्तक प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में राज्यपाल के विभिन्न कार्यक्रमों, उत्सवों, दीक्षांत समारोहों और अन्य महत्त्वपूर्ण आयोजनों में दिए गए 108 प्रमुख संबोधनों को संकलित किया गया है।

संस्कृति और विकास में राज्यपाल का योगदान अहम

सतपाल महाराज ने कहा कि राज्यपाल ने अपने कार्यकाल के दौरान उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और विकास की संभावनाओं को व्यापक स्तर पर सामने रखने का प्रयास किया। उनके संबोधनों में प्रदेश की परंपराओं, सामाजिक मूल्यों और विकास से जुड़े विषयों को स्थान मिला है। उन्होंने राज्यपाल के योगदान की सराहना करते हुए उनके आगामी जीवन के लिए शुभकामनाएं व्यक्त कीं। इस शिष्टाचार भेंट के दौरान राज्य के विकास और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई।

मसूरी में एमडीडीए के नोटिस से मसूरी के पर्यटन कारोबार में हड़कंप

होमस्टे, होटल और गेस्ट हाउस संचालकों ने जताई नाराजगी

सुनील सोनकर

मसूरी। पहाड़ों की रानी मसूरी में आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद एमडीडीए की नोटिस कार्रवाई से पर्यटन कारोबारियों में बेचैनी बढ़ गई है। होमस्टे, होटल, गेस्ट हाउस और बीएनबी संचालकों को नोटिस मिलने से नाराज लोग प्राधिकरण कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और सरकार से हस्तक्षेप कर राहत दिलाने की मांग की। कारोबारियों का कहना है कि यदि व्यावसायिक गतिविधियां बंद करनी पड़ीं तो मसूरी के पर्यटन कारोबार और स्थानीय रोजगार पर व्यापक असर पड़ सकता है।

स्थानीय निवासी सुधांशु रावत और सभासद पवन थलवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत नियमों के विरुद्ध चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, मसूरी में मास्टर प्लान, अधिसूचित क्षेत्रों और भूमि उपयोग की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से कारोबारियों के सामने असमंजस बना हुआ है। उन्होंने मांग की कि मसूरी की भौगोलिक और नियोजन संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाए।



कारोबारियों ने कहा कि सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे योजना को प्रोत्साहित किया है। ऐसे में होमस्टे और अन्य पर्यटन इकाइयों को नोटिस मिलने से संचालक परेशान हैं। उनका कहना है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मसूरी की वास्तविक परिस्थितियों और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था का पक्ष रखना चाहिए।

पवन थलवाल ने दावा किया कि इस कार्रवाई से होटल, गेस्ट हाउस, होमस्टे और बीएनबी कारोबार से जुड़े करीब 95 प्रतिशत लोग प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, इस आंकड़े की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने पुराने निर्माणों को निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत नियमित करने के लिए अध्यादेश लाने तथा कानूनी रूप से संभव मामलों में निर्धारित शुल्क लेकर राहत देने की मांग की।

कारोबारियों ने बताया कि वे एसडीएम मसूरी को ज्ञापन सौंप चुके हैं। उन्होंने सरकार और एमडीडीए से नोटिस कार्रवाई पर पुनर्विचार कर समाधान निकालने की मांग की। फिलहाल, इस कार्रवाई से मसूरी के पर्यटन कारोबार और स्थानीय रोजगार को लेकर चिंता बढ़ गई है।

होमस्टे संचालकों ने सरकार से राहत मांगी

कारोबारियों ने कहा कि सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे योजना को प्रोत्साहित किया है। ऐसे में होमस्टे और अन्य पर्यटन इकाइयों को नोटिस मिलने से संचालक परेशान हैं। उनका कहना है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मसूरी की वास्तविक परिस्थितियों और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था का पक्ष रखना चाहिए। पवन थलवाल ने दावा किया कि इस कार्रवाई से होटल, गेस्ट हाउस, होमस्टे और बीएनबी कारोबार से जुड़े करीब 95 प्रतिशत लोग प्रभावित हो सकते हैं।

दिव्यांग युवाओं को मुफ्त सिविल सेवा कोचिंग देगी धामी सरकार

भारतेन्दु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड सरकार दिव्यांग युवाओं को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) की परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क सिविल सेवा कोचिंग उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शुरू की जा रही इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और प्रशासनिक सेवाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। इसके लिए देहरादून और हल्द्वानी में कोचिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों में आवासीय और गैर-आवासीय दोनों प्रकार की कोचिंग की सुविधा मिलेगी।



योजना के तहत दिव्यांग अभ्यर्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुलभ और अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा। केंद्रों में ब्रेल पुस्तकें, श्रव्य अध्ययन सामग्री, स्क्रीन रीडर के अनुकूल डिजिटल सामग्री, रैंप, लिफ्ट, सुगम शौचालय और व्हीलचेयर के अनुकूल बैठने की व्यवस्था होगी।

अभ्यर्थियों को पढ़ाई के साथ मिलेगा आवास और भोजन

आवासीय सुविधा लेने वाले अभ्यर्थियों को रहने और भोजन की सुविधा मिलेगी, जबकि गैर-आवासीय अभ्यर्थियों को परिवहन भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर प्रयोगशाला, डिजिटल अध्ययन संसाधन, अभ्यास परीक्षाओं और व्यक्तिगत परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कोचिंग में अनुभवी शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों के मार्गदर्शन में भारतीय राजव्यवस्था, इतिहास, अर्थव्यवस्था, भूगोल और समसामयिक विषयों की तैयारी कराई जाएगी। श्रवण बाधित अभ्यर्थियों के लिए सांकेतिक भाषा की सहायता भी उपलब्ध होगी। योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी का उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना और प्रमाणित दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत होना आवश्यक है। शैक्षिक योग्यता, पारिवारिक आय और चयन संबंधी अन्य शर्तें शासन के निर्धारित मानकों के अनुसार होंगी।

रेखा आर्या के आरोपों से उत्तराखंड की सियासत में भूचाल

महिला सुरक्षा और सत्ता की जवाबदेही पर उठे सवाल

रेखा आर्या के पति पर मारपीट और जान से मारने की धमकी के आरोप, एफआईआर दर्ज!

विकास बलूनी

देहरादून। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या द्वारा अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ प्रताड़ना, मारपीट और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। शिकायत के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 को उन्होंने पुलिस से कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की। वहीं, रोते हुए वीडियो साझा करने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने और अस्पताल में भर्ती कराए जाने की खबर ने इस मामले को और संवेदनशील बना दिया है।



रेखा आर्या अस्पताल में भर्ती।



पति गिरधारी लाल साहू।

शिकायत में रेखा आर्या ने वर्ष 2004 में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह होने का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि शादी के बाद उन्हें पति की कथित पहली शादी और बच्चों के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने अन्य महिलाओं से कथित संबंधों का विरोध करने पर विवाद बढ़ने, मारपीट और गाली-गलौज किए जाने के आरोप भी लगाए हैं।

मारपीट, जान से मारने की धमकी और कथित फर्जी दस्तावेजों के गंभीर आरोप

मामले में महिला और उनके नाबालिग बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई है। शिकायतकर्ता ने सरकारी आवास में जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल से अपमानित किए जाने का आरोप लगाया है। इसके अतिरिक्त, कंपनियों में निदेशक पद से हटाने के लिए कथित तौर पर फर्जी हस्ताक्षर और कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल किए जाने का दावा भी किया गया है। शिकायत में एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग का हवाला देते हुए जान का खतरा होने की आशंका जताई गई है।

महिला सुरक्षा पर सवाल, क्या निष्पक्ष जांच होगी? यह मामला केवल एक पारिवारिक विवाद तक सीमित नहीं है। एक वरिष्ठ महिला जनप्रतिनिधि द्वारा लगाए गए इन गंभीर आरोपों ने महिला सुरक्षा, कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र जांच और संबंधित साक्ष्यों का सत्यापन होना अभी आवश्यक है। आरोपों को न्यायिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता।

राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर कार्रवाई जरूरी: घटना के बाद प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की खबर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मामला भी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रह जाएगा, या कानून के अनुसार निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी?

पुलिस की जिम्मेदारी है कि शिकायत में लगाए गए प्रत्येक आरोप, उपलब्ध साक्ष्य, कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेजों की विधिसम्मत जांच करे। साथ ही, यदि सुरक्षा को लेकर वास्तविक खतरा है, तो नियमानुसार आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएं। संबंधित पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिलना चाहिए। रेखा आर्या के गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मामला राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित न रहे, बल्कि सच्चाई सामने आए, कानूनसम्मत कार्रवाई हो और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

क्या सरकार के भरोसे अंकिता के माता-पिता को मिलेगा न्याय, या इंतजार ही बनेगा उनकी नियति?

विनोद चमोली की परिवार से अपील— सरकार पर रखें भरोसा

विकास बलूनी

देहरादून। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर प्रदेश की राजनीति और न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अपनी बेटी को खो चुके माता-पिता आज भी न्याय की उम्मीद में संघर्ष कर रहे हैं। उनका दर्द केवल एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों की चिंता है, जो चाहते हैं कि इस मामले में हर सवाल का जवाब मिले और न्याय की प्रक्रिया पर जनता का भरोसा कायम रहे।



एआई निर्मित चित्र।

हाल ही में अंकिता के माता-पिता ने दिल्ली के इंडिया गेट पर धरना देकर न्याय की मांग उठाई। उनकी मांगों और कथित वीआईपी एंगल को लेकर राजनीतिक बहस तेज हुई। इसी बीच भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि अंकिता पूरे उत्तराखंड की बेटी है और उसके माता-पिता का कष्ट जायज है। उन्होंने परिवार से सरकार पर भरोसा रखने तथा सीबीआई जांच के नतीजे का इंतजार करने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि दोषियों को उम्रकैद दिलाने में सरकार के प्रयास रहे हैं। दूसरी ओर, कांग्रेस इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है। इन राजनीतिक दावों और प्रतिदावों के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल अंकिता के परिवार को न्याय मिलने का है।

अंकिता हत्याकांड में हर सवाल का जवाब जरूरी

भरोसा अपनी जगह, जवाबदेही अपनी जगह: विनोद चमोली की बात अपनी जगह है कि जांच पूरी होने तक उसके परिणाम का इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब एक परिवार अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो, तो क्या केवल भरोसा रखने की अपील पर्याप्त है?

लोकतंत्र में सरकार से भरोसे की अपेक्षा की जाती है, लेकिन यह भरोसा पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यायिक प्रक्रिया के प्रति सम्मान से मजबूत होता है। पीड़ित परिवार की मांगों को राजनीतिक बयानबाजी के चश्मे से देखने के बजाय उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुनना आवश्यक है। यदि जांच जारी है, तो जनता को उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जांच की स्थिति क्या है, किन कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है और परिवार की उठाई गई मांगों पर संबंधित एजेंसियों का क्या रुख है। जांच की गोपनीयता और न्यायिक प्रक्रिया की सीमाओं का सम्मान करते हुए भी सरकार संवाद और जवाबदेही सुनिश्चित कर सकती है।



विधायक, विनोद चमोली

वीआईपी एंगल पर उठे सवालों का क्या होगा? दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद इस मामले को लेकर राजनीतिक विवाद फिर चर्चा में आया है। विपक्ष इस नियुक्ति को अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी एंगल से जोड़कर सवाल उठा रहा है, जबकि भाजपा इन आरोपों को खारिज कर रही है। किसी भी आरोप को बिना प्रमाण तथ्य नहीं माना जा सकता। इसी तरह, किसी सवाल को केवल राजनीतिक विवाद बताकर नजरअंदाज करना भी उचित नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि संबंधित जांच एजेंसी तथ्यों और कानून के आधार पर अपना काम करे तथा जो जानकारी सार्वजनिक की जा सकती है, उसे स्पष्ट रूप से सामने रखा जाए। किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप और उसकी कानूनी जिम्मेदारी का निर्धारण सक्षम जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही होना चाहिए।

सवाल यह कि अंकिता के परिवार को न्याय के लिए आखिर कब तक इंतजार करना होगा?

अंकिता के माता-पिता को अब क्या चाहिए? अंकिता के परिवार को केवल सांत्वना नहीं, बल्कि उनकी मांगों पर गंभीर सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखने वाला स्पष्ट संवाद चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह परिवार की पीड़ा को समझे, उनकी वैध चिंताओं पर जवाब दे और कानून के दायरे में हर संभव सहयोग सुनिश्चित करे।

यह भी याद रखना होगा कि न्याय केवल दोषियों को सजा मिलने तक सीमित नहीं है। न्याय का अर्थ है कि मामले से जुड़े प्रत्येक प्रासंगिक सवाल की निष्पक्ष जांच हो, किसी निर्दोष को गलत तरीके से न फंसाया जाए और किसी दोषी को केवल प्रभाव या पद के कारण संरक्षण न मिले।

न्यूज ब्रीफ

थराली सीएचसी में अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने की मांग

भारतेन्दु संवाददाता, थराली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन, रेडियोलॉजिस्ट, स्त्री रोग और हड्डी रोग विशेषज्ञ की तैनाती की मांग की। साथ ही नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, आयुष्मान मित्र और वार्ड बॉय की नियुक्ति करने का अनुरोध किया। लोगों ने अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सप्ताह में कम से कम तीन दिन ओपीडी लगाने और अस्पताल परिसर में सोलर लाइट लगाने की मांग भी उठाई।

उत्तरकाशी में राज्यस्तरीय स्पीड क्लाइंबिंग प्रतियोगिता शुरू

भारतेन्दु संवाददाता, उत्तरकाशी। खेल महाकुंभ मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2026 के तहत शुक्रवार को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (निम) में राज्यस्तरीय स्पीड क्लाइंबिंग प्रतियोगिता शुरू हुई। भाजपा जिलाध्यक्ष नागेंद्र चौहान, जिलाधिकारी प्रशांत आर्य और निम के प्रधानाचार्य एसएस राजपुरोहित ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया। तीन दिवसीय प्रतियोगिता में अंडर-14 और अंडर-19 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं तथा 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं ने हिस्सा लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि स्पीड क्लाइंबिंग में एकाग्रता, मानसिक मजबूती और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता महत्वपूर्ण है। निम के प्रधानाचार्य ने कहा कि ओलंपिक स्तर के इस खेल में उत्तराखंड में बेहतर संभावनाएं हैं। प्रतियोगिता से उभरते खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।



सचिव रंजना राजगुरु ने आयुर्वेदिक अस्पताल का किया निरीक्षण

भारतेन्दु संवाददाता, उत्तरकाशी। सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा तथा राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव रंजना राजगुरु ने राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों की तैनाती, मरीजों की संख्या, बाह्य रोगी विभाग और पंचकर्म सेवाओं की जानकारी ली। साथ ही अस्पताल में साफ-सफाई बनाए रखने और मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाने, अभिलेखों के डिजिटलीकरण और ई-ऑफिस व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने प्रमाणपत्र निर्धारित समयसीमा में जारी करने, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों का निस्तारण करने और फर्जी दस्तावेजों के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

फसल उत्पादन के लिए सटीक उपज आकलन जरूरी : सीडीओ

भारतेन्दु संवाददाता, टिहरी। जनपद में फसलों की औसत उपज और कुल उत्पादन के सटीक आंकड़े जुटाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने नागणी क्षेत्र के जड़धार गांव में धान की क्रॉप कटिंग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं क्रॉप कटिंग कराकर प्राप्त उपज का जायजा लिया और किसान कुलदीप थापा से फसल की स्थिति की जानकारी ली। राजस्व विभाग ने खेत में दो प्लॉट तैयार किए थे, जिनसे क्रमशः 21 किलो 700 ग्राम और 18 किलो 800 ग्राम धान प्राप्त हुआ। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धान को सुखाने के 15 दिन बाद उपज का वास्तविक आकलन किया जाएगा। सीसीई एग्री ऐप के माध्यम से क्रॉप कटिंग की प्रक्रिया दर्ज की गई। सीडीओ ने संबंधित कार्मिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्रॉप कटिंग के आंकड़ों से फसल उत्पादन का आकलन करने के साथ फसल क्षति की स्थिति में मुआवजा और बीमा राशि निर्धारित की जाती है।

कैंची धाम में सप्ताहांत पर यातायात योजना लागू

कैंची धाम जाने वाले पर्यटकों को पार्किंग से मिलेगी शटल सेवा

भारतेन्दु संवाददाता, नैनीताल। कैंची धाम, भवाली और भीमताल क्षेत्र में सप्ताहांत पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए पुलिस ने 17 और 18 अक्टूबर के लिए विशेष यातायात एवं डायवर्जन योजना लागू की है। इसके तहत भारी वाहनों का सुबह तीन बजे से रात 11 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। केमू और निजी बसों सहित चौपहिया वाहनों के लिए सुबह पांच बजे से रात आठ बजे तक निर्धारित यातायात व्यवस्था लागू रहेगी।

योजना के अनुसार, अल्मोड़ा, जागेश्वर, बागेश्वर और पिथौरागढ़ से मैदानी क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहनों को लमगड़ा, धानाचूली, धारी, खुटानी बैंड और भीमताल के रास्ते भेजा जाएगा। रानीखेत से आने वाले वाहन क्वारब, ओड़ाखान, रामगढ़ और भीमताल होकर जाएंगे। वहीं, हल्द्वानी और काठगोदाम से पहाड़ी क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहनों के लिए भी वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं।

कैंची धाम में भीड़ से निपटने को पुलिस ने बनाई नई योजना

पुलिस के अनुसार, भीमताल के रास्ते कैंची धाम जाने वाले पर्यटकों को भीमताल विकास भवन पार्किंग में वाहन खड़े करने होंगे, जबकि गेठिया और नैनीताल की ओर से आने वाले पर्यटकों के वाहन भवाली सैनिटोरियम में पार्क होंगे। यहां से भवाली और कैंची धाम मंदिर तक पहुंचने के लिए शटल सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। सप्ताहांत के दौरान कैंची धाम क्षेत्र और नैनीताल में टैक्सी व दोपहिया वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा। पुलिस ने वाहन चालकों और पर्यटकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। गौरतलब है कि अक्टूबर के पहले लंबे सप्ताहांत में पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण यातायात प्रभावित हुआ था।

अंकिता भंडारी मामले में 24 अक्टूबर को सीबीआई कार्यालय घेरेगा यूकेडी

अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उक्रांद का आंदोलन तेज

अनिल थपलियाल

देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर 24 अक्टूबर को सीबीआई कार्यालय का घेराव और तालाबंदी करेगा। दल के कार्यकारी अध्यक्ष जय प्रकाश उपाध्याय ने बताया कि 17 अक्टूबर को भाजपा का पुतला दहन किया जाएगा। इसके बाद प्रदेशभर में दोषियों को कठोर सजा दिलाने और मामले से जुड़े कथित वीआईपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाना केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि प्रदेश की अस्मिता और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। दल ने निष्पक्ष जांच और पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग की।



उपाध्याय ने बताया कि उक्रांद आगामी विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों के साथ रोजगार, पलायन, मूल निवास, स्थायी राजधानी और जल-जंगल-जमीन जैसे मुद्दों पर भी जनसंवाद करेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक अनुशासन बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से जनता की आवाज उठाने का आह्वान किया।

न्यूज शॉर्ट्स

सीमा पार से हथियार तस्करी का भंडाफोड़ पांच गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। काउंटर इंटेलीजेंस अमृतसर ने सीमा पार से हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी करने वाले मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें पिता-पुत्र भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों से एक .30 बोर असॉल्ट राइफल, दो हैंड ग्रेनेड, 13 विदेशी पिस्तौलें और 25 कारतूस बरामद किए हैं। खेप की आवाजाही में इस्तेमाल दो मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुरप्रीत सिंह, उसके बेटे जसकरण सिंह, वीनू, अमृतपाल सिंह और गौरव मसीह के रूप में हुई है। खुफिया सूचना के मुताबिक, गुरप्रीत और जसकरण विदेश में बैठे एक तस्कर के संपर्क में थे।

जसवां में अवैध खनन पर छापा, टिपर पोकलेन जब्त

भारतेंदु संवाददाता, पठानकोट। पठानकोट जिले में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तारागढ़ पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने गांव जसवां में छापेमारी की। इस दौरान टीम ने बजरी से भरा एक टिपर और खुदाई में इस्तेमाल की जा रही पोकलेन मशीन जब्त की। पुलिस ने इस मामले में नवजोत सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, खनन विभाग के कनिष्ठ अभियंता अभिमन्यु कांडा को गांव जसवां क्षेत्र में कथित अवैध खनन किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद विभाग की टीम ने तारागढ़ पुलिस के सहयोग से मौके पर छापा मारा। जांच के दौरान वहां बजरी की खुदाई में इस्तेमाल की जा रही पोकलेन मशीन और बजरी से भरा टिपर मिला। संयुक्त टीम ने दोनों वाहनों और मशीन को कब्जे में ले लिया।

नशे पर शाह का मान सरकार से सवाल

झोटा हत्याकांड और दिड़बा घटना का हवाला देकर कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नशे का मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी की नशा मुक्ति यात्रा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सवालों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से प्रदेश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। अमित शाह ने इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर पंजाब में नशे के कारोबार, गैंगस्टरवाद और संगठित अपराध को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा। उन्होंने मानसा में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले परविंदर सिंह झोटा की हत्या और दिड़बा की घटना का उल्लेख करते हुए प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए। शाह ने कहा कि पंजाब की जनता को केवल घोषणाओं के बजाय ठोस कार्रवाई और सुरक्षा की जरूरत है।

अमित शाह ने अपनी पोस्ट में कहा कि पंजाब नशे, गैंगस्टरवाद और संगठित अपराध के बढ़ते खतरे का सामना कर रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से सवाल किया कि प्रदेश की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। शाह ने दिड़बा में एक पिता के कथित तौर पर दबाव में जहर खाने और मानसा में परविंदर सिंह झोटा की दिनदहाड़े हत्या का जिक्र करते हुए इन घटनाओं को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि इन मामलों ने कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। शाह के अनुसार, परविंदर सिंह के पिता ने आम आदमी पार्टी सरकार और



गृह मंत्री अमित शाह।

क्षेत्रीय विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय इन दोनों घटनाओं पर पंजाब सरकार से जवाब मांगेगा। हालांकि, इन आरोपों और घटनाओं के संबंध में संबंधित पक्षों का जवाब सामने आना जरूरी है। अमित शाह का यह बयान ऐसे समय आया है, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 15 अक्टूबर को इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुरक्षा का सवाल उठाया था। राहुल गांधी ने मानसा में परविंदर सिंह झोटा की हत्या का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान से पूछा था कि नशे के खिलाफ लड़ने वालों की हिफाजत कौन करेगा। उन्होंने संगरूर में मजदूर गुलजार सिंह की मौत और नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले मोहनजीत सिंह से जुड़े मामले का भी जिक्र किया था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि नशे के खिलाफ बोलने वालों को हिंसा और दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

भाजपा ने नशा मुक्ति यात्रा से बढ़ाया दबाव

पंजाब में नशे के मुद्दे पर भाजपा पहले से ही आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रही है। पार्टी ने हाल ही में प्रदेश में नशा मुक्ति यात्रा निकाली थी। इसके जरिए नशे के कारोबार पर रोक लगाने, युवाओं को नशे से बचाने और कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर दबाव बनाया गया। अब अमित शाह के बयान ने इस मुद्दे को और तूल दे दिया है। शाह ने नशे के नेटवर्क पर निर्णायक कार्रवाई, अपराधियों को कथित राजनीतिक संरक्षण मिलने के मामलों की निष्पक्ष जांच और युवाओं के भविष्य की रक्षा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर नशामुक्त, गैंगस्टरमुक्त और सुरक्षित पंजाब बनाने के लिए काम किया जाएगा। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले नशे का मुद्दा भाजपा और कांग्रेस, दोनों के लिए मान सरकार को घेरने का प्रमुख आधार बनता जा रहा है। एक ओर विपक्ष नशे के कारोबार और अपराध पर प्रभावी कार्रवाई की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। परविंदर सिंह झोटा की हत्या और दिड़बा की घटना का राजनीतिक बयानों में उल्लेख होने से विवाद और गहरा गया है। अब सबकी नजर पंजाब सरकार के जवाब और संबंधित मामलों में जांच की प्रगति पर रहेगी। आने वाले दिनों में नशे के खिलाफ कार्रवाई, अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था का मुद्दा प्रदेश की राजनीति में और प्रमुखता से उठ सकता है।

सुखना वेटलैंड बना भारत का 103वां रामसर स्थल, प्रकृति पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की सुखना झील के वेटलैंड क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी रामसर स्थल का दर्जा मिलने से शहर की प्राकृतिक विरासत को वैश्विक पहचान मिली है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है। इस उपलब्धि से प्रवासी पक्षियों और जैव विविधता के संरक्षण के साथ चंडीगढ़ में प्रकृति पर्यटन को बढ़ावा देने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं।

सुखना झील पहले से ही नौकायन, सुबह-शाम की सैर और प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। रामसर स्थल घोषित होने के बाद इसकी पहचान मनोरंजन स्थल के साथ महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास के रूप में भी मजबूत होगी। इससे पक्षी प्रेमियों, प्रकृति फोटोग्राफरों, पर्यावरण विशेषज्ञों और विद्यार्थियों की रुचि बढ़ने की उम्मीद है।

सुखना वेटलैंड मध्य एशियाई प्रवासी पक्षी मार्ग के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यहां सर्दियों में विभिन्न प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं। कामन पोचार्ड और पैलस फिश ईगल जैसी पक्षी प्रजातियों के अलावा ब्लैक पांड टर्टल जैसे जीव भी इस क्षेत्र की जैव विविधता का हिस्सा हैं। ऐसे में इस क्षेत्र का संरक्षण पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

रामसर स्थल का दर्जा मिलने के बाद प्रशासन के सामने वेटलैंड के संरक्षण और प्रबंधन की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। झील में गाद जमा होना, जलग्रहण क्षेत्र से मिट्टी का बहाव और आक्रामक वनस्पतियों का फैलाव प्रमुख चुनौतियां हैं। इसलिए पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देते समय जल गुणवत्ता, पक्षियों के प्राकृतिक आवास और जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभावों का ध्यान रखना होगा।

प्रशासन पक्षी दर्शन के लिए निर्धारित क्षेत्र, जानकारी केंद्र और प्रशिक्षित गाइड जैसी सुविधाएं विकसित कर सकता है। इसके साथ ही सुखना झील को रॉक गार्डन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स और शहर की अन्य प्राकृतिक विरासत के साथ जोड़कर पर्यावरण अनुकूल पर्यटन योजना तैयार की जा सकती है। इससे चंडीगढ़ की पर्यटन पहचान को मजबूती मिलने की संभावना है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बृहस्पतिवार को सुखना वेटलैंड को रामसर सूची में शामिल किए जाने की जानकारी दी। रामसर कन्वेंशन वर्ष 1971 में अपनाई गई एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, जिसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों के नुकसान को रोकना और उनके संरक्षण तथा विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। हालांकि, रामसर स्थल बनने से पर्यटकों की संख्या, पर्यटन आय या केंद्रीय वित्तीय सहायता में स्वत: वृद्धि की गारंटी नहीं मिलती।



सुखना झील की वैश्विक पहचान बढ़ने से पक्षी प्रेमियों का बढ़ेगा आकर्षण ।

◆रामसर दर्जे से प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को मिलेगी नई दिशा

हत्या के बाद बीमा लाभ नकारना एलआइसी को पड़ा महंगा, आयोग ने सुनाया फैसला

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। मोगा में एक कारोबारी की हत्या के बाद अतिरिक्त दुर्घटना बीमा लाभ देने से इन्कार करना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) को भारी पड़ गया। पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने निगम के फैसले को पलटते हुए कारोबारी के परिवार को चार बीमा पालिसियों के तहत 26.50 लाख रुपये का दोहरा दुर्घटना लाभ देने का आदेश दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी हत्या को सुनियोजित अपराध बताकर अपने आप अतिरिक्त दुर्घटना बीमा लाभ देने से इन्कार नहीं किया जा सकता। निगम को छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 50 हजार रुपये मुआवजा और मुकदमे का खर्च भी देना होगा। आयोग के न्यायिक सदस्य एचपीएस महल और सदस्य किरण सिब्बल की पीठ ने कारोबारी की पत्नी, नाबालिग बेटे और मां की अपील पर यह फैसला सुनाया। इससे पहले मोगा जिला उपभोक्ता आयोग ने 29 नवंबर 2022 को परिवार की शिकायत खारिज कर दी थी। राज्य आयोग ने 13 अक्टूबर को दिए फैसले में जिला आयोग का आदेश रद करते हुए एलआइसी की सेवा में कमी मानी। मोगा के कारोबारी तजिंदर सिंह कंबो की 14 जुलाई 2020 को उनकी दुकान पर अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। उनकी पत्नी रिपनदीप कौर कंबो चार बीमा पालिसियों में नामित थीं। इन पालिसियों के तहत पांच लाख, 10 लाख, 1.60 लाख और 10 लाख रुपये की बीमा राशि निर्धारित थी। कारोबारी की मृत्यु के बाद एलआइसी ने मूल बीमा राशि का भुगतान कर दिया, लेकिन अतिरिक्त दुर्घटना लाभ देने से इन्कार कर दिया। निगम ने 30 अप्रैल 2021 को जारी अस्वीकृति पत्र में हत्या को सुनियोजित बताते हुए इंटरनेट मीडिया पर कथित हमलावर की एक पोस्ट और पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट का हवाला दिया था।

तीन साल बाद चंडीगढ़ से शारजाह आबू धाबी की उड़ानें फिर होंगी शुरू

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ और आसपास के यात्रियों के लिए खाड़ी देशों की यात्रा आसान होने जा रही है। शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस शारजाह और आबू धाबी के लिए उड़ानें दोबारा शुरू करने की तैयारी में है। करीब तीन साल बाद इन सेवाओं की बहाली से यात्रियों को सीधी हवाई कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। दोनों उड़ानों को आगामी विंटर शेड्यूल में शामिल किया गया है। हालांकि, शारजाह की उड़ान का संचालन कुछ औपचारिकताएं पूरी होने पर निर्भर करेगा।

एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार, शारजाह रूट के लिए स्लॉट मिल चुका है और कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं। 26 अक्टूबर तक स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, उड़ान सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को दोपहर 1:50 बजे चंडीगढ़ से रवाना होकर स्थानीय समयानुसार



शाम 4:50 बजे शारजाह पहुंचेगी। वापसी में शाम 5:50 बजे उड़ान भरकर रात 11:05 बजे चंडीगढ़ पहुंचने का कार्यक्रम है। इस रूट पर टिकट का फ्लेक्सी किराया करीब 23,169 रुपये बताया गया है।

आबू धाबी की उड़ान चंडीगढ़ से सुबह 11:59 बजे रवाना होकर स्थानीय समयानुसार दोपहर तीन बजे पहुंचेगी। वापसी में उड़ान सुबह 4:30 बजे आबू धाबी से रवाना होकर सुबह 9:40 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी। इस मार्ग पर फ्लेक्सी किराया करीब 21,150 रुपये बताया गया है।

चंडीगढ़ में फिर दौड़ेगी डबल डेकर ओपन बस

खुले आसमान के नीचे शहर की खूबसूरती निहारेंगे पर्यटक, बढ़ेगा पर्यटन आकर्षण

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ घूमने आने वाले पर्यटकों और ट्राईसिटी के लोगों के लिए अच्छी खबर है। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर कराने वाली हॉप-ऑन हॉप-ऑफ डबल डेकर ओपन बस सेवा एक साल से अधिक समय बाद फिर शुरू होने जा रही है। चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन (सिटको) ने बस की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया है। सेवा बहाल होने के बाद पर्यटक खुले आसमान के नीचे बैठकर शहर की खूबसूरत सड़कों, हरियाली और प्रमुख पर्यटन स्थलों का नजारा देख सकेंगे। पहले इस बस में 75 रुपये किराया देकर शहर घूमने की सुविधा मिलती थी। बस खराब होने के कारण सेवा बंद कर दी गई थी और इसे सेक्टर-17 स्थित होटल शिवालिक व्यू की पार्किंग में खड़ा किया गया था।



हॉप-ऑन हॉप-ऑफ डबल डेकर ओपन बस सेवा फिर से शुरू होने जा रही।

डबल डेकर ओपन बस सेवा पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय रही है। खासकर युवाओं और परिवारों में इस बस से शहर घूमने का खासा आकर्षण था। इसके माध्यम से सुखना झील, रॉक गार्डन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-17 प्लाजा, रोज गार्डन, पंजाब विश्वविद्यालय और सेक्टर-10 स्थित सरकारी संग्रहालय एवं कला दीर्घा जैसे प्रमुख स्थलों तक पहुंचने की सुविधा मिलती थी। बस सेवा दोबारा शुरू होने से पर्यटकों को शहर की वास्तुकला, हरियाली और सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने का अवसर मिलेगा।

सिटको की ओर से बस को व्यक्तिगत यात्राओं के अलावा परिवारों और समूहों के लिए भी बुक करने की सुविधा दी जाती थी। पहले आधे दिन की बुकिंग के लिए 5,900 रुपये और पूरे दिन के लिए 11,800 रुपये का विकल्प उपलब्ध था। लोग विशेष अवसरों पर परिवार और दोस्तों के साथ इस बस में घूमने का आनंद लेते थे।

खैर कटाई मामले में एनजीटी ने याचिका का किया निस्तारण

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के रूपनगर में संरक्षित वन क्षेत्रों में खैर के 1,561 पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कार्रवाई रिपोर्ट पर संतोष जताते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया है। वन विभाग के अनुसार, काटे गए प्रत्येक पेड़ के बदले 10 पौधे लगाने के निर्देश पर कुल 15,610 पौधे लगाए गए हैं। विभाग ने इनमें 98 प्रतिशत पौधों के जीवित रहने का दावा किया है। नई दिल्ली स्थित एनजीटी की प्रधान पीठ ने प्रदीप शर्मा बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य मामले में यह आदेश दिया।

वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, फतेहपुर गांव में 772, बगवाली में 743 और भंगाला में 46 खैर के पेड़ों की अवैध कटाई सामने आई थी। मामले में 19 जनवरी 2026 को थाना सदर, रूपनगर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कार्रवाई के दौरान लकड़ी के 793 लट्ठे जब्त किए गए। पुलिस जांच अभी जारी है।

एनजीटी के निर्देश पर लगाए गए पौधों में खैर और शीशम के अलावा शहतूत, जामुन तथा आम की प्रजातियां भी शामिल हैं। वन विभाग ने पौधों के पांच वर्ष तक रखरखाव के लिए अनुमान स्वीकृत होने की जानकारी दी।



नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल।

◆वन संरक्षण के प्रयासों पर एनजीटी संतुष्ट, पांच साल तक पौधों की होगी देखरेख

हाईकोर्ट से मान को राहत, फ्रांस जाने की मिली अनुमति

◆सुरक्षा चिंताओं के बीच मान की फ्रांस यात्रा को हाईकोर्ट की हरी झंडी

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की प्रस्तावित फ्रांस यात्रा को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के बीच चल रहे विवाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री को बड़ी राहत दी है। अदालत ने भगवंत मान को फ्रांस जाने की अनुमति दे दी है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं जताईं, जबकि पंजाब सरकार ने केंद्र के रुख पर सवाल उठाते हुए इसे भेदभावपूर्ण बताया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यात्रा की अनुमति देने का फैसला किया। हालांकि, मामले में विस्तृत आदेश बाद में जारी किए जाने की बात कही गई। यह विवाद मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा के लिए आवश्यक राजनीतिक मंजूरी को लेकर पैदा हुआ था।



पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से दलील दी गई कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सुरक्षा को लेकर संभावित खतरे की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। केंद्र ने बताया कि उसे बृहस्पतिवार शाम ही पंजाब सरकार का एक पत्र मिला था। इस पत्र में मुख्यमंत्री को देश और विदेश में खालिस्तानी संगठनों से खतरा होने की आशंका जताई गई थी। पत्र में खालिस्तानी संगठन से जुड़े गुरपतवंत सिंह का नाम भी उल्लेखित किया गया था।

पंजाब सरकार ने दूसरे देशों की यात्राओं का दिया हवाला

पंजाब सरकार ने केंद्र की दलीलों का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पहले भी जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की यात्रा कर चुके हैं और उन यात्राओं के लिए मंजूरी दी गई थी। ऐसे में फ्रांस यात्रा के मामले में अलग रवैया अपनाना उचित नहीं है। राज्य सरकार ने यह भी दलील दी कि जब विदेशी प्रतिनिधि भारत आते हैं तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में केंद्र सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी तरह केंद्र फ्रांस के अधिकारियों से बातचीत कर मुख्यमंत्री की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करवा सकता है। पंजाब सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चुनिंदा आधार पर मंजूरी दे रही है और उसका रवैया भेदभावपूर्ण है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने भगवंत मान को फ्रांस जाने की अनुमति दे दी। अदालत के विस्तृत आदेश से मामले में फैसले के आधार और शर्तों को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

औपचारिक निमंत्रण नहीं मिलने का भी दिया तर्क

केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री की यात्रा पर आपत्ति जताते हुए यह भी कहा कि फ्रांस सरकार की ओर से भगवंत मान को कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है। ऐसे में उनकी यात्रा के दौरान फ्रांस सरकार की ओर से आवश्यक राजकीय शिष्टाचार और प्रोटोकॉल उपलब्ध कराने को लेकर सवाल खड़े होते हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा की जमानत याचिका खारिज

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले गुरुग्राम की अदालत भी 15 जून को उनकी जमानत याचिका ठुकरा चुकी थी। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद अरोड़ा ने हाईकोर्ट का रुख किया था। यहां भी याचिका खारिज होने से उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि, अदालत ने किन तथ्यों और कानूनी आधारों पर जमानत देने से इनकार किया है, इसकी विस्तृत जानकारी आदेश सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। मामले की शुरुआत हरियाणा के गुरुग्राम में 18 मार्च को दर्ज प्राथमिकी से हुई थी। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में जांच शुरू की। संजीव अरोड़ा का आरोप है कि इसी प्राथमिकी के आधार पर उनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है। जांच के सिलसिले में ईडी की कार्रवाई के बाद यह मामला लगातार कानूनी प्रक्रिया के अधीन है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़े इस मामले में अरोड़ा ने अदालत से जमानत देने की मांग की थी, लेकिन उन्हें अब तक राहत नहीं मिल सकी है। संजीव अरोड़ा नौ मई से ईडी की हिरासत में हैं। उन्होंने जमानत हासिल करने के लिए सबसे पहले गुरुग्राम की अदालत में याचिका दायर की थी। 15 जून को अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत के लिए गुहार लगाई।



अमृतसर से शारजाह तक फर्जी टिकटों का जाल, 16 यात्री जांच के घेरे में



◆विदेश यात्रा के नाम पर ठगी की आशंका हवाई अड्डे पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

भारतेंदु संवाददाता, अमृतसर। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फर्जी हवाई टिकटों के जरिए शारजाह जाने की कोशिश का मामला सामने आया है। अमृतसर से शारजाह जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान संख्या 6ई 1427 में सफर करने पहुंचे 16 यात्रियों के टिकटों की जांच के दौरान गड़बड़ी का संदेह हुआ। एयरलाइन के सिस्टम में न तो यात्रियों के नाम दिखाई दिए और न ही उनके पीएनआर (यात्री नाम रिकॉर्ड) का विवरण मिला। इसके बाद एयरलाइन प्रबंधन ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और सभी यात्रियों को पूछताछ के लिए राजा सांसी थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद यात्रियों को छोड़ दिया है। वहीं, उन्हें टिकट उपलब्ध कराने वाले एजेंट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।

एयरलाइन की सहायक प्रबंधक दीक्षा सादाना की ओर से राजा सांसी पुलिस थाने के प्रभारी को दी गई शिकायत के अनुसार, यात्री अमृतसर से शारजाह जाने वाली उड़ान में सवार होने के लिए चेक-इन कराने पहुंचे थे। नियमित जांच के दौरान उनके टिकटों में अनियमितता सामने आई। सिस्टम में टिकटों की बुकिंग का रिकॉर्ड नहीं मिलने के बाद एयरलाइन कर्मचारियों को संदेह हुआ। इसके बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत यात्रियों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। मामले में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि टिकट किस माध्यम से उपलब्ध कराए गए थे और बुकिंग में गड़बड़ी कैसे हुई।

एयरपोर्ट इंचार्ज कुलजीत के मुताबिक, पूछताछ के बाद सभी यात्रियों को छोड़ दिया गया है। टिकट उपलब्ध कराने वाले एजेंट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि टिकट कथित तौर पर कहां तैयार किए गए और क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह सक्रिय है। यात्रियों के दस्तावेजों और टिकट बुकिंग से संबंधित जानकारी की भी जांच की जा रही है। फिलहाल मामले में एजेंट की भूमिका और कथित धोखाधड़ी की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

पर्यटकों को नए समय के अनुसार बनानी होगी योजना, शाम पांच बजे तक पहुंचना जरूरी

मौसम के मिजाज ने बदला अटारी-वाघा परेड का समय

भारतेंदु संवाददाता, अमृतसर। मौसम में बदलाव के मद्देनजर अटारी-वाघा सीमा पर आयोजित होने वाली रिट्रीट सेरेमनी के समय में परिवर्तन किया गया है। शुक्रवार से समारोह शाम पांच बजे शुरू होगा और साढ़े पांच बजे तक चलेगा। इससे पहले यह परेड शाम साढ़े पांच बजे से छह बजे तक आयोजित की जाती थी। समय में किए गए इस बदलाव के बाद अब देश-विदेश से समारोह देखने के लिए पहुंचने वाले पर्यटकों को अपनी यात्रा की योजना नए समय के अनुसार बनानी होगी।

वाघा सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकारियों के अनुसार, मौसम में बदलाव को ध्यान में रखते हुए रिट्रीट सेरेमनी का समय निर्धारित किया गया है। पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे समारोह देखने के लिए शाम पांच बजे तक पहुंचने की योजना बनाएं, ताकि उन्हें प्रवेश और अन्य व्यवस्थाओं के लिए



अटारी-वाघा सीमा पर बीएसएफ की परेड

पर्याप्त समय मिल सके। निर्धारित समय के बाद पहुंचने वाले लोगों को समारोह देखने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

अटारी-वाघा सीमा पर प्रतिदिन आयोजित होने वाली रिट्रीट सेरेमनी देश के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में शामिल है। इसे देखने के लिए पंजाब सहित देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक अमृतसर पहुंचते हैं। विदेश से आने वाले पर्यटक भी इस समारोह में विशेष रुचि दिखाते हैं। समारोह के दौरान सीमा सुरक्षा बल के जवान पूरे जोश और अनुशासन के साथ परेड करते हैं। उनकी कदमताल, ऊर्जावान गतिविधियां और देशभक्ति से ओतप्रोत प्रदर्शन दर्शकों में उत्साह भर देते हैं।

समारोह का प्रमुख आकर्षण भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा द्वार बंद करने की पारंपरिक प्रक्रिया है। इस दौरान दर्शक देशभक्ति के नारों और उत्साहपूर्ण माहौल के बीच जवानों का प्रदर्शन देखते हैं। अटारी-वाघा सीमा पर होने वाला यह आयोजन भारत की सैन्य परंपरा, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है।

समय में बदलाव के चलते पर्यटकों के लिए जरूरी है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले समारोह के नवीनतम समय की जानकारी प्राप्त कर लें। इससे उन्हें समय पर पहुंचने और बिना किसी असुविधा के इस लोकप्रिय आयोजन का आनंद लेने में मदद मिलेगी।

न्यू अमृतसर में करोड़ों की जमीन की रजिस्ट्री में हेराफेरी, डीसी ने बैठाई जांच

भारतेंदु संवाददाता, अमृतसर । अमृतसर के रजिस्ट्री दफ्तर नंबर एक में न्यू अमृतसर क्षेत्र की करोड़ों रुपये कीमत की जमीन की रजिस्ट्री के दस्तावेजों से कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जिला उपायुक्त दलविंदरजीत सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ) नवकीरत सिंह रंधावा को जांच के आदेश दिए हैं। उन्हें खरीददार, विक्रेता, संबंधित सब-रजिस्ट्रार, महिला क्लर्क और रजिस्ट्री प्रक्रिया से जुड़े अन्य कर्मचारियों के बयान दर्ज कर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रजिस्ट्री के दस्तावेजों में खसरा नंबर 1256 मिन के स्थान पर 1255 मिन दर्ज कराए जाने का आरोप है। सब-रजिस्ट्रार-एक लखविंदर सिंह ने संबंधित रजिस्ट्री का इंतकाल रोकने के लिए हलका पटवारी को निर्देश दिए थे, ताकि कथित हेराफेरी के आधार पर जमीन का इंतकाल दर्ज न हो सके। इसके बाद पटवारी ने भी इंतकाल की प्रक्रिया रोक दी।

मामले में सब-रजिस्ट्रार और महिला क्लर्क दोनों ने खुद को निर्दोष बताया है। ऐसे में जांच का मुख्य बिंदु यह है कि दस्तावेजों में बदलाव किसने और किन परिस्थितियों में किया। मामले को लेकर संबंधित पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। जांच के जरिए रजिस्ट्री प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों की भूमिका स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है।

डीसी कार्यालय कर्मचारी यूनियन ने भी अपने स्तर पर मामले की पड़ताल शुरू की है। यूनियन की सब-रजिस्ट्रार और अन्य संबंधित कर्मचारियों के साथ बैठक हुई।

जम्मू संभाग में अवैध खनन मामले में एसीबी की तीन जिलों में छापेमारी

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। अवैध खनन से जुड़े मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने शुक्रवार तड़के जम्मू संभाग के तीन जिलों में बड़ी कार्रवाई की। ब्यूरो की अलग-अलग टीमों ने जम्मू, रियासी और उधमपुर में खनन विभाग के अधिकारियों तथा ठेकेदारों से जुड़े ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान संबंधित परिसरों में दस्तावेजों, लेन-देन के अभिलेखों और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री की जांच की गई। कार्रवाई का उद्देश्य अवैध खनन के नेटवर्क और इसमें अधिकारियों की कथित भूमिका से जुड़े साक्ष्य जुटाना है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, एसीबी की टीमों ने रियासी में दो, उधमपुर में दो और जम्मू में एक स्थान पर तलाशी अभियान चलाया। जम्मू में टीम ने खनन विभाग के जिला खनिज अधिकारी (डीएमओ) रामेश्वर सांगड़ा के दबलैहड़, आरएसपुरा स्थित आवास पर तलाशी ली। सांगड़ा पहले रियासी जिले में तैनात रह चुके हैं और वर्तमान में जम्मू के बाहू प्लाजा स्थित खनन विभाग के कार्यालय में कार्यरत हैं। वहीं, उधमपुर में हाउसिंग कॉलोनी और जखैनी के माला क्षेत्र में भी एसीबी की टीमों ने संबंधित परिसरों की तलाशी ली। इनमें से एक ठिकाना खनन कार्य से जुड़े ठेकेदार का बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, संबंधित ठेकेदार की खनन विभाग के कुछ अधिकारियों से कथित नजदीकी होने की जानकारी भी जांच के दायरे में है। हालांकि, इस संबंध में एसीबी की ओर से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सुरक्षा के बीच दस्तावेजों की जांच छापेमारी के दौरान एसीबी की टीमों के साथ पुलिस के जवान भी तैनात रहे। सुरक्षा के मद्देनजर संबंधित परिसरों को घेर लिया गया और तलाशी के दौरान आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया। जांच दल दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल कर रहे हैं, ताकि अवैध खनन से संबंधित गतिविधियों और संभावित अनियमितताओं का पता लगाया जा सके। फिलहाल, कार्रवाई से जुड़े विस्तृत तथ्यों और बरामद सामग्री के बारे में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। एसीबी की जांच पूरी होने के बाद ही मामले में संबंधित व्यक्तियों की भूमिका और आगे की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

खनन अधिकारियों और ठेकेदारों के ठिकानों से साक्ष्य जुटाने में जुटी जांच टीमें

दिव्यांग श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी यात्रा में मिलीं निशुल्क सुविधाएं

नवरात्र में देशभर से पहुंचे दिव्यांग श्रद्धालुओं ने विशेष सुविधाओं के बीच किए मां के दर्शन

भारतेंदु संवाददाता, कटड़ा



मां वैष्णो के दर्शन और सुविधाओं से खिले दिव्यांग श्रद्धालुओं के चेहरे।

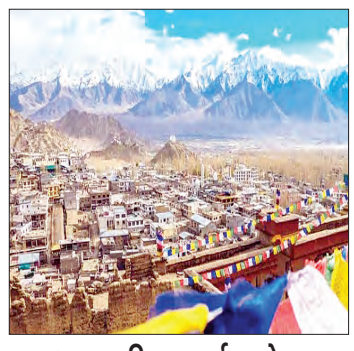
शारदीय नवरात्र के दौरान देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आधार शिविर कटड़ा पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। विशेष रूप से दिव्यांग श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए निशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इसी कड़ी में नवरात्र महोत्सव में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से कटड़ा पहुंचे करीब 200 दिव्यांग श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई। श्राइन बोर्ड की ओर से यात्रा के दौरान उन्हें कई विशेष सुविधाएं प्रदान की गईं। इन व्यवस्थाओं से दिव्यांग श्रद्धालुओं को कठिन चढ़ाई वाले मार्ग पर यात्रा करने और मां के दर्शन करने में काफी सहूलियत मिली। घोड़े से बैटरी कार तक निशुल्क सुविधा श्राइन बोर्ड ने दिव्यांग श्रद्धालुओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधार शिविर कटड़ा से यात्रा मार्ग पर निशुल्क घोड़ों की व्यवस्था की। वहीं, अर्धकुंवारी से भवन तक पहुंचने के लिए निशुल्क बैटरी कार सेवा उपलब्ध कराई गई। भवन पर मां वैष्णो देवी के विशेष दर्शन और निशुल्क भोजन की सुविधा भी दी गई। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को सम्मानपूर्वक वापस आधार शिविर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई।

इन सुविधाओं के कारण दिव्यांग श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान होने वाली परेशानियों से राहत मिली। उन्होंने श्राइन बोर्ड की व्यवस्थाओं पर प्रसन्नता जताते हुए मां के जयकारे लगाए।

मां के दर्शन के बाद श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्हें इतनी सुविधाओं के साथ यात्रा करने का अवसर मिलेगा, इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने इस अनुभव को सुखद बताते हुए कहा कि मां के दर्शन और बोर्ड की ओर से मिली सहायता को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। श्रद्धालुओं ने निशुल्क सुविधाओं के लिए श्राइन बोर्ड का आभार जताया।

लद्दाख में पांच नई तहसीलों को मंजूरी, दूरदराज इलाकों तक पहुंचेगी प्रशासनिक सुविधा



भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। लद्दाख में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और दूर-दराज के क्षेत्रों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए पांच नई तहसीलों के गठन को मंजूरी दी गई है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि नई तहसीलों के गठन से स्थानीय लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं अपने नजदीक उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही लद्दाख में कुल तहसीलों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। नई तहसीलों में श्याम जिले की आर्यन वैली, कारगिल जिले की सोध, जंस्कार की फे, द्रास की थासगम और चांगथांग जिले की हिमया शामिल हैं। उपराज्यपाल ने बताया कि इस वर्ष जुलाई में 17 नई तहसीलों के गठन के बाद अब पांच और तहसीलों को मंजूरी दी गई है। इस कदम से प्रशासनिक ढांचे का विस्तार होगा और स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने में सहूलियत मिलेगी। प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए दुर्बुक के अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) की शक्तियां वहां के उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को सौंप दी गई हैं। इससे स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया आसान होने और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। लोगों को छोटे-छोटे प्रशासनिक कार्यों के लिए दूसरे कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी राहत मिल सकती है। लद्दाख का भौगोलिक क्षेत्र दुर्गम होने के कारण कई इलाकों में सरकारी सेवाओं तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण रहता है। नई तहसीलों के गठन से राजस्व संबंधी कार्यों, प्रमाणपत्रों और अन्य प्रशासनिक सेवाओं को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और लोगों की शिकायतों के निपटारे में भी तेजी आने की संभावना है। उपराज्यपाल ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी और विकसित लद्दाख के लक्ष्य के अनुरूप है। इससे स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने और प्रशासन को आम जनता के करीब लाने में सहायता मिलेगी।

प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत दुर्बुक के एसडीएम को अतिरिक्त शक्तियां, सांकू को जिला बनाने की घोषणा

किश्तवाड़ में घर के पास मिला लापता एसपीओ का शव, राइफल बरामद

भारतेंदु संवाददाता, किश्तवाड़



जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में लापता हुए स्पेशल पुलिस ऑफिसर (एसपीओ) बशीर अहमद का शव शुक्रवार सुबह उनके घर के पास मिला। घटनास्थल से उनकी सर्विस राइफल एसएलआर और एक मैगजीन भी बरामद की गई है। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल उनकी मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

जानकारी के अनुसार, 55 वर्षीय बशीर अहमद वीरवार रात अपनी सर्विस राइफल और एक मैगजीन के साथ लापता हो गए थे। वह वर्ष 2025 से पेदिल पुलिस पोस्ट पर तैनात थे। उनके लापता होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने उनकी तलाश के लिए व्यापक अभियान शुरू किया था।

अधिकारियों के मुताबिक, बशीर अहमद सुबह करीब सात बजे अपनी ड्यूटी पोस्ट से घर जाने के लिए निकले थे। लेकिन काफी समय बीतने के बावजूद जब वह घर नहीं पहुंचे तो परिवार के सदस्य चिंतित हो गए। उनकी पत्नी ने बताया कि निर्धारित समय पर पति के घर नहीं लौटने पर वह घबरा गईं और जानकारी लेने के लिए पुलिस पोस्ट पहुंचीं। वहां उन्होंने बशीर अहमद के लापता होने की सूचना दी।

इसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया। शुक्रवार सुबह उनका शव घर के पास बरामद हुआ। उनकी सर्विस राइफल भी मिल गई है। पुलिस अब उनकी मौत से जुड़े परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि मामले में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।

पुंछ में आतंकियों की तलाश तेज, चार इलाकों में घेराबंदी

कृष्णा घाटी विस्फोट और आतंकी ठिकाने के खुलासे के बाद बढ़ाई सतर्कता

भारतेंदु संवाददाता, पुंछ



जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती पुंछ जिले में आतंकवादियों की संभावित गतिविधियों पर अंकुश लगाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सुरक्षाबलों और पुलिस ने शुक्रवार को चार अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों के अनुसार, इन अभियानों के तहत संवेदनशील क्षेत्रों, गांवों और जंगलों में तलाशी ली गई। यह कार्रवाई नियंत्रण रेखा (एलओसी) के आसपास हाल में हुई घटनाओं और आतंकवादी ठिकाने का पर्दाफाश होने के बाद की गई है।

अधिकारियों ने बताया कि मेंढर उपमंडल के गुरसाई क्षेत्र में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) ने गुरसाई-हरूनी-बैधर इलाके में तलाशी अभियान चलाया। इसके अलावा एसओजी मेंढर और सेना की राष्ट्रीय राइफल्स ने संयुक्त रूप से धरना गांव, कश्मीर मोहल्ला, बेहरी के जंगलों और आसपास के क्षेत्रों में तलाशी ली। वहीं, एसओजी मनकोट ने मनकोट पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मंगलानू-चिल्ला के वन क्षेत्रों में भी अभियान शुरू किया।

सीमावर्ती गांवों और जंगलों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बढ़ाई चौकसी

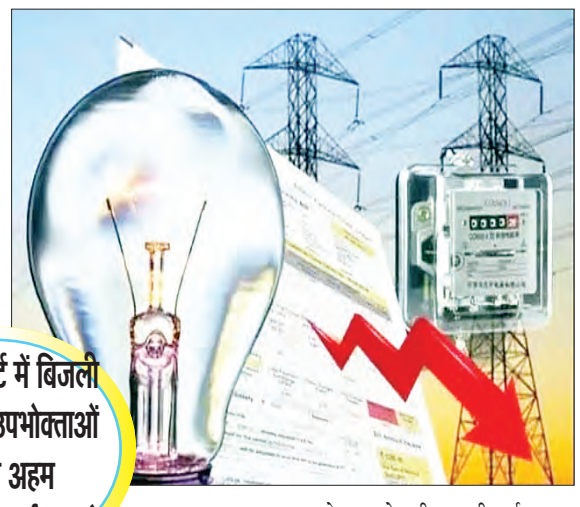
इन अभियानों का उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाना, आतंकवादियों की संभावित आवाजाही पर नजर रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। सुरक्षाबल सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार निगरानी बनाए हुए हैं।

यह तलाशी अभियान ऐसे समय में चलाया गया है, जब हाल ही में पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर के पास नियंत्रण रेखा के पार एक संदिग्ध विस्फोट में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के चार संदिग्ध आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना सामने आई थी। अधिकारियों के अनुसार, विस्फोट में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) के इस्तेमाल की आशंका जताई गई थी।

इससे पहले मंगलवार को सथरबन के जंगलों में सुरक्षाबलों ने एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भी पर्दाफाश किया था। तलाशी के दौरान वहां से एक स्वचालित राइफल, छह हथगोले और गोला-बारूद बरामद किया गया था। इस बरामदगी के बाद आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता और बढ़ा दी गई है।

बिजली बिल वसूली में पिछड़ा जम्मू-कश्मीर 417 करोड़ रुपए की अटकी राशि

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर



जम्मू-कश्मीर में बिजली की खपत और बिलों की वसूली बिजली विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में प्रदेश में 2983.03 करोड़ रुपये के बिजली बिल जारी किए गए, जबकि 2565.93 करोड़ रुपये की ही वसूली हो सकी। इस तरह बिलिंग और वसूली के बीच 417.10 करोड़ रुपये का अंतर रहा। जम्मू-कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड (जेकेपीडीसीएल) की वार्षिक ऊर्जा ऑडिट रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है।

रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के कुल 12,94,733 बिजली कनेक्शन दर्ज किए गए। इनसे कुल 7,024.58 मिलियन यूनिट बिजली की खपत हुई, जबकि कुल कनेक्टेड लोड 3,538.31 मेगावाट रहा। घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक रही। उनके 10,66,717 कनेक्शन थे, जो कुल कनेक्शनों का 82.39 प्रतिशत हैं। घरेलू उपभोक्ताओं ने 5,025.91 मिलियन यूनिट बिजली इस्तेमाल की, जो कुल खपत का 71.5 प्रतिशत है। इस श्रेणी से 1663.53 करोड़ रुपये की बिलिंग हुई, जबकि 1455.90 करोड़ रुपये ही वसूले जा सके।

कम वोल्टेज वाली वाणिज्यिक एवं औद्योगिक श्रेणी में 2,11,882 कनेक्शन दर्ज किए गए। इन उपभोक्ताओं ने 759.40 मिलियन यूनिट बिजली इस्तेमाल की, जो कुल खपत का 10.8 प्रतिशत है। इस श्रेणी में 450.49 करोड़ रुपये के बिल जारी हुए और 374.02 करोड़ रुपये की वसूली हुई। उच्च वोल्टेज वाली वाणिज्यिक एवं औद्योगिक श्रेणी के 550 कनेक्शन थे। इनकी खपत 460.19 मिलियन यूनिट रही। यहां 246.95 करोड़ रुपये की बिलिंग के मुकाबले 239.97 करोड़ रुपये वसूले गए। कृषि क्षेत्र में 4,338 कनेक्शन थे और बिजली की खपत 108.75 मिलियन यूनिट रही। इस क्षेत्र में 67.71 करोड़ रुपये के बिल जारी किए गए, लेकिन केवल 19.76 करोड़ रुपये की वसूली हुई।

वार्षिक रिपोर्ट में बिजली खपत और उपभोक्ताओं से जुड़ी अहम जानकारियां आईं सामने

श्रीनगर में रिश्वत लेते नगर निगम का वार्ड अधिकारी गिरफ्तार



भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) के सफाकदल वार्ड अधिकारी को 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अधिकारी ने शिकायतकर्ता से उसके आवास पर चल रहे मरम्मत कार्य को जारी रखने की अनुमति देने के बदले रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और अधिकारी को कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। सीबीआई के अनुसार, वार्ड अधिकारी के खिलाफ 15 अक्टूबर को रिश्वतखोरी का मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसके घर में छोटे स्तर पर जीर्णोद्धार का काम चल रहा था। इस काम को जारी रखने की अनुमति देने के बदले अधिकारी ने उससे 10 हजार रुपये की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामले की प्रारंभिक जांच की और आरोपों की पुष्टि के लिए कार्रवाई की योजना बनाई। इसके बाद सीबीआई की टीम ने 15 अक्टूबर को जाल बिछाया। इस दौरान वार्ड अधिकारी को शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए कथित तौर पर रंगे हाथों पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के बाद मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जांच की जा रही है।

चीन के दावों पर लद्दाख का पलटवार, अक्साई चिन पर भारत का अधिकार दोहराया



भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। चीन के लद्दाख संबंधी दावों पर अब स्थानीय नेताओं ने भी कड़ा विरोध जताया है। लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) के सह-अध्यक्ष और लद्दाख बौद्ध संघ के प्रमुख शेरिंग दोरजे लाक्रूक ने चीन के बयान की निंदा करते हुए अक्साई चिन को भारत का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि इतिहास में कभी भी लद्दाख चीन का हिस्सा नहीं रहा है और चीन को अपने बयानों में सावधानी बरतनी चाहिए। लाक्रूक ने कहा कि लद्दाख के लोग भारत के साथ खुशी-खुशी रह रहे हैं। वे पश्चिमी लद्दाख पर चीन के दावों को खारिज करते हैं और अपनी जमीन का एक इंच भी नहीं छोड़ेंगे। इसमें अक्साई चिन भी शामिल है। उन्होंने भारत सरकार से चीन के बयान की कड़े शब्दों में निंदा करने की अपील भी की।

चीन लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता नहीं देता है। इसके अलावा, वह भारत के साथ क्षेत्रीय नामकरण को लेकर भी विवाद करता रहा है। हाल ही में चीन ने भारत द्वारा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने और पूर्वी लद्दाख के 28 स्थानों के नामकरण पर आपत्ति जताई थी। चीन के इन दावों के बाद भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि लद्दाख देश का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। लद्दाख के सांसद हनीफा जान ने भी चीन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत की मजबूत सीमा सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लद्दाख और जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं और देश को अपने लोकतंत्र पर गर्व है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी चीन के दावों को खारिज करते हुए कहा था कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा। चीन के किसी भी तरह के इनकार से यह वास्तविकता नहीं बदल सकती। स्थानीय नेताओं की प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है कि लद्दाख के क्षेत्रीय मुद्दे पर भारत की संप्रभुता को लेकर उनका रुख स्पष्ट है। लद्दाख के नेताओं ने चीन के दावों को खारिज करते हुए अक्साई चिन पर भारत का अधिकार दोहराया। सांसद हनीफा जान ने भी मजबूत सीमा सुरक्षा पर जोर दिया।

लद्दाख के नेताओं ने चीन की आपत्तियों को खारिज कर भारत के पक्ष में आवाज उठाई

महिला अधिकारी के अपमान पर जेकेएएस एसोसिएशन की हड़ताल का ऐलान

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (जेकेएएस) एसोसिएशन की अंतरिम समिति ने एक महिला जेकेएएस अधिकारी के कथित अपमान के विरोध में एक दिवसीय पेन-डाउन हड़ताल का आह्वान किया है। यह घटना 14 अक्टूबर को एक आधिकारिक बैठक के दौरान हुई थी, जिसमें एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर महिला जेकेएएस अधिकारी को अपमानित करने का आरोप लगाया गया है। एसोसिएशन ने इस घटना को प्रशासनिक सेवा की गरिमा, आत्मसम्मान और संस्थागत प्रतिष्ठा से जुड़ा गंभीर मामला बताया है।

एसोसिएशन की अंतरिम समिति, जिसे एजेजेएसकेए के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने सदस्यों को भेजे गए पत्र में विरोध की जानकारी दी। पत्र में कहा गया है कि यह कदम किसी एक अधिकारी तक सीमित मामला नहीं है, बल्कि पूरी प्रशासनिक सेवा की गरिमा और सम्मान की रक्षा से जुड़ा है। समिति ने सदस्यों से इस मुद्दे पर एकजुट रहने और संबंधित महिला अधिकारी के प्रति समर्थन व्यक्त करने की अपील की है।

एसोसिएशन के अनुसार, प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी के सम्मान और आत्मसम्मान की रक्षा जरूरी है। किसी अधिकारी के साथ कथित तौर पर अपमानजनक व्यवहार होने से पूरी सेवा बिरादरी की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। ऐसे मामलों में संस्थागत मर्यादा बनाए रखना और अधिकारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना आवश्यक है।

समिति ने अपने सदस्यों से प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आग्रह किया है। एसोसिएशन का कहना है कि एकजुटता प्रदर्शित करने का उद्देश्य संबंधित अधिकारी के साथ खड़े होना और प्रशासनिक सेवा की गरिमा को बनाए रखने की मांग उठाना है। पेन-डाउन हड़ताल के माध्यम से अधिकारी अपने विरोध को दर्ज कराएंगे। इस घटनाक्रम ने जम्मू-कश्मीर के प्रशासनिक हलकों में अधिकारियों के बीच आपसी सम्मान, कार्यस्थल पर गरिमापूर्ण व्यवहार और संस्थागत मर्यादा को लेकर चर्चा तेज कर दी है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में प्रस्तावित हड़ताल की निश्चित तारीख, इसके दायरे और प्रशासन की प्रतिक्रिया का उल्लेख नहीं है। कथित घटना को लेकर संबंधित वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का पक्ष भी सामने नहीं आया है। फिलहाल एसोसिएशन की ओर से उठाए गए कदम को महिला अधिकारी के सम्मान और प्रशासनिक सेवा की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है।

14 अक्टूबर की बैठक में महिला अधिकारी से कथित दुर्व्यवहार पर प्रशासनिक हलकों में नाराजगी

कश्मीर घाटी में आज से 31 अक्तूबर तक दो रेलगाड़ियां रद्द



भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। कश्मीर घाटी में सर्दियों के दौरान रेल परिचालन को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने के लिए रेलवे ने प्री-विंटर डिस्ट्रेसिंग कार्य करवाने का निर्णय लिया है। इस कार्य के चलते बनिहाल और बारामूला के बीच चलने वाली दो रेलगाड़ियों को 15 दिनों के लिए निरस्त कर दिया गया है। रेलवे के इस फैसले के अनुसार, आज से 31 अक्टूबर तक यात्रियों को इन रेलगाड़ियों की सुविधा नहीं मिल पाएगी। ऐसे में इस मार्ग पर नियमित रूप से यात्रा करने वाले लोगों को अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करना पड़ सकता है।

रेलवे प्रशासन के अनुसार, सर्दियों के मौसम में कश्मीर घाटी में तापमान में गिरावट और मौसम में बदलाव के कारण रेल परिचालन को सुचारु बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे में रेलवे पटरियों और संबंधित व्यवस्थाओं की जांच तथा आवश्यक तकनीकी कार्य पहले ही किए जाते हैं। इसी उद्देश्य से घाटी में प्री-विंटर डिस्ट्रेसिंग कार्य करवाया जाएगा, ताकि सर्दियों के दौरान रेल सेवाओं के संचालन में किसी तरह की बाधा न आए और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

सर्दियों से पहले तकनीकी कार्य के चलते बनिहाल-बारामूला रेलमार्ग पर सेवाएं रहेंगी प्रभावित

रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 74615 बानिहाल-बारामूला और ट्रेन संख्या 74620 बारामूला-बानिहाल को आज से 31 अक्टूबर तक निरस्त रखने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों रेलगाड़ियों के बंद रहने से बनिहाल और बारामूला के बीच आने-जाने वाले यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। खासकर नौकरी, शिक्षा और अन्य जरूरी कार्यों के लिए रेल से यात्रा करने वाले लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

जम्मू-कश्मीर में हिम तेंदुओं की गणना का दूसरा चरण हुआ शुरू



भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में हिम तेंदुओं की वास्तविक संख्या और उनके आवास का पता लगाने के लिए गणना का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ इंडिया (एसपीएआइ) 2.0 के तहत आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों की मदद से इन दुर्लभ वन्यजीवों की निगरानी और संरक्षण को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए कैमरा ट्रैप, रेडियो टेलीमेट्री और आनुवंशिक विश्लेषण जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।

भारत में पहली बार हुई हिम तेंदुओं की गणना में जम्मू-कश्मीर में नौ हिम तेंदुओं की मौजूदगी का अनुमान लगाया गया था। हालांकि, बाद में कैमरा ट्रैप से किए गए अध्ययनों में इनकी संख्या अधिक होने की संभावना जताई गई। लगभग 12 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किए गए अध्ययन के आधार पर इनकी संख्या 20 तक होने का अनुमान सामने आया। किश्तवाड़ हिमालय क्षेत्र के पाडर, वारवान और किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क को इनके प्रमुख आवासों में शामिल किया गया है।

आधुनिक तकनीकों से हिम तेंदुओं की संख्या और आवास का होगा वैज्ञानिक आकलन

हिम तेंदुए दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जिससे उनकी निगरानी चुनौतीपूर्ण होती है। कैमरा ट्रैप से उनकी मौजूदगी, रेडियो टेलीमेट्री से आवाजाही और आनुवंशिक नमूनों से जैविक विविधता का अध्ययन किया जाएगा।

जलवायु परिवर्तन, पशुओं की चराई, प्राकृतिक आवासों में मानवीय हस्तक्षेप और इंसान-वन्यजीव संघर्ष इनके अस्तित्व के लिए प्रमुख चुनौतियां हैं। बदलते तापमान से इनके अनुकूल आवास भी प्रभावित हो सकते हैं।

कश्मीर के रेपोरा गांव में अंगूर की बहार, मौसम की मार भी रही बेअसर



भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में इस साल अनिश्चित मौसम ने किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ाई। कई इलाकों में ओलावृष्टि, तेज हवाओं और बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा, लेकिन गांदरबल जिले के रेपोरा गांव में अंगूर की फसल पर मौसम का खास असर नहीं पड़ा। 'ग्रेप्स विलेज' के नाम से मशहूर यह गांव एक बार फिर लाल, हरे और बैंगनी अंगूरों की अच्छी पैदावार के कारण चर्चा में है। यहां अंगूर की खेती हजारों लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है। श्रीनगर से करीब 30 किलोमीटर उत्तर में स्थित रेपोरा गांव में अंगूर की तुड़ाई का काम पूरा हो चुका है। अब किसान बेलों की देखभाल और उन पर दवाइयों का छिड़काव करने में जुटे हैं, ताकि पौधे स्वस्थ रहें और अगली फसल के लिए तैयार हो सकें। स्थानीय अंगूर उत्पादक मोहम्मद रफीक राथर ने बताया कि इस साल मौसम में कई बार बदलाव आया, लेकिन गांव में ओलावृष्टि नहीं होने से अंगूर की फसल सुरक्षित रही। बारिश के बावजूद अच्छी पैदावार होने से किसानों को राहत मिली है। गांदरबल जिले में लगभग 206 हेक्टेयर भूमि पर अंगूर की खेती की जाती है। इसमें करीब 85 प्रतिशत क्षेत्र रेपोरा गांव में है। जिले में हर साल लगभग 1,500 से 1,700 मीट्रिक टन अंगूर का उत्पादन होता है। कश्मीर घाटी में होने वाली अंगूर की खेती का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा इसी गांव से जुड़ा बताया जाता है। यहां साहिबी, हुसैनी, किशमिश और पर्लेट जैसी किस्मों की खेती की जाती है। साहिबी और हुसैनी प्रमुख व्यावसायिक किस्में हैं, जबकि थॉमसन अंगूर का उपयोग मुख्य रूप से किशमिश बनाने में किया जाता है।

मां आशापुरी धाम

आस्था, प्रकृति और विकास का उभरता पर्यटन केंद्र



मां आशापुरी धाम।

पालमपुर और जयसिंहपुर क्षेत्र की पहाड़ियों पर स्थित मां आशापुरी मंदिर को एक सुव्यवस्थित धार्मिक-पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावना न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे सकती है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर एक नया आकर्षण भी जोड़ सकती है।

जिस प्रकार माता वैष्णो देवी मंदिर ने आधुनिक सुविधाओं, सुव्यवस्थित मार्गों और रोपवे जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित किया है, उसी तर्ज पर मां आशापुरी धाम का विकास एक दूरदर्शी पहल हो सकती है।

सबसे पहले, इस क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं को समझना आवश्यक है। पालमपुर और जयसिंहपुर के बीच फैली हरियाली, चाय बागानों की सुंदरता और धौलाधार की पर्वत श्रृंखला का दृश्य स्वयं में अद्वितीय है। इन प्राकृतिक संसाधनों के बीच स्थित मां आशापुरी का मंदिर आध्यात्मिक शांति के साथ-साथ प्राकृतिक सौंदर्य का संगम प्रस्तुत करता है, किंतु वर्तमान में यहां तक पहुंचने के साधन, सुविधाएं और पर्यटन प्रबंधन अपेक्षाकृत सीमित हैं।

यदि महाराज नगर से मां आशापुरी मंदिर तक एक आधुनिक रोपवे परियोजना विकसित की जाए, तो यह न केवल यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि वृद्ध, दिव्यांग और दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी सुविधा सुनिश्चित करेगा। रोपवे का निर्माण पर्यावरणीय दृष्टि से भी अपेक्षाकृत कम नुकसानदायक होता है, यदि इसे वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किया जाए। इससे सड़क निर्माण के कारण होने वाले वनों के कटाव को भी रोका जा सकता है। पर्यटन विकास केवल पहुंच तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही बुनियादी सुविधाओं का व्यापक विस्तार जरूरी है। मंदिर परिसर और उसके आसपास स्वच्छ शौचालय, पेयजल व्यवस्था, विश्राम स्थल, भोजनालय, मेडिकल सहायता केंद्र और सुरक्षा प्रबंधन जैसी सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए। डिजिटल टिकटिंग, भीड़ प्रबंधन प्रणाली और ऑनलाइन सूचना प्लेटफॉर्म भी इस परियोजना को आधुनिक स्वरूप देंगे।

इस तरह के विकास से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। होटल, गेस्ट हाउस, होम-स्टे, स्थानीय हस्तशिल्प और खाद्य उत्पादों की मांग बढ़ेगी। युवाओं को गाइड, ट्रांसपोर्ट और सेवा क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। यदि सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर इस दिशा में काम करें, तो यह क्षेत्र आत्मनिर्भर पर्यटन मॉडल का उदाहरण बन सकता है। हालांकि, विकास के साथ संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हिमालयी क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हैं, इसलिए किसी भी निर्माण कार्य में पर्यावरणीय मानकों का सख्ती से पालन होना चाहिए। अनियंत्रित भीड़, कचरा प्रबंधन की कमी और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस क्षेत्र की सुंदरता और स्थायित्व को नुकसान पहुंचा सकता है। अत: 'सस्टेनेबल टूरिज्म' को इस परियोजना का आधार बनाया जाना चाहिए। सरकार को इस दिशा में एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, जिसमें स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो। पंचायत स्तर पर योजनाओं का f, यान्वयन, स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन और पारदर्शी निवेश नीति इस परियोजना को सफल बना सकती है। साथ ही, धार्मिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखते हुए व्यावसायिकता और आस्था के बीच संतुलन बनाना भी आवश्यक होगा।

कुल मिलाकर, मां आशापुरी धाम का विकास केवल एक पर्यटन परियोजना नहीं, बल्कि क्षेत्रीय विकास का एक व्यापक अवसर है। यदि इसे योजनाबद्ध तरीके से, आधुनिक तकनीक और पारंपरिक मूल्यों के समन्वय के साथ विकसित किया जाए, तो यह स्थान आने वाले वर्षों में उत्तर भारत का एक प्रमुख धार्मिक-पर्यटन केंद्र बन सकता है। यह पहल न केवल श्रद्धालुओं की आस्था को सशक्त करेगी, बल्कि स्थानीय समाज और अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।



संदीप डोगरा
निजी सचिव मेडिकल कॉलेज टांडा,

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

आंतरिक साधना, अहिंसा के पथिक भगवान महावीर स्वामी



एआई निर्मित चित्र।

भारत विविधता से भरा हुआ देश है जहां पर हर धर्म के पर्व और त्योहारों को पूरे श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। महावीर जयंती का पर्व जैन धर्म के 24 में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज से 599 ईसा पूर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को क्षत्रिय कुल में भगवान महावीर का जन्म हुआ था।

राजसी क्षत्रिय कुल में पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला के घर तीसरी संतान के रूप में वर्धमान ने जन्म लिया था। घर में समस्त भौतिक सुख सुविधाओं का भंडार होने के बावजूद भी वर्धमान भगवान महावीर वैराग्य, तपस्या के मार्ग के पथिक बने। वैराग्य और साधना के प्रबल संस्कारों ने भगवान महावीर को आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान की। युवावस्था में ही वर्धमान ने आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हेतु समस्त भौतिक संसाधनों को त्याग दिया था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने श्रामणी दीक्षा ली। अपरिग्रह तथा अहिंसा की साधना का कठोरता से पालन किया। अपने शरीर के निर्वाह के लिए भी महावीर ने किंचित मात्र भी वस्त्रो का संग्रह नहीं किया। भोजन भी वर्धमान स्वयं अपने हाथों पर ही कर लिया करते थे। महावीर ने 12 साल तक मौन तपस्या की। 42 वर्ष की आयु में इन्हें कैवल्य (सर्वोच्च ज्ञान) प्राप्त हुआ। महावीर जी ने अपने उपदेश अर्धमागधी भाषा में दिए ताकि जन सामान्य भी उनके भाव को समझ सके। महावीर जी ने समस्त प्राणियों के आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया।

जैन धर्म में तीर्थंकर शब्द का अर्थ है वह आत्माएं जो मानवीय पीड़ा और हिंसा से भरे इस सांसारिक जीवन को पार कर आध्यात्मिक मुक्ति के क्षेत्र में पहुंच गई है। महावीर जी ने इसी आध्यात्मिक मुक्ति के आनंद को साधना से अनुभूत किया था। इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में लोगों को अहिंसा, सत्य, अचोर्य, ब्रह्मचर्य और



आचार्य दीप चंद भारद्वाज
(आध्यात्मिक चिंतक)

अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों पर चलने के लिए प्रेरित किया। जैन धर्म में इन पांच सिद्धांतों को 'पंच महाव्रत' कहा जाता है। मनसा वाचा कर्मणा जीवन में अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन करना, सदैव सत्याचरण करना, चोरी ने करना, इंद्रिय संयम का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य के पथ पर चलना, भौतिक पदार्थ का अत्यधिक संग्रह न करना इन सभी जीवन उपयोगी उपदेशों को महावीर जी ने जन सामान्य तक पहुंचाया।

महावीर स्वामी अहिंसा के मूर्तिमान प्रतीक थे। उन्हें वीर, अतिवीर, सन्मति के नामों से भी पुकारा जाता है। महावीर जी ने श्रमण-श्रामणी, श्रावक-श्राविका सबको लेकर चतुर्विध संघ की स्थापना की। उन्होंने कहा कि जो जिस अधिकार का है वह उसी वर्ग में आकर सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। वर्धमान जी आंतरिक दिव्य मानवीय भावनाओं के प्रबल संरक्षक थे। उनका चिंतन था कि इंद्रियों का सुख, विषय वासनाओं का सुख, दूसरों को दुख पहुंचा कर ही पाया जा सकता है। महावीर ने किसी के अस्तित्व को मिटाने की अपेक्षा उसे शांति से जीने दो तथा स्वयं भी शांति से जीवन व्यतीत करने का स्वर्णिम सूत्र दिया। 'अहिंसा परमो धर्म:' इनका आदर्श वाक्य था। आत्मवत सर्वभूतेषु अर्थात सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा का प्रतिबिंब देखना। भगवान महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसके भीतर ही होता है- क्रोध, अहंकार, लालच और आसक्ति। उन्होंने सिखाया कि ईर्ष्या, द्वेष और हिंसा के सूक्ष्म विचार भी त्यागने योग्य हैं तथा करुणा, सत्य और अहिंसा ही सच्चे जीवन का मार्ग हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

भारत को दुनिया में महाशक्ति बनना है तो पक्ष और विपक्ष को चलना होगा साथ

मतभेद रहें कायम, लेकिन सर्वोपरि हो राष्ट्रहित



एआई निर्मित चित्र।

भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अपनी प्राचीन सभ्यता, समृद्ध संस्कृति, विशाल जनसंख्या, आर्थिक क्षमताओं और वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण भारत का विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र बनना नहीं, बल्कि विश्व की एक प्रमुख महाशक्ति के रूप में उभरना भी है। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों को राष्ट्रहित में मिलजुलकर काम करना होगा।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें विचारों की विविधता को स्थान दिया जाता है। सत्ता पक्ष सरकार चलाता है और देश के विकास के लिए नीतियां निर्धारित करता है, जबकि विपक्ष सरकार की नीतियों की समीक्षा करते हुए उनकी कमियों को उजागर करता है और जनता की समस्याओं को सामने लाता है। इस प्रकार, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए जितनी आवश्यकता सक्षम सरकार की होती है, उतनी ही आवश्यकता जिम्मेदार विपक्ष की भी होती है। दोनों की भूमिका देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने और विकास को गति देने में महत्त्वपूर्ण है।

भारत को महाशक्ति बनाने के लिए आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, तकनीक, रक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में निरंतर प्रगति करनी होगी। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक नीतियों की आवश्यकता है। यदि प्रत्येक सरकार केवल अपने कार्यकाल तक सीमित होकर योजनाएं बनाएगी और अगली सरकार राजनीतिक कारणों से पुरानी योजनाओं को रोक देगी, तो विकास की गति धीमी पड़ जाएगी। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा सुधार, गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन और आधारभूत संरचना जैसे विषयों पर व्यापक राजनीतिक सहमति बनना बहुत आवश्यक है। इन क्षेत्रों में निरंतरता बनाए रखने से देश की विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।

सत्ता पक्ष को भी यह समझना होगा कि विपक्ष लोकतंत्र का विरोधी नहीं, बल्कि उसका एक अभिन्न अंग है। सरकार को विपक्ष की आलोचनाओं को व्यक्तिगत हमले के रूप में लेने के बजाय उनमें छिपे उन सुझावों पर विचार करना चाहिए, जो देशहित में हों। वहीं, विपक्ष का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह केवल विरोध के लिए विरोध न करे। उसे सरकार की गलत नीतियों का तार्किक विरोध करना चाहिए और देशहित में लिए जा रहे अच्छे निर्णयों का समर्थन भी करना चाहिए। राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र की शक्ति हैं, लेकिन जब ये मतभेद राष्ट्रीय हित से ऊपर उठ जाते हैं, तब वे देश की प्रगति में बाधा बनते हैं।

विजय शर्मा

आज दुनिया में वही देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जहां राजनीतिक स्थिरता, मजबूत संस्थाएं और दूरदर्शी नेतृत्व मौजूद हैं। भारत के पास व्यापक युवा जनसंख्या, प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, कुशल उद्यमी और विशाल बाजार जैसी अनेक शक्तियां हैं। इन क्षमताओं का पूरा लाभ तभी उठाया जा सकता है, जब राजनीतिक दल आपसी प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ सहयोग की भावना भी विकसित करें। देश के युवाओं को बेहतर शिक्षा, रोजगार और नवाचार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी सभी दलों को मिलकर प्रयास करने चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि विपक्ष सरकार से प्रश्न पूछना छोड़ दे या सत्ता पक्ष अपनी नीतियों पर समझौता कर ले। बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि संसद में सार्थक मुद्दों पर बहस हो, महत्त्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाए और जनता से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठाकर जनकल्याण से जोड़ा जाए। लोकतंत्र में स्वस्थ बहस और असहमति की अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

'उड़ता हिमाचल' और सवालों के घेरे में प्रशासन



एआई निर्मित चित्र।

देवभूमि हिमाचल, जो कभी अपनी शांत वादियों और नशा-मुक्त छवि के लिए जाना जाता था, आज वही प्रदेश नशे की गंभीर समस्या में जकड़ता दिखाई दे रहा है। इसका असर सबसे अधिक प्रदेश की युवा पीढ़ी में साफ दिखाई दे रहा है।

चिट्टे और अन्य नशीले पदार्थों का जाल न केवल युवा पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में ले रहा है, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर यह नशे का जाल प्रदेश में फैला कैसे और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है और यही वजह है कि आज 'उड़ता हिमाचल' जैसी चिंता बार-बार सामने आने लगी है। प्रदेश में नशे के बढ़ते मामलों को लेकर सामने आए आधिकारिक आंकड़े भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। ऐसा शायद ही कोई दिन जाता हो जब प्रदेश का कोई समाचार पत्र नशे के सरगनाओं, तस्करी और गिरफ्तारी से जुड़ी खबरें प्रकाशित न करता हो। विधानसभा में दिए गए लिखित उत्तर में सरकार ने यह जानकारी दी है कि वर्ष 2023 से जनवरी 2026 तक नशे से जुड़े 6246 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि ओवरडोज के कारण 66 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में बढ़ता नशे का जाल आज एक गंभीर सामाजिक संकट का रूप ले चुका है। बेरोजगारी, अकेलापन, प्रशासनिक कमजोरियां, पैसों का लालच, सीमा पार से तस्करी और तेजी से फैलता पार्टी कल्चर-ये सभी कारक मिलकर इस समस्या को और गहरा बना रहे हैं।

कभी शांत और देवभूमि के रूप में पहचाने जाने वाले इस प्रदेश में अब युवाओं का एक वर्ग नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है, जो समाज के लिए चिंता का विषय है। सबसे अधिक प्रभावित युवा पीढ़ी हो रही है, जो भविष्य का आधार मानी जाती है। रोजगार के सीमित अवसर, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और मानसिक तनाव युवाओं को गलत रास्तों की ओर धकेल रहे हैं। वहीं, आधुनिक जीवनशैली और दिखावे की संस्कृति ने भी नशे को 'फैशन' के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, जो स्थिति को और गंभीर बना रहा है। सीमा पार से होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी इस समस्या को और हवा दे रही है, जिससे नशे की उपलब्धता आसान हो गई है।

इस पूरे परिदृश्य में प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। कई मामलों में कार्रवाई की धीमी गति और निगरानी की कमी से तस्करों के हौसले बुलंद होते दिखाई देते हैं। यदि कानून का भय कम होगा, तो इस तरह के अवैध कारोबार को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि प्रशासन अधिक सक्रिय, सतर्क और कठोर रुख अपनाए। इस समस्या से निपटने के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि समाज और परिवार की भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में नियमित जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में सही जानकारी देना बेहद जरूरी है।



अभिषेक कुमार

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

संपादकीय

आरक्षण पर संवैधानिक सवाल

बेहतर सामाजिक स्थिति, समान अवसर और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा आरक्षण का प्रश्न एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय ने अनुसूचित जाति के दर्जे और धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण की पात्रता को लेकर बहस को नई दिशा दी है। इस विषय पर मद्रास उच्च न्यायालय भी निर्णय दे चुका था, जिसे तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। राज्य सरकार उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहती थी, जिसके तहत अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कुछ लोगों को इस्लाम या ईसाई मत अपनाने के बाद भी आरक्षण का लाभ जारी रखने की सुविधा देने का प्रयास किया गया था। इस पूरे प्रकरण ने आरक्षण की पात्रता, धार्मिक पहचान और सामाजिक न्याय के बीच संबंधों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को समान अवसर उपलब्ध कराना और सामाजिक असमानताओं को कम करना है। इसी कारण आरक्षण से संबंधित नियमों और पात्रता की शर्तों का स्पष्ट होना आवश्यक है। धर्म परिवर्तन के बाद किसी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिल सकता है या नहीं, यह प्रश्न संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और लागू कानूनों के आधार पर तय होता है। ऐसे मामलों में केवल व्यक्तिगत धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि उस सामाजिक श्रेणी के लिए निर्धारित कानूनी शर्तें भी महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए इस विषय पर विचार करते समय न्यायिक निर्णयों और संवैधानिक व्यवस्था को समझना जरूरी है।

इस बहस का एक प्रमुख पक्ष यह है कि क्या धर्म परिवर्तन के बाद सामाजिक भेदभाव समाप्त हो जाता है। दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों के संगठन लंबे समय से यह तर्क देते रहे हैं कि धर्म बदलने के बावजूद सामाजिक और आर्थिक वंचना का प्रभाव बना रह सकता है। उनका कहना है कि कुछ क्षेत्रों में जातिगत पहचान और उससे जुड़ी असमानताएं नए धार्मिक समुदायों में भी दिखाई देती हैं। दूसरी ओर, आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था में अनुसूचित जाति के दर्जे और उससे मिलने वाले लाभों के लिए विशिष्ट कानूनी प्रावधान लागू होते हैं। ऐसे में सामाजिक वास्तविकताओं और कानूनी पात्रता के बीच संबंध को लेकर विभिन्न पक्ष अलग-अलग दृष्टिकोण रखते हैं।

आरक्षण के साथ अल्पसंख्यक समुदायों को मिलने वाली सुविधाओं का प्रश्न भी इस बहस से जुड़ता है। कुछ लोगों का मानना है कि धर्म परिवर्तन के बाद विभिन्न सरकारी योजनाओं की पात्रता को लेकर स्पष्टता होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी या नियमों के दुरुपयोग की आशंका कम हो। हालांकि, आरक्षण और अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं अलग-अलग कानूनी प्रावधानों और नीतियों के तहत संचालित होती हैं। इसलिए यह मान लेना उचित नहीं होगा कि धर्म परिवर्तन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वत: सभी प्रकार के अतिरिक्त लाभों का पात्र बन जाता है। किसी भी सुविधा की पात्रता संबंधित योजना के नियमों के अनुसार ही निर्धारित की जानी चाहिए।

मतांतरण के मुद्दे पर देश के कई राज्यों में कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों का उद्देश्य बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन के माध्यम से होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना बताया जाता है। समय-समय पर कुछ राज्यों ने इन कानूनों में संशोधन कर प्रावधानों को अधिक कठोर भी किया है। फिर भी इस विषय पर धार्मिक स्वतंत्रता और अवैध तरीकों से होने वाले धर्म परिवर्तन के बीच अंतर करना आवश्यक है। किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म चुनने का अधिकार है, जबकि दबाव, धोखाधड़ी या अनुचित प्रलोभन के जरिए धर्म परिवर्तन कराने की शिकायतों की जांच कानून के अनुसार की जानी चाहिए।

इस संदर्भ में सरकारों की जिम्मेदारी केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं रह सकती। कानूनों का निष्पक्ष और प्रभावी क्रियान्वयन, शिकायतों की उचित जांच और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी जरूरी है। इसके साथ ही लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों, आरक्षण की पात्रता और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सही जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को कानूनी प्रक्रियाओं से परिचित कराना भी उपयोगी हो सकता है। इससे वे किसी भी प्रकार के दबाव, धोखाधड़ी या गलत जानकारी के आधार पर निर्णय लेने से बच सकेंगे।

आरक्षण की पात्रता को लेकर अस्पष्टता दूर करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता भी महत्वपूर्ण है। संबंधित नियमों की स्पष्ट जानकारी सरकारी माध्यमों पर उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि लोगों को अपनी स्थिति समझने में कठिनाई न हो। किसी व्यक्ति के अधिकारों का निर्धारण अफवाहों या सामान्य धारणाओं के आधार पर नहीं, बल्कि लागू कानूनों और न्यायिक निर्णयों के अनुरूप होना चाहिए। इसी तरह किसी पूरे धार्मिक समुदाय या संगठन को एक ही दृष्टि से देखना भी उचित नहीं है। आरोपों और दावों की जांच प्रमाणों के आधार पर की जानी चाहिए।

-शिवांश धाकड़

आज की प्रमुख हस्ती

दक्षिण सिनेमा की दमदार अभिनेत्री

कीर्ति सुरेश भारतीय सिनेमा की प्रमुख अभिनेत्रियों में शामिल हैं। उनका जन्म 17 अक्टूबर 1992 को हुआ था। वह मुख्य रूप से तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में अभिनय करती हैं। अपने प्रभावशाली अभिनय और विविध भूमिकाओं के कारण उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में अलग पहचान बनाई है। उनके नाम एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, पांच साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवॉर्ड्स (साइमा), एक तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार और दो फिल्मफेयर अवॉर्ड्स साउथ सहित कई प्रतिष्ठित सम्मान दर्ज हैं। वर्ष 2021 में उन्हें फोर्ब्स इंडिया की 30 अंडर 30 सूची में भी स्थान मिला था।



कीर्ति सुरेश
जन्म : 17 अक्टूबर 1992

कीर्ति सुरेश का जन्म फिल्म निर्माता जी. सुरेश कुमार और अभिनेत्री मेनका के घर हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2000 के शुरुआती वर्षों में बाल कलाकार के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने फैशन डिजाइन की पढ़ाई की और फिर फिल्मों में वापसी की। वर्ष 2013 में प्रदर्शित मलयालम फिल्म गीतांजलि में उन्होंने पहली बार मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का साइमा पुरस्कार मिला। वर्ष 2015 में तमिल फिल्म इधु एन्ना मायम के लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ।

इसके बाद कीर्ति ने कई सफल फिल्मों में अभिनय किया। उनकी प्रमुख फिल्मों में रिंग मास्टर (2014), नेनु शैलजा (2016), राजिनीमुरुगन (2016), रेमो (2016), भैरवा (2017), नेनु लोकल (2017), थाना सेरंध कूट्टम (2018), सरकार (2018), सरकारु वारी पाटा (2022) और दसरा (2023) शामिल हैं। इन फिल्मों ने उन्हें विभिन्न भाषाओं के दर्शकों के बीच लोकप्रियता दिलाई।

वर्ष 2018 में आई जीवनीपरक फिल्म महानटी उनके करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई। इसमें उन्होंने प्रसिद्ध अभिनेत्री सावित्री की भूमिका निभाई। उनके अभिनय को व्यापक सराहना मिली और इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। वर्ष 2023 में प्रदर्शित फिल्म दसरा में उनके अभिनय के लिए उन्हें एक और फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार प्राप्त हुआ।



कविता

गाय की व्यथा

रवि कुमार, बिलासपुर
हिमाचल प्रदेश

शरीर में पीड़ा,
आंखों में पानी।
छम-छम रोती,
गऊ माता सयानी।
मैं भी थी कभी पंचगव्य खान,
भूतकाल का तो कर लो ध्यान।
जीर्ण-शीर्ण अवस्था मेरी,
न कर घोर अपमान,
श्रेष्ठ मनु संतान।
मां को यूं न कर दरकिनार,
दूध-मक्खन से पाला है लाल।
मृत्युशैया बेला आयेगी मेरी याद,
बेसुध पड़ा इच्छुक होगा गऊदान,
तेरे ऊपर अपने कुछ एहसान,
मनुसंतान न बन अनजान।
मेरे खातिर गोशाला तो बनवा,
पॉलीथिन में न डाल खाद्य पदार्थ,
बन महाभारत का श्रेष्ठ धनुर्धर पार्थ।
पॉलीथिन गलता नहीं पेट में,
चरने दे घासणियां, बंजर खेत में। संडे हो या मंडे,
निर्बल शरीर सहता जोर के डंडे। गो सदन खोल सरकार करे आगाज,
जनसहयोग बिना अधूरे ये काज। मेरा भी तो नहीं कसूर,
भूख-प्यास से बेहाल हूं हुजूर। मानी जाती हूं 33 कोटि देव निवास,
लगा रखी है आपसे आस। मेरे पुत्र हल जोतें, धरती उगले सोना ।
तेरे कामों के कारण, बुढ़ापे में पड़ा विलख कर रोना ।

'भारतेन्दु शिखर'

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

न्यूज ब्रीफ

बिना पंजीकरण रह रहे प्रवासियों पर सख्ती एसडीएम ने भूमि मालिकों को जारी किए नोटिस

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। उपमंडल नादौन में बिना पुलिस पंजीकरण और सत्यापन के रह रहे प्रवासियों के मामलों में प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। संबंधित भूमि मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। नगर परिषद नादौन ने खुले में शौच के मामलों में भी नोटिस दिए हैं। एसडीएम निशांत शर्मा ने तहसीलदारों को पत्र लिखकर प्रवासियों की झुग्गियों की संख्या और उनमें रहने वाले लोगों का ब्योरा मांगा है। उन्होंने कहा कि पूरे उपमंडल में विशेष अभियान चलाकर पंजीकरण और सत्यापन की जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। एसडीएम ने लोगों से किरायेदारों का पुलिस सत्यापन करवाने और लिखित समझौता तैयार करने की अपील की।

जयसिंहपुर के राज्य स्तरीय दशहरा उत्सव में पंजाबी गायक निंजा मचाएंगे धमाल

भारतेन्दु संवाददाता, जयसिंहपुर। राज्य स्तरीय दशहरा उत्सव 18 से 20 अक्तूबर तक आयोजित होगा। अंतिम सांस्कृतिक संध्या में 20 अक्तूबर को पंजाबी गायक निंजा और हास्य कलाकार दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। पहली संध्या में डॉ. गगन सिंह और अंजली नानक प्रस्तुति देंगे, जबकि दूसरी संध्या पहाड़ी और स्थानीय कलाकारों के नाम रहेगी। मेला कमेटी अध्यक्ष एवं एसडीएम संजीव ठाकुर ने तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कानून-व्यवस्था, यातायात, पार्किंग और विभागीय प्रदर्शनियों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उत्सव में खेल प्रतियोगिताएं भी होंगी। दर्शकों की सुविधा के लिए तीनों सांस्कृतिक संध्याओं में अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला कुल्लू द्वारा युवती सम्मेलन 'ओजस्विनी' का आयोजन

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिला कुल्लू ने युवती सम्मेलन 'ओजस्विनी' का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्देश्य युवतियों में आत्मविश्वास, नारी शक्ति, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। कार्यक्रम में पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष धनेश्वरी ठाकुर मुख्य अतिथि रहीं। आरोग्य भारती की जिला स्वास्थ्य प्रमुख श्यामा सोलंकी और पतंजलि योग समिति की जिला प्रभारी बिंदिया सूद विशिष्ट अतिथि रहीं। प्रदेश सह मंत्री जाह्नवी चौहान भी उपस्थित रहीं। अध्यक्षता जिला परिषद कटराई की जिंदु देवी ने की। वक्ताओं ने युवतियों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सशक्त बनकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संदेश दिया।

लाल चंद प्रार्थी कला केंद्र के जीर्णोद्धार पर परिवार ने जताया आभार

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। लाल चंद प्रार्थी कला केंद्र के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण पर प्रार्थी परिवार ने विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का आभार जताया। अधिवक्ता अनुराग प्रार्थी ने कहा कि केंद्र का नया स्वरूप कुल्लू की सांस्कृतिक विरासत को संजोने की दिशा में सराहनीय पहल है। भवन पर पारंपरिक लोकनृत्य, लोकजीवन और कुल्लवी शैली की सजावट इसकी सुंदरता बढ़ाती है। उन्होंने संबंधित विभागों, अधिकारियों, कलाकारों, कारीगरों और श्रमिकों के योगदान की सराहना करते हुए केंद्र के नियमित रखरखाव की उम्मीद जताई।

पठानकोट में अवैध खनन पर छापा, पोकलेन मशीन और बजरी से भरा टिप्पर जब्त

अशोक ठाकुर, पठानकोट। तारागढ़ पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने गांव जसवां में अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी कर पोकलेन मशीन और करीब 400 क्यूबिक फीट बजरी से भरा टिप्पर जब्त किया। कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। खनन विभाग के जूनियर इंजीनियर अभिमन्यु कांडा की शिकायत पर पुलिस ने मानवाल बाग निवासी नवजोत सिंह के खिलाफ खान एवं खनिज अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बंजार की 40 पंचायतों के प्रतिनिधियों को वन अधिकार कानून की जानकारी

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। बंजार उपमंडल की सभी 40 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों का वन अधिकार अधिनियम के तहत सात चरणों में प्रशिक्षण पूरा हो गया है। एसडीएम पंकज शर्मा के अनुसार, अब तक 238 वन अधिकार समितियों में से 172 के सामुदायिक वन अधिकार स्वीकृत किए जा चुके हैं। जल्द ही अधिकार पत्र वितरित कर उन्हें राजस्व और वन विभाग के अभिलेखों में दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

मुख्यमंत्री सुक्खू की नीतियों से प्रभावित होकर अमर चंद जग्गी और देव राज ने थामा कांग्रेस का हाथ

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। बूणी पंचायत में सेवानिवृत्त प्रिंसिपल अमर चंद जग्गी और भाजपा के पूर्व बूथ अध्यक्ष देव राज ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन पृथ्वी चंद ने दोनों को पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य रवींद्र गद्दी सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

अघोषित बिजली कटों से बिलासपुरवासी परेशान, सरकार स्मार्ट मीटर थोपने में व्यस्तः त्रिलोक जमवाल

अमर सिंह ठाकुर, बिलासपुर। सदर विधायक त्रिलोक जमवाल ने जिले में अघोषित बिजली कटों को लेकर प्रदेश सरकार और बिजली बोर्ड प्रबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाखड़ा बांध परियोजना के लिए बलिदान देने वाले बिलासपुरवासी आज खुद बिजली संकट से जूझ रहे हैं। शहर और गांवों में बार-बार कट लगने से विद्यार्थियों, व्यापारियों और गृहिणियों को परेशानी हो रही है। इससे टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे उपकरण भी खराब हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रिक्त पद भरने के बजाय सरकार उपभोक्ताओं पर स्मार्ट मीटर थोपने में व्यस्त है।

भानुपली-बिलासपुर रेलवे लाइन के तहत टनल नंबर-16 और पुलों का किया निरीक्षण

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। उपायुक्त राहुल कुमार ने शुक्रवार को एसडीएम सदर राजकुमार और रेलवे अधिकारियों के साथ भानुपली-बिलासपुर रेलवे लाइन परियोजना के तहत भराड़ी टनल नंबर-16 के समीप निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने धीमी गति से चल रहे टनल और पुलों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने स्थानीय लोगों की सड़क, रास्ते और पानी संबंधी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने को कहा। उन्होंने फोरलेन से जबली को जोड़ने वाली बंद सड़क जल्द बहाल करने और भूमि अधिग्रहण के लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश भी दिए।

साईगलू व तल्याहड़ फीडर की मरम्मत 18 अक्टूबर को, बिजली बाधित रहेगी

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। विद्युत उपमंडल साईगलू के सहायक अभियंता विनीत ठाकुर ने बताया कि 33/22 केवी सब-स्टेशन साईगलू के तहत 22 केवी कोटली और तल्याहड़ फीडर की मरम्मत तथा नए जीओ स्विच लगाने का कार्य 18 अक्टूबर को किया जाएगा। इसके चलते संबंधित क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान कोट, डवाहन, तरयासल, माहन, कून, कडकोह, लागधार, सताहन, खलाणू, बरनोटा, कोटली, सूराड़ी, सैण, सलेतर, हार्ट, साईगलू, साई, सदयाणा, लरवाहन, सतोहल, गोखड़ा, बटाहर, बतौर और सेहली सहित आसपास के क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। सहायक अभियंता ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।

मंत्री जगत सिंह नेगी ने परियोजना सलाहकार समिति सहित विभिन्न बैठकों की अध्यक्षता की

सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें: जगत सिंह नेगी

भारतेन्दु संवाददाता, काजा। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने शुक्रवार को अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय काजा में उपमंडल स्तरीय परियोजना सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्पीति क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई और लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए गए।



स्पीति में विकास कार्यों की समीक्षा करते मंत्री नेगी।

मंत्री ने गत बैठक में दिए गए निर्देशों पर हुई कार्रवाई और विभिन्न विभागों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने बागवानी, कृषि, स्वास्थ्य, पशुपालन और कल्याण विभागों को अपनी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा पंचायत स्तर पर संयुक्त जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एक ही स्थान पर मिलेगा।

उन्होंने लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को निर्माणाधीन योजनाएं तय समयसीमा में पूरी करने तथा कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। सीमा सड़क संगठन को समदो-काजा सड़क के उन्नयन कार्य में तेजी लाने और मार्ग पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए। इसके बाद मंत्री ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्राप्त दावों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वन अधिकार उन्हीं पात्र लोगों को मिलेंगे, जो अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करते हों। वन भूमि हस्तांतरण से पहले ग्राम सभा में 50 प्रतिशत कोरम के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि दावे के लिए आवेदन और साक्ष्य प्रस्तुत करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता। तीसरी बैठक में भूमि अधिग्रहण और नौतोड़ से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई।

मंत्री ने संबंधित विभागों को मामलों का नियमानुसार निपटारा करने, आपसी समन्वय बढ़ाने और प्रभावित लोगों की समस्याओं पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठकों में विधायक अनुराधा राणा, एसडीएम एवं परियोजना अधिकारी दीक्षित राणा, तहसीलदार धर्मपाल नेगी, बीडीसी अध्यक्ष छेरिंग डोलमा, उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह, अतिरिक्त सचिव राजस्व बलवान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और समिति सदस्य उपस्थित रहे। मंत्री ने अधिकारियों को जनजातीय क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

होनहार युवा खिलाड़ी आयुष कौंडल को पूरे सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई

- गणमान्य लोगों ने आयुष को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। बकारटी के होनहार युवा वॉलीबाल खिलाड़ी आयुष कौंडल की अकस्मात मृत्यु से क्षेत्र में शोक की लहर है। शुक्रवार को उनके अंतिम संस्कार में 500 से अधिक लोगों ने शामिल होकर नम आंखों से विदाई दी। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, खेल विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों, सहपाठियों और ग्रामीणों ने शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया। जानकारी के अनुसार, आयुष शिमला जिले की तहसील कुपवी में आयोजित अंडर-19 खेल प्रतियोगिता में हमीरपुर जिला की वॉलीबाल टीम की जीत के बाद निजी बस से वापस लौट रहे थे।

इसी दौरान कुपवी से करीब चार-पांच किलोमीटर आगे उनका सिर टेलीफोन के खंभे से टकरा गया। घायल अवस्था में उन्हें कुपवी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के लिए उनकी पार्थिव देह आईजीएमसी शिमला ले जाई गई। इसके बाद वीरवार शाम करीब छह बजे पार्थिव देह घर पहुंची और शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील कुमार शर्मा बिट्टू, स्थानीय विधायक आशीष शर्मा, हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुनील कुमार, खेल एवं युवा सेवाएं विभाग के कर्मचारी और नाल्टी स्कूल के समस्त स्टाफ सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

आयुष साधारण परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिता हुकम चंद मेहनत-मजदूरी कर बेटे को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत थे। वॉलीबाल में आयुष के शानदार प्रदर्शन और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चयन की जानकारी से उनके साथी गौरवान्वित थे। उनके असमय निधन से गांव, स्कूल, सहपाठियों और दोस्तों में गहरा दुख है। ग्रामीणों ने आयुष को प्रतिभाशाली खिलाड़ी बताते हुए कहा कि उसके निधन से क्षेत्र ने खेल जगत में आगे बढ़ने की अपार संभावनाओं वाले युवा को खो दिया है।

सेना का अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना पूर्व सैनिकों की सबसे बड़ी पहचान

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश एवं जिला पदाधिकारियों ने शुक्रवार को समीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात की। इस दौरान धूमल ने कहा कि पूर्व सैनिक सेवानिवृत्ति के बाद भी अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रसेवा की भावना से समाज में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनका अनुभव और देश के प्रति निष्ठा संगठन की ताकत है।



प्रो. धूमल ने वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के अनुभव साझा करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने बताया कि चार जुलाई 1999 को वह तत्कालीन भाजपा प्रदेश प्रभारी नरेंद्र मोदी के साथ कारगिल पहुंचे थे, ताकि सैनिकों का मनोबल बढ़ाया जा सके। पूर्व सैनिकों के कल्याण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 1990 में लोकसभा में पहली बार वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा उठाया गया था। नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में सुजानपुर रैली के दौरान इसे लागू करने का वादा किया, जिसे केंद्र सरकार बनने के बाद पूरा किया गया।

उन्होंने पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) को भी पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण बताया। धूमल ने कहा कि कारगिल युद्ध में हिमाचल के 52 शहीदों के परिवारों से मिलकर आर्थिक सहायता दी गई। शहीदों के आश्रितों के लिए पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियों और बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के प्रयास भी किए गए। उन्होंने पूर्व सैनिकों से समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान व कल्याण सुनिश्चित करना राष्ट्र का दायित्व है।

यूनिटी पब्लिक स्कूल रिवालसर में आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

भारतेन्दु संवाददाता, रिवालसर। यूनिटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रिवालसर में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों को प्राकृतिक एवं मानव-जनित आपदाओं से बचाव और आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने भूकंप से बचाव के लिए 'ड्रॉप, कवर और होल्ड' तकनीक का अभ्यास किया। इसके अलावा बांस, कपड़े, रस्सी और मजबूत बोरियों की सहायता से अस्थायी स्ट्रेचर बनाने तथा घायलों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का प्रदर्शन किया गया। अग्निशामक यंत्र के उपयोग की जानकारी देने के साथ मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई। विद्यार्थियों ने चित्रों, पोस्टरों और जागरूकता-पट्टों के माध्यम से आपदा प्रबंधन का संदेश दिया। प्रधानाचार्य डी.डी. शर्मा ने कहा कि आपदा के समय धैर्य, सतर्कता, पूर्व तैयारी और सामूहिक सहयोग बेहद जरूरी हैं।

ऊना में कांगड़ा का दबदबा, विवेक तिवारी की घातक गेंदबाजी से धर्मशाला को 73 रन से हराया

सोहम ने 50 रन की पारी खेली, लेकिन धर्मशाला को हार से नहीं बचा सके

आशीष दमीर, भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में एमसीएम डीएवी कांगड़ा कॉलेज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए धर्मशाला कॉलेज को 73 रन से हरा दिया। ऊना में खेले गए इस मुकाबले में कांगड़ा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में धर्मशाला की टीम 15.2 ओवर में 97 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ कांगड़ा कॉलेज ने फाइनल में जगह पक्की कर ली।



कांगड़ा कॉलेज की टीम ने धर्मशाला को हराकर फाइनल में बनाई जगह।

कांगड़ा की ओर से सलामी बल्लेबाज अरशद धीमान ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों में नौ चौकों और एक छक्के की मदद से 57 रन बनाए। ध्रुव सिंह ने 40 और सुकृत शर्मा ने 34 रन की उपयोगी पारियां खेलकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। धर्मशाला की ओर से सक्षम और प्रवल ने दो-दो विकेट हासिल किए।

171 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी धर्मशाला की टीम कांगड़ा के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी। विवेक तिवारी ने घातक गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में एक मेडन के साथ महज सात रन देकर चार विकेट झटके। उनकी शानदार गेंदबाजी ने धर्मशाला की बल्लेबाजी को पूरी तरह दबाव में ला दिया। धर्मशाला की ओर से सोहम ने 50 रन बनाकर संघर्ष किया, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से पर्याप्त सहयोग नहीं मिला।

टीम 15.2 ओवर में 97 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। सुकृत शर्मा और अरशद धीमान ने भी दो-दो विकेट लेकर कांगड़ा की जीत में अहम योगदान दिया। इस शानदार जीत के साथ कांगड़ा कॉलेज की टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब टीम की नजर खिताब जीतने पर रहेगी। विवेक तिवारी की बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजों के उपयोगी योगदान ने कांगड़ा की जीत में निर्णायक भूमिका निभाई।

राष्ट्रीय स्तर पर चयन से बढ़ा हिमाचल का गौरव, बोर्ड अध्यक्ष ने किया सम्मानित

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड परिवार के लिए गर्व की बात है कि बोर्ड कार्यालय में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के पद पर कार्यरत तुलसी देवी की सुपुत्री का अंडर-17 बैडमिंटन प्रतियोगिता के राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन हुआ है। इस उपलब्धि पर बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने कार्यालय में छात्रा को सम्मानित कर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयन छात्रा की मेहनत, लगन, प्रतिभा और समर्पण का परिणाम है। यह उपलब्धि उनके परिवार के साथ पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। खेलों में ऐसी उपलब्धियां अन्य विद्यार्थियों को भी लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करती हैं।

डीसी ने रागी पाउडर के उपयोग एवं बच्चों के पोषण पर महिलाओं के साथ किया संवाद

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। छोटे बच्चों में कुपोषण रोकने और बेहतर पोषण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग की पहल पर भोरंज में शुरू किए गए पोषण हस्तक्षेप कार्यक्रम की समीक्षा की गई। उपायुक्त गंधर्व राठौड़ ने शुक्रवार को मिनी सचिवालय में महिलाओं के साथ दूसरे चरण का संवाद किया। इसमें बच्चों की माताओं सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया।



उपायुक्त ने बताया कि कार्यक्रम के तहत छोटे बच्चों को पौष्टिक गुणों से भरपूर रागी पाउडर दिया जा रहा है। इससे तैयार विभिन्न व्यंजन बच्चों को पसंद आ रहे हैं और उनके स्वास्थ्य तथा शारीरिक विकास के मानकों में सुधार दिखाई देने लगा है। उन्होंने कहा कि इस माह रागी से बने कुछ नए व्यंजन और उत्पाद भी उपलब्ध करवाए गए हैं।

माताएं इनके बारे में अपना फीडबैक दें, ताकि बच्चों के पोषण में जरूरी सुधार किए जा सकें। इन उत्पादों को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली खाद्य सामग्री की सूची में शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है। इस अवसर पर एसडीएम शशिपाल शर्मा, सीडीपीओ सुनील कुमार, कुलदीप चौहान, तहसीलदार डॉ. आशीष शर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं।

मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार ने किया प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने लिए ऐतिहासिक निर्णय : सुनील शर्मा बिट्टू

अनिल कुमार, हमीरपुर। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने शुक्रवार को आईटीआई हमीरपुर में जाइका के तहत हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना (एचपीसीडीपी) चरण-2 द्वारा ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रायोजित साढ़े चार माह के टेलरिंग एंड कटिंग प्रशिक्षण कोर्स का शुभारंभ किया।



उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। एचपीशिवा परियोजना, राजीव गांधी प्राकृतिक खेती और खुशहाल किसान योजना सहित विभिन्न योजनाओं से किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्राकृतिक खेती की उपज के लिए अधिक दाम निर्धारित किए गए हैं और दूध के दाम में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि एचपीसीडीपी चरण-2 कृषि विकास, सिंचाई और क्षमता निर्माण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा दे रही है। सिलाई-कटिंग प्रशिक्षण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। उन्होंने प्रशिक्षुओं से कोर्स का लाभ उठाकर स्वरोजगार अपनाने और परिवार की आय बढ़ाने की अपील की। इस अवसर पर परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान, जाइका अधिकारी शोतारो हयासी, आईटीआई प्रधानाचार्य सुभाष चंद शर्मा और एपीएमसी अध्यक्ष अजय शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

शुभारंभ | जोगेंद्रनगर विधानसभा की विभिन्न पंचायतों में विकास कार्यों को मिलेगी प्राथमिकता

जोगेंद्रनगर में 1.30 करोड़ की जायका परियोजना का शुभारंभ

जितेंद्र कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, जोगेंद्रनगर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जीवन ठाकुर ने शुक्रवार को उपमंडल की ग्राम पंचायत हार गुनैण के नागचला गांव में 1.30 करोड़ रुपये की जायका परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दे रही है।



पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को धरातल पर उतारने की पहल।

जीवन ठाकुर ने कहा कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जायका) के सहयोग से संचालित यह परियोजना वानिकी और ग्रामीण विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत जोगेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। परियोजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने और लोगों की आजीविका से जुड़े कार्यों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जोगेंद्रनगर के समग्र विकास के लिए वह लगातार प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में क्षेत्र की पंचायतों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। जायका परियोजना से ग्रामीण विकास और वानिकी से जुड़े कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है। इस पहल के लिए स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष जीवन ठाकुर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि परियोजना के तहत पंचायत स्तर पर ठोस विकास कार्य होंगे और ग्रामीणों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

इस अवसर पर ग्राम पंचायत हार गुनैण के प्रधान मुकेश ठाकुर, महिला मोर्चा अध्यक्ष दक्षा देवी, जिला जायका परियोजना अधिकारी हेमराज, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर अश्वनी कुमार, कृषि अधिकारी निशांत, सेवादल अध्यक्ष बीरबल ठाकुर और एससी सेल अध्यक्ष गोविंद अत्री सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान अधिकारियों ने परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीणों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया।

सूत्रधार कला संगम ने उपायुक्त से की नशा निवारण पर चर्चा



भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। सूत्रधार कला संगम के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को अध्यक्ष दिनेश सेन की अध्यक्षता में उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान उपायुक्त को कुल्लू की परंपरा के अनुसार टोपी और मफलर पहनाकर सम्मानित किया गया। संस्था ने अपने 49 वर्षों के कार्यों, कला-संस्कृति संरक्षण और समाजसेवा की गतिविधियों की जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल ने युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से बचाने के लिए चलाए जा रहे प्रयासों और प्रस्तावित कार्यक्रमों पर भी चर्चा की। उपायुक्त ने दशहरा उत्सव के बाद दोबारा बैठक करने और नशा निवारण सहित सामाजिक कार्यों में सहयोग का आश्वासन दिया।

गौरतलब है कि सूत्रधार कला संगम प्रदेश की अग्रणी सांस्कृतिक संस्थाओं में शामिल है। संस्था 25 राष्ट्रीय युवा उत्सवों में प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुकी है और ओमान में हिमाचली संस्कृति का प्रदर्शन भी किया है। संस्था ने राष्ट्रीय स्तर पर हारमोनियम में कांस्य, बांसुरी में रजत और लोकगीत में स्वर्ण पदक जीते हैं।

नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले भवानी सिंह को सुरक्षा देने की उठी मांग

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद



पंजाब के मानसा में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद हरियाणा में भी नशामुक्ति अभियान से जुड़े लोगों की सुरक्षा का मुद्दा उठने लगा है। विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और जनहितकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ज्ञापन भेजकर नशामुक्ति सेना के अध्यक्ष भवानी सिंह को तत्काल सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की है।

इस संबंध में संगठनों के प्रतिनिधि शुक्रवार को उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से मिले तथा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश में नशे की बढ़ती समस्या युवाओं के भविष्य, परिवारों की खुशहाली और सामाजिक व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है।

प्रतिनिधियों के अनुसार, भवानी सिंह पिछले करीब दो वर्षों से नशे के खिलाफ अभियान चलाकर युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। वह नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ भी लगातार आवाज उठाते रहे हैं। इस दौरान उन्हें कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। आरोप है कि हाल ही में कुछ नशा तस्करों ने उनके घर में घुसकर भी धमकी दी थी।

ज्ञापन में कहा गया कि पंजाब में सामाजिक कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा से जुड़ी घटना और नशा तस्करों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को मिल रही धमकियों को देखते हुए भवानी सिंह की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। संगठनों ने सरकार से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और नशे के खिलाफ काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को संरक्षण देने की मांग की। इस अवसर पर पेस्टीसाइड एसोसिएशन के प्रधान कृष्ण गिल्होत्रा, अग्रोहा विकास ट्रस्ट के प्रधान सुरेंद्र मित्तल, टाइपिस्ट एसोसिएशन के प्रधान टोनी गिल्होत्रा सहित यादविंदर सरपंच, डॉ. सुमन बजाज, विनोद अरोड़ा और अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।

सरकारी डेटा की सुरक्षा के लिए हरियाणा की 738 करोड़ की दो परियोजनाएं मंजूर

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा में सरकारी डेटा की सुरक्षा मजबूत करने, साइबर हमलों से निपटने और डिजिटल सेवाओं को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए राज्य सरकार ने 738 करोड़ रुपये की दो प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुरक्षित और आधुनिक बनाया जाएगा। साथ ही, भविष्य की तकनीकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डेटा प्रबंधन व्यवस्था को भी बेहतर किया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी संचालन समिति (आईटी प्रिज्म) की 51वीं बैठक में इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें 269 करोड़ रुपये की हरियाणा डिजिटल कवच-सुरक्षा संचालन केंद्र (एच-एसओसी) परियोजना और 469 करोड़ रुपये की हरियाणा राज्य डेटा केंद्र 2.0 (एचएसडीसी 2.0) परियोजना शामिल हैं। हरियाणा डिजिटल कवच-सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्देश्य साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। इसके माध्यम से सरकारी डिजिटल प्रणालियों पर होने वाले संभावित साइबर हमलों की निगरानी की जाएगी।

इससे साइबर खतरों की पहचान करने और उनसे निपटने की क्षमता बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सरकारी विभागों के डिजिटल नेटवर्क और महत्वपूर्ण सूचनाओं की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा राज्य डेटा केंद्र 2.0 परियोजना पर 469 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत राज्य के डेटा सेंटर का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे सरकारी डेटा के सुरक्षित प्रबंधन और डिजिटल सेवाओं की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद मिलेगी। आधुनिक तकनीकी ढांचे से सरकारी विभागों की डिजिटल जरूरतों को पूरा करने की क्षमता भी मजबूत होगी। सरकार की इन दोनों परियोजनाओं का व्यापक उद्देश्य सरकारी डेटा को सुरक्षित रखना, साइबर खतरों से निपटने की तैयारी बढ़ाना और नागरिकों को बेहतर डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी व्यवस्था को सुदृढ़ करना है।

हरियाणा में सैनी सरकार के दो साल पूरे 217 में से 70 चुनावी संकल्प किए पूरे

रोजगार, आवास और औद्योगिक विकास के वादे पूरे करने पर सरकार का जोर

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़



मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार शनिवार को अपने तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे करने जा रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा करना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती रही है। दो साल के कार्यकाल में भाजपा के 217 चुनावी संकल्पों में से 70 पूरे हो चुके हैं, जबकि 143 संकल्पों पर काम जारी है। शेष वादों को पूरा करना सरकार के लिए अगले तीन साल की प्रमुख चुनौती होगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने की तैयारी कर रहे हैं। अक्टूबर के अंत तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हरियाणा आने की संभावना है। वहीं, हरियाणा दिवस पर एक नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के गुरुकुल कुरुक्षेत्र आने का कार्यक्रम संभावित है। प्रधानमंत्री की रैली में मुख्यमंत्री सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का ब्यौरा पेश कर सकते हैं। मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करवाया गया है।

सरकार के दो साल के कार्यकाल में महिलाओं, किसानों और गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई योजनाएं प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रविधान किया गया है। सरकार का दावा है कि योजना से लाखों महिलाओं को लाभ मिला है। इसके अलावा अंत्योदय और बीपीएल परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलिंडर उपलब्ध कराने का वादा भी पूरा किया गया है।

किसानों के लिए 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की व्यवस्था को भी सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों में गिन रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में चिरायु आयुष्मान योजना के तहत परिवारों को 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा और सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस मुफ्त करने जैसे फैसलों से लोगों को राहत देने का प्रयास किया गया है।

युवाओं को रोजगार देना और गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराना सरकार के प्रमुख चुनावी वादों में शामिल रहा है। भाजपा ने दो लाख पक्की सरकारी नौकरियां देने का संकल्प लिया था। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दो साल में करीब 50 हजार सरकारी नौकरियां दी गई हैं। निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सरकार के पास अभी तीन साल का समय है।

इसी तरह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पांच लाख मकान उपलब्ध कराने के लक्ष्य के मुकाबले करीब 70 हजार मकान तैयार होने की जानकारी दी गई है। इन दोनों क्षेत्रों में सरकार को अपनी योजनाओं की गति बढ़ानी होगी।

औद्योगिक विकास को गति देने के लिए आइएमटी खरखौदा की तर्ज पर 10 आधुनिक औद्योगिक शहर विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इनके लिए जमीन जुटाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में बताई गई है। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 10 औद्योगिक नीतियां शुरू की हैं।

हरियाणा में मत्स्य पालन को बढ़ावा किसानों को मिलेगी सस्ती बिजली

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़



हरियाणा सरकार ने मछली और झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए बिजली दरों में राहत देने के साथ आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की योजना बनाई है। कृषि फीडर से जुड़े मछली और झींगा पालकों को अब 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। वहीं, गैर-कृषि फीडर से जुड़े किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ) और कृषि उद्योग श्रेणी के उपभोक्ताओं को 4.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

कृषि एवं किसान कल्याण तथा मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालकों को उच्च गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही मछली और झींगा की बिक्री के लिए अलग-अलग मंडियां स्थापित की जाएंगी। मंत्री ने बताया कि यमुनानगर, रोहतक और फरीदाबाद में छह करोड़ रुपये की लागत से तीन नई मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। इनके मार्च तक शुरू होने की संभावना है। ज्योतिसर और सांपला स्थित सरकारी मत्स्य बीज फार्मों के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण पर भी करीब 20 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हिसार और फरीदाबाद में 100 करोड़ रुपये की लागत से दो आधुनिक मछली मंडियां स्थापित करने को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल चुकी है।

डेढ़ साल की आस्था ने दुनिया को कहा अलविदा, दो बच्चों को मिली नई रोशनी

भारतेन्दु संवाददाता, महम



हरियाणा के महम में डेढ़ साल की मासूम आस्था की बुखार से मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस घर में कुछ समय पहले तक बेटी की किलकारियां गूंजती थीं, वहां अब मातम पसरा है। इस असहनीय दुख के बीच आस्था के माता-पिता ने ऐसा मानवीय फैसला लिया, जिसने दो अन्य बच्चों की जिंदगी में नई उम्मीद जगाई है। उन्होंने अपनी बेटी की आंखें दान करने का निर्णय लिया, ताकि दुनिया से विदा होने के बाद भी आस्था किसी के जीवन में रोशनी बनकर रह सके।

मासूम बेटी को खोने का दर्द किसी भी माता-पिता के लिए असहनीय होता है। ऐसे कठिन समय में भी आस्था के माता-पिता ने दूसरों की जिंदगी के बारे में सोचा। उनका यह कदम समाज के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। नेत्रदान के माध्यम से उनकी बेटी की आंखें दो जरूरतमंद बच्चों को नई दृष्टि देने में मदद करेंगी।

वे बच्चे दुनिया को देख सकेंगे और अपने जीवन में नई संभावनाओं की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। आस्था की मृत्यु से परिवार को जो गहरा आघात पहुंचा है, उसकी भरपाई संभव नहीं है। हालांकि, उसके माता-पिता के इस फैसले ने दुख की घड़ी में भी परोपकार और संवेदनशीलता का संदेश दिया है। बेटी की यादें हमेशा परिवार के साथ रहेंगी, वहीं नेत्रदान से मिलने वाली दृष्टि दो अन्य बच्चों के जीवन में खुशियों का कारण बन सकती है।

नेत्रदान को महादान कहा जाता है, क्योंकि इससे दृष्टिहीनता से जूझ रहे लोगों को देखने का अवसर मिल सकता है। आस्था के माता-पिता ने अपने फैसले से यह संदेश दिया कि किसी अपने को खोने के बाद भी दूसरों की जिंदगी संवारने का रास्ता चुना जा सकता है। आस्था के माता-पिता का यह फैसला समाज को नेत्रदान के प्रति जागरूक करेगा और जरूरतमंदों को नई उम्मीद देगा।

कोसली में 11.57 करोड़ से बनेगा आधुनिक बस स्टैंड विधायक ने किया भूमि पूजन

भारतेन्दु संवाददाता, रेवाड़ी। कोसली में शुक्रवार को विधायक अनिल यादव ने करीब 11 करोड़ 57 लाख रुपये की लागत से बनने वाले नए बस स्टैंड भवन का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। यह बस स्टैंड 18 महीने में तैयार होगा। इसके बनने से कोसली और आसपास के गांवों के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। विधायक ने बताया कि नए बस स्टैंड परिसर में यात्रियों की सुविधा के लिए छह बस बूथ, अधिकारियों के कार्यालय, बसों के ठहराव के लिए प्लेटफार्म, पार्किंग और कार्यशाला बनाई जाएगी। इसके साथ ही बस स्टैंड तक आवागमन सुगम बनाने के लिए तीन करोड़ 82 लाख रुपये की लागत से सर्विस रोड का निर्माण भी किया जाएगा। कोसली सब डिपो के लिए 92 पदों को स्वीकृति दी गई है। यहां से करीब 50 बसों का संचालन किया जाएगा। इससे क्षेत्र के लोगों को बस सेवाओं के लिए रेवाड़ी बस स्टैंड पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

फरीदाबाद में गुटबाजी पर कांग्रेस का शिकंजा, दो महिला नेताओं को नोटिस

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़



हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फरीदाबाद में पार्टी के काला दिवस कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद को गंभीरता से लेते हुए दो महिला नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इनमें बल्लभगढ़ से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी पराग शर्मा और फरीदाबाद की पूर्व जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष गजना लांबा शामिल हैं। दोनों से नोटिस मिलने के सात दिन के भीतर लिखित जवाब मांगा गया है।

प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति के अध्यक्ष धर्मपाल सिंह मलिक की ओर से जारी नोटिस में आरोप लगाया गया है कि आठ अक्टूबर को जिला कांग्रेस कमेटी, फरीदाबाद की ओर से आयोजित काला दिवस कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं के बीच विवाद हुआ। समिति ने इसे कथित अनुशासनहीनता, अमर्यादित व्यवहार और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा मामला बताया है।

नोटिस के अनुसार, कार्यक्रम का उद्देश्य शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से विरोध दर्ज कराना था, लेकिन इस दौरान कथित तौर पर झगड़े की स्थिति बनी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। समिति ने दोनों नेताओं के विवाद को पुलिस थाने तक ले जाने और मीडिया में सार्वजनिक करने पर भी आपत्ति जताई है। समिति का कहना है कि पार्टी के आंतरिक विवादों का समाधान संगठन के सक्षम नेतृत्व और निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए था।

कैथल में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, पूर्व विधायक के दो पड़पोतों समेत तीन की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, कैथल



हरियाणा के कैथल में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। करनाल रोड पर गांव नरड़ के पास तेज रफ्तार आई-20 कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मृतकों में पूर्व विधायक भगत राम वाल्मीकि के दो पड़पोते भी शामिल हैं। हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में शोक की लहर है।

मृतकों की पहचान खुराना रोड स्थित नानकपुरी कॉलोनी निवासी 29 वर्षीय अभिषेक, 27 वर्षीय रक्षत और 35 वर्षीय कृष्ण के रूप में हुई है। अभिषेक और रक्षत सगे भाई थे। दोनों अशोक कुमार के बेटे थे। हादसे में तीनों युवकों की जान चली गई। जानकारी के अनुसार, तीनों युवक आई-20 कार में सवार होकर करनाल से कैथल की तरफ आ रहे थे। शुक्रवार सुबह जब उनकी कार गांव नरड़ के पास पहुंची तो अचानक चालक गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद कार सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

दुर्घटना में तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों ने मामले की जानकारी जुटाई। हादसे में अभिषेक और रक्षत की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक ही परिवार के दो सगे भाइयों की असमय मौत की खबर से परिचितों और क्षेत्र के लोगों में भी शोक है। मृतकों में कृष्ण भी शामिल हैं, जिनकी उम्र 35 वर्ष बताई गई है। इस दुर्घटना ने एक बार फिर सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की जरूरत को रेखांकित किया है। हालांकि, हादसे के सटीक कारणों और परिस्थितियों के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

तेज रफ्तार के कारण कार का संतुलन बिगड़ने की बात सामने आई है। पुलिस हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर सकती है। क्षतिग्रस्त कार की स्थिति और घटनास्थल की परिस्थितियों से दुर्घटना की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हादसे में तीन युवकों की मौत से इलाके में शोक है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखने और सावधानी बरतने की अपील की है।

यमुनानगर में टायर फैक्ट्री में हुआ जोरदार धमाका, भीषण आग में दो लोग झुलसे

भारतेन्दु संवाददाता, यमुनानगर



हरियाणा के यमुनानगर जिले के छछरौली थाना क्षेत्र के गांव बलाचौर में शुक्रवार सुबह टायर से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में तेज धमाके के बाद भीषण आग लग गई। धमाके की आवाज करीब तीन किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे में दो लोग झुलस गए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की आठ गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए मोर्चा संभाला और काफी मशक्कत शुरू की।

फैक्ट्री में आग लगने के बाद उठती लपटों और धुएं से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज दूर तक सुनाई दी। हादसे के समय फैक्ट्री में कितने कर्मचारी मौजूद थे, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। आग लगने के कारणों का भी फिलहाल पता नहीं चल पाया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, धमाके के बाद फैक्ट्री में आग तेजी से फैल गई, जिसके चलते दमकल विभाग को आग बुझाने के लिए कई गाड़ियां लगानी पड़ीं।

घटना की जानकारी मिलने पर संबंधित अधिकारी और पुलिस भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। झुलसे हुए दोनों लोगों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाए जाने की जानकारी है। उनकी हालत के बारे में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। फलहाल दमकल विभाग की टीमें आग पर काबू पाने में जुटी हैं। प्रशासन की ओर से घटना के कारणों और नुकसान का आकलन किया जाएगा। फैक्ट्री में आग लगने के बाद उठती लपटों और धुएं से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के लिए मोर्चा संभाला।

'एक मिनट में इंस्पेक्टरी निकाल दूंगा' रिपोर्ट न मिलने पर भड़के अनिल विज

भारतेन्दु संवाददाता, अंबाला। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने वीरवार को अंबाला छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित जनसुनवाई के दौरान बिजली निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई। करीब चार घंटे चली जनसुनवाई में उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। जगगी सिटी सेंटर में अनधिकृत बिजली आपूर्ति का मामला सामने आने पर विज ने बिजली निगम के अधिकारियों से जवाब मांगा। मामले की निरीक्षण रिपोर्ट तीन सप्ताह बाद भी नहीं मिलने पर उन्होंने बिजली निगम के एसई से नाराजगी जताई। रिपोर्ट में देरी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा, 'रिपोर्ट पैदल आ रही है या गाड़ी में?' इसके बाद मंत्री ने फोन पर चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से संपर्क कर मामले में जवाब तलब किया और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट समय पर उपलब्ध नहीं करवाए जाने से नाराज विज ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित एक्सईएन के तबादले के आदेश भी दिए। जनसुनवाई के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और मामलों की जांच में अनावश्यक देरी न हो। उन्होंने बिजली आपूर्ति से जुड़ी अनियमितताओं पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जनसुनवाई में अनधिकृत स्कूल दाखिलों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मामलों पर भी कार्रवाई करने को कहा गया। विकास कार्यों में देरी को लेकर नगर परिषद के अधिकारियों को भी फटकार लगाई गई। विज ने संबंधित अधिकारियों से लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

न्यूज ब्रीफ

हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दलजीत सिसाय की उम्रकैद की सजा रद्द

भारतेन्दु संवाददाता, हिसार। हरियाणा में वर्ष 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में दलजीत सिहाग सिसाय जेल से रिहा हो गया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिलने और उम्रकैद की सजा रद्द होने के बाद उसकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ। दलजीत को लेने के लिए जाट समाज के लोग झज्जर जेल पहुंचे और रिहाई के बाद उसका स्वागत किया। हिंसा के दौरान हांसी में मिंटू की हत्या हुई थी। दलजीत के वकील जगपाल ने रिहाई को संघर्ष की जीत बताया। दलजीत की रिहाई के लिए उसकी पत्नी अनीता सिसाय ने लंबी कानूनी और सामाजिक लड़ाई लड़ी। वह विभिन्न खाप पंचायतों और चबूतरों पर जाकर समर्थन जुटाती रहीं। 20 नवंबर 2025 को हांसी पुलिस ने तत्कालीन डीजीपी ओपी सिंह के आदेश पर दलजीत को बेड़ियां पहनाकर बाजार में घुमाया था। पुलिस के अनुसार, वह फिरौती, लूटपाट, जानलेवा हमला और हत्या के प्रयास समेत 61 मामलों में वांछित रहा था।

बहादुरगढ़ में भाजपा नेता की ब्रेजा कार चोरी, 10 मिनट में वारदात

भारतेन्दु संवाददाता, झज्जर। हरियाणा के बहादुरगढ़ में चोरों ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष नरेश भारद्वाज की ब्रेजा कार चोरी कर ली। वारदात को तीन युवकों ने महज 10 मिनट में अंजाम दिया। घटना के समय कार घर के बाहर खड़ी थी। चोर क्रेटा कार में सवार होकर आए और मौका पाकर ब्रेजा लेकर फरार हो गए। कार चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में तीन युवकों को कार चोरी कर ले जाते हुए देखा जा सकता है। घटना के सामने आने के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने और चोरी हुई कार का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

गुरुग्राम में दिल्ली के गब्बर की मौत परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली के मांडी गांव निवासी 40 वर्षीय गब्बर सिंह की गुरुग्राम में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह करीब 13 दिन पहले सड़क पर घायल अवस्था में मिला था। उसकी मौत के बाद परिजनों ने घटना को सामान्य सड़क हादसा मानने पर सवाल उठाए हैं। पत्नी और भाई का आरोप है कि गब्बर की मौत के पीछे कोई साजिश हो सकती है। परिजनों के अनुसार, गब्बर के सिर के पिछले हिस्से में चोट लगी थी। वहीं, उसकी बाइक पर खरोंच तक नहीं थी। इसी आधार पर परिवार हादसे की कहानी पर संदेह जता रहा है। गब्बर के भाई का कहना है कि यदि बाइक से दुर्घटना हुई होती, तो वाहन पर भी नुकसान के निशान दिखाई देने चाहिए थे। हालांकि, इस संबंध में पुलिस की जांच और मेडिकल रिपोर्ट से ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। जानकारी के अनुसार, सड़क पर घायल मिलने के बाद गब्बर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिवार को उम्मीद थी कि वह ठीक होकर घर लौट आएगा, लेकिन 13 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद उसने दम तोड़ दिया। गब्बर की मौत से परिवार में शोक का माहौल है। परिजनों ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वह किन परिस्थितियों में घायल हुआ था।

फरीदाबाद में रिश्तों का कत्ल, पत्नी, बेटी और प्रेमी पर पति की हत्या का आरोप

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदाबाद



हरियाणा के फरीदाबाद में थाना पल्ला क्षेत्र की श्याम कॉलोनी में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान गोपाल के रूप में हुई है। उसके परिजनों ने हत्या का आरोप उसकी पत्नी काजल, बेटी और पत्नी के कथित प्रेमी योगेंद्र पर लगाया है। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, गोपाल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के गांव कुंवरपुर का निवासी था। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ फरीदाबाद की श्याम कॉलोनी पार्ट-एक की गली नंबर पांच स्थित मकान नंबर 79 के एक कमरे में किराये पर रहता था। शुक्रवार सुबह उसकी हत्या की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, गोपाल रात को खाना खाने के बाद सो गया था। पड़ोसी ने बताया कि रात के दौरान उसे किसी तरह की असामान्य आवाज सुनाई नहीं दी। सुबह घटना का पता चलने पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए।

मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि गोपाल की पत्नी काजल और योगेंद्र के बीच पिछले करीब तीन वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों को आशंका है कि इसी संबंध के चलते गोपाल की हत्या की गई। हालांकि, हत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा।

परिजनों के अनुसार, गोपाल के फोन से उसकी पत्नी ने उन्हें उसकी तबीयत खराब होने की सूचना दी थी और तुरंत फरीदाबाद पहुंचने के लिए कहा था। जब परिवार के सदस्य घर पहुंचे तो गोपाल का शव जमीन पर पड़ा था और उसकी गर्दन कटी हुई थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तीनों आरोपितों को हिरासत में लिया है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और हत्या में इस्तेमाल हथियार सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर सड़क नेटवर्क मजबूत करने की तैयारी

हरियाणा के पांच शहरों में 9700 करोड़ से बनेंगे बाईपास

भारतेन्दु संवाददाता, पानीपत



एआई चित्र

- पांच शहरों में यातायात का दबाव कम करने पर रहेगा जोर

हरियाणा में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और शहरों के भीतर वाहनों का दबाव कम करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के पांच शहरों में करीब 9700 करोड़ रुपये की लागत से बाईपास और बाहरी रिंग रोड विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार, कुरुक्षेत्र-लाडवा, नारनौल, जींद और सोहना-पलवल बाईपास परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर संबंधित शहरों में यातायात को सुगम बनाने और लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा देने में मदद मिलेगी।

सरकार का उद्देश्य शहरों के अंदर से गुजरने वाले वाहनों का दबाव कम करना है। बाईपास और रिंग रोड बनने से शहरों के बीच से होकर गुजरने वाले यातायात को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो सकेंगे। इससे प्रमुख सड़कों पर वाहनों की भीड़ कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही, स्थानीय लोगों को रोजाना आवागमन के दौरान होने वाली परेशानियों से राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 12 सितंबर को चंडीगढ़ में आयोजित बैठक में प्रदेश के एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और कस्बों के बाहर रिंग रोड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित करने की योजना पर चर्चा की थी। बैठक में सड़क संपर्क को मजबूत बनाने और शहरी क्षेत्रों में बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने के उपायों पर विचार किया गया।

सरकार की योजना के तहत सड़क ढांचे के विस्तार के साथ शहरों के बाहर वैकल्पिक मार्ग तैयार करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे शहरी क्षेत्रों में यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप राज्य की वित्तीय भागीदारी का मॉडल तैयार करने पर भी विचार किया गया है। इस संबंध में वित्त विभाग, लोक निर्माण विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों की तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी वित्तीय भागीदारी से जुड़े पहलुओं पर काम करेगी।

करीब 9700 करोड़ रुपये की इन परियोजनाओं को हरियाणा के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इनके माध्यम से पांच शहरों में यातायात का दबाव कम करने और आवागमन को अधिक सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन परियोजनाओं से प्रदेश में सड़क संपर्क को बढ़ावा मिलने के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है। बेहतर सड़क व्यवस्था से यात्रियों और मालवाहक वाहनों को लाभ मिल सकता है। सरकार का प्रयास है कि बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या को देखते हुए शहरों के बाहर मजबूत सड़क नेटवर्क तैयार किया जाए, ताकि भविष्य में भी यातायात संबंधी समस्याओं को कम किया जा सके।

न्यूज ब्रीफ

दिल्ली पुलिस का अभिजीत दीपके को 14 पॉइंट का नोटिस, तिरंगा यात्रा नहीं निकालने की अपील



एजेंसी ,नई दिल्ली दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके को कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर 14 बिंदुओं वाला नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 16 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर दिया गया है। पुलिस ने अभिजीत दीपके से तिरंगा यात्रा नहीं निकालने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि निर्देशों का उल्लंघन करते हुए यात्रा निकाली गई, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों को परेशानी से बचाने के लिए सतर्क है। प्रदर्शन के कारण यातायात, व्यापारिक गतिविधियों और रोजगार पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर भी चिंता जताई गई है। फिलहाल, पुलिस के नोटिस के बाद सबकी नजर अभिजीत दीपके और पार्टी के अगले कदम पर है।

आगराः खेरिया मोड़-ईदगाह रेल ओवरब्रिज 90 दिन रहेगा बंद, हजारों लोगों की बढ़ेगी परेशानी



खेरिया मोड़ ईदगाह रेलवे ओवर ब्रिज।

एजेंसी, नई दिल्ली आगराः खेरिया मोड़-ईदगाह रेल ओवरब्रिज शुक्रवार सुबह से 90 दिनों के लिए बंद किया जा रहा है। पुल की 50 साल की निर्धारित आयु पूरी होने और जर्जर स्थिति को देखते हुए इसका नवनिर्माण कराया जाएगा। इसके चलते रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वैकल्पिक मार्ग से गुजरेंगे वाहन पुल बंद रहने के दौरान यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है। वाहनों को अर्जुन नगर तिराहे से बारह खंभा डबल फाटक मार्ग स्थित रेलवे फाटक होकर निकाला जाएगा। रेल ओवरब्रिज बंद होने का असर खेरिया एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों पर भी पड़ सकता है। वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने से लोगों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ सकती है। ऐसे में यात्रियों को घर से समय से पहले निकलने और निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी की तकनीशियन परीक्षा की आंसर की, 22 अक्टूबर तक मौका

एजेंसी, नई दिल्ली रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने तकनीशियन भर्ती परीक्षा की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन 02/2026) के तहत आयोजित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी उत्तर कुंजी और प्रश्न-प्रतिक्रिया पत्रक देख सकते हैं। बोर्ड ने तकनीशियन ग्रेड-1 (सिग्नल) और तकनीशियन ग्रेड-3 के लिए अलग-अलग सूचनाएं जारी की हैं। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी में किसी उत्तर पर असहमति होने पर 22 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रयागराज में 469 पदों पर भर्ती आरआरबी **प्रयागराज में तकनीशियन के कुल 469** पदों पर भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्तर कुंजी की जांच कर लें और जरूरत पड़ने पर आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार आपत्ति दर्ज करें। अंतिम तिथि के बाद आपत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती है। रेलवे तकनीशियन भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, प्रयागराज में 469 पदों पर भर्ती। अभ्यर्थी 22 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

त्योहारों पर रेल यात्रियों को बड़ा तोहफा, नई दिल्ली और पटना के बीच चलेगी विशेष वंदे भारत एक्सप्रेस

एजेंसी, नई दिल्ली



दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक सफर उपलब्ध कराने के लिए नई दिल्ली और पटना जंक्शन के बीच विशेष वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा शुरू की गई है। इस ट्रेन के संचालन से त्योहारों पर घर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। **16 अक्टूबर से 17 नवंबर तक होगा संचालन** रेलवे के अनुसार, यह विशेष वंदे भारत एक्सप्रेस 16 अक्टूबर 2026 से 17 नवंबर 2026 तक संचालित की जाएगी।

ट्रेन सप्ताह में तीन दिन चलेगी। इस सेवा का उद्देश्य त्योहारों के दौरान दिल्ली से बिहार जाने वाले यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को संभालना और उनकी यात्रा को आसान बनाना है। दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाने के लिए घर जाते हैं। ऐसे में नियमित ट्रेनों में सीटों की मांग बढ़ जाती है और यात्रियों को टिकट मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

विशेष ट्रेन चलाए जाने से यात्रियों को यात्रा का एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।नई दिल्ली और पटना जंक्शन के बीच विशेष वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा शुरू होने से त्योहारों के दौरान आवागमन को सुगम बनाने में मदद मिल सकती है। तेज गति और आधुनिक सुविधाओं के लिए पहचानी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव देने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।

दिल्ली में प्रदर्शन से कारोबार को नुकसान हुआ तो मिलेगा मुआवजा ? सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने छोटे व्यापारियों और दिहाड़ी मजदूरों की आजीविका पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि यदि प्रदर्शन के कारण व्यापारियों के कारोबार या मजदूरों के रोजगार को नुकसान पहुंचता है, तो वह मुआवजे के सवाल पर विचार कर सकती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अपने संवैधानिक अपकृत्य क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल कर सकता है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन को लेकर चिंता जताई गई थी। अदालत ने उम्मीद जताई कि सभी पक्ष समझदारी से काम लेंगे और प्रदर्शनकारियों, व्यापारियों तथा प्रशासन के हितों के बीच संतुलन बनाए रखेंगे।सुनवाई के दौरान व्यापारियों के एक संगठन की ओर से पेश अधिवक्ता जय अनंत देहाद्रई ने प्रदर्शन के कारण कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई। इस पर न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि यदि प्रदर्शन से व्यापार को नुकसान होता है या व्यापारियों के अधिकारों का गैरकानूनी तरीके से उल्लंघन होता है, तो अदालत अपने संवैधानिक अपकृत्य क्षेत्राधिकार के तहत शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति सामने आने पर अदालत इस मुद्दे पर विचार करेगी। हालांकि, यह टिप्पणी मुआवजा दिए जाने का अंतिम आदेश नहीं है। मुआवजे पर फैसला परिस्थितियों और संबंधित तथ्यों के आकलन के बाद ही लिया जाएगा।जब व्यापारियों के वकील ने याचिका में उठाई गई विभिन्न चिंताओं पर जोर दिया, तो न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि मामले में प्रदर्शनकारियों, व्यापारियों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के दावों पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए।



दिल्ली प्रदर्शन से व्यापारियों को नुकसान पर मुआवजे पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कोई प्रदर्शन करना चाहता है, कोई मूंगफली बेचकर अपनी आजीविका कमाना चाहता है और कोई कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभा रहा है। अदालत के सामने इन सभी पक्षों के हित हैं, इसलिए मामले को संतुलित तरीके से देखना जरूरी है। पीठ ने संकेत दिया कि मामले पर एक सप्ताह बाद फिर सुनवाई की जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि छोटे दुकानदारों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। त्योहारों के दौरान कारोबार से होने वाली कमाई कई छोटे व्यापारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है।

मेरठ में चर्चित हत्याकांड पर बड़ा फैसला, पत्नी और प्रेमी को फांसी की सजा



एजेंसी, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के बहसूमा क्षेत्र में हुए अमित कश्यप हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। दोनों को हत्या का दोषी करार दिया गया। इस मामले में आरोप था कि अमित की हत्या करने के बाद घटना को सांप के डसने से हुई मौत का रूप देने की कोशिश की गई थी।

सांप के डसने से मौत दिखाने की कोशिश जानकारी के अनुसार, अमित कश्यप की मौत का मामला शुरुआत में सांप के डसने से हुई मृत्यु के रूप में सामने आया था। हालांकि, जांच के दौरान मामले में हत्या की आशंका और अन्य तथ्य सामने आए। इसके बाद पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, जिसमें अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप की भूमिका सामने आई।

अभियोजन पक्ष ने अदालत में दोनों के खिलाफ साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। मामले की सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को हत्या का दोषी माना। **86 तारीखों के बाद आया फैसला** इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज, कोर्ट संख्या-12 में हुई। करीब डेढ़ साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के दौरान कुल 86 तारीखें लगीं। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों की गवाही कराई गई, जिन्हें मामले में महत्वपूर्ण माना गया।

रेवाड़ी में दिवाली पर निर्बाध बिजली देने की तैयारी, शनिवार को दो पावर हाउस में मरम्मत

एजेंसी, नई दिल्ली

दिवाली के त्योहार से पहले बिजली निगम ने निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। त्योहार के दौरान बिजली का लोड बढ़ने से होने वाले फॉल्ट और पावर कट की समस्या से बचने के लिए शनिवार को जिले के दो बड़े पावर हाउस में मरम्मत कार्य किया जाएगा। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से दिवाली से पहले यह वार्षिक रखरखाव कार्य कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य त्योहार के दौरान बिजली व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। **त्योहार पर बढ़ जाता है बिजली का लोड** दिवाली के दौरान घरों, दुकानों और बाजारों में सजावटी लड़ियां, फैंसी लाइटें और अन्य विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। इससे बिजली की मांग में बढ़ोतरी होती है।

ग्रेटर नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1.84 लाख के नकली नोटों के साथ गिरोह पकड़ा

एजेंसी, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने बाजार में जाली नोट खपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 1 लाख 84 हजार रुपये के नकली नोट, एक असली नोट और वारदात में इस्तेमाल की गई कार बरामद की गई है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के नेटवर्क और जाली नोटों के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है।

920 जाली नोट बरामद

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के पास से 200-200 रुपये के कुल 920 जाली नोट बरामद हुए हैं। इन सभी नोटों की कुल कीमत 1,84,000 रुपये बताई गई है। इसके अलावा आरोपियों के कब्जे से अपराध से संबंधित 1,000 रुपये का असली नोट भी मिला है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों द्वारा



चार आरोपी गिरफ्तार। एआई जनरेटेड

इन नकली नोटों को बाजार में चलाने की कोशिश की जा रही थी। समय रहते कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को पकड़ लिया और उनके पास मौजूद नकली नोटों को जब्त कर लिया। **बिना नंबर प्लेट की कार भी बरामद**

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद की है। यह कार बिना नंबर प्लेट के थी और कथित तौर पर घटना में इस्तेमाल की गई थी। पुलिस वाहन के इस्तेमाल और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस की इस कार्रवाई को जाली नोटों के कारोबार पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नकली नोटों को बाजार में खपाने से आम नागरिकों और व्यापारियों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। ऐसे में इस तरह के गिरोहों पर कार्रवाई जरूरी है। चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि जाली नोट कहां से लाए गए थे और इन्हें किन बाजारों में चलाने की योजना थी।

ग्रेटर नोएडा में बारिश का कहर, ईकोटेक-12 में गिरा लाखों से सजा रामलीला का मंच

एजेंसी, नई दिल्ली



ईकोटेक-12 स्थित रामलीला मैदान में गिरा मंच

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खराब मौसम का असर धार्मिक आयोजनों पर भी देखने को मिला। ग्रेटर नोएडा में तेज हवा और बारिश के कारण रामलीला के मंचन में बाधा आई। ईकोटेक-12 में रामलीला के लिए तैयार किया गया भव्य मंच तेज हवा के चलते गिर गया, जबकि सेक्टर पाई में जलभराव के कारण रामलीला का आयोजन स्थगित करना पड़ा। अचानक मौसम बिगड़ने से आयोजकों की तैयारियां प्रभावित हुईं और रामलीला देखने पहुंचे दर्शकों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। ईकोटेक-12 में रामलीला के मंचन के लिए लाखों रुपये की लागत से आकर्षक मंच सजाया गया था।

आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई थीं और दर्शकों को रामलीला देखने की उम्मीद थी। लेकिन तेज हवा और बारिश ने कार्यक्रम में खलल डाल दिया। खराब मौसम के कारण मंच की सजावट गिर गई, जिससे आयोजन प्रभावित हुआ। मंच गिरने की घटना से आयोजकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

रामलीला के मंचन के लिए की गई तैयारियों पर मौसम की मार पड़ने से कार्यक्रम को सुचारु रूप से आयोजित करना मुश्किल हो गया। दर्शकों को भी कार्यक्रम देखे बिना वापस लौटना पड़ा।ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पाई में भी बारिश के कारण स्थिति प्रभावित हुई। यहां जलभराव होने से रामलीला का आयोजन करना संभव नहीं हो सका। ऐसे में आयोजकों को कार्यक्रम स्थगित करने का फैसला लेना पड़ा। बारिश और तेज हवाओं के कारण आयोजन स्थल पर व्यवस्थाएं प्रभावित होने से रामलीला देखने आने वाले लोगों को परेशानी हुई।

धार्मिक आयोजन के लिए पहुंचने वाले दर्शकों को निराश होकर लौटना पड़ा। खराब मौसम के कारण प्रभावित हुए कार्यक्रमों को लेकर आयोजकों की ओर से आगे की तैयारियां की जा रही हैं।

आगरा में पैंटून पुल को लेकर व्यापारियों का गुस्सा, बाजार बंद कर उठाई आवाज

एजेंसी, नई दिल्ली

पिनाहट (आगरा): चंबल नदी पर पैंटून पुल निर्धारित समय तक चालू नहीं होने से नाराज व्यापारियों ने शुक्रवार सुबह बाजार बंद कर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुल का निर्माण 15 अक्टूबर तक पूरा कर इसे चालू किया जाना था, लेकिन तय समय सीमा बीतने के बाद भी पुल शुरू नहीं हो सका। इससे स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी है। उनका कहना है कि पुल चालू नहीं होने से व्यापार प्रभावित हो रहा है और लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। **पुल चालू नहीं होने से बढ़ी परेशानी** पिनाहट में चंबल नदी पर बना पैंटून पुल स्थानीय लोगों और व्यापारियों के लिए आवागमन का महत्वपूर्ण साधन है।

निर्धारित समय पर पुल चालू नहीं होने से क्षेत्र के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। व्यापारियों के मुताबिक, पुल के अभाव में ग्राहकों और कारोबारियों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है, जिसका सीधा असर बाजार के कारोबार पर पड़ रहा है।पैंटून पुल चालू नहीं होने के साथ ही स्टीमर सेवा भी बंद है। ऐसे में चंबल नदी के आर-पार आने-जाने वाले लोगों के सामने आवागमन की समस्या गंभीर हो गई है। स्थानीय लोगों को आवाजाही के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि पुल और स्टीमर सेवा बंद रहने से दैनिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं।

निर्धारित तारीख बीतने के बाद भी पुल चालू नहीं होने से नाराज व्यापारियों ने शुक्रवार सुबह बाजार बंद कर विरोध जताया। उन्होंने धरना देकर जल्द से जल्द पैंटून पुल चालू करने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि पुल शुरू होने से क्षेत्र में आवागमन सामान्य हो सकेगा और कारोबार को राहत मिलेगी।

प्रयागराज में अंतरराष्ट्रीय सेमिनार, विशेषज्ञों ने आधुनिक तकनीकों पर किया मंथन

एजेंसी, नई दिल्ली

इमारतों, पुलों और फ्लाईओवरों की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है। किसी निर्माण में दरार दिखाई देने के बाद मरम्मत करने के बजाय, यदि तकनीक पहले ही उसके कमजोर होने का संकेत दे दे, तो बड़े हादसों को रोकने में मदद मिल सकती है। इसी उद्देश्य से भविष्य की तकनीकों पर चर्चा करने के लिए देश-विदेश के विशेषज्ञ प्रयागराज में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में जुटे हैं।

सम्मेलन में विशेषज्ञों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग और आधुनिक निगरानी प्रणालियों की मदद से इमारतों तथा अन्य संरचनाओं की स्थिति का आकलन करने पर चर्चा की। इन तकनीकों के माध्यम से निर्माण में होने वाले छोटे बदलावों और संभावित



एमएनएनआईटी में अंतरराष्ट्रीय सेमिनार, स्मारिका विमोचन। भारतेन्दु

कमजोरियों का समय रहते पता लगाया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, एआई और मशीन लर्निंग आधारित प्रणालियां निगरानी के दौरान जुटाए गए आंकड़ों का विश्लेषण कर सकती हैं। इससे यह समझने में मदद मिल सकती है कि किसी इमारत, पुल या फ्लाईओवर की संरचना में असामान्य बदलाव हो रहे हैं या नहीं।

समय रहते ऐसे संकेत मिलने पर संबंधित विभाग आवश्यक जांच और मरम्मत की कार्रवाई कर सकते हैं। सम्मेलन में लेजर आधारित गैर-संपर्क निगरानी तकनीक भी चर्चा का महत्वपूर्ण विषय रही। इस तकनीक की मदद से किसी संरचना को सीधे छुए बिना उसकी स्थिति में होने वाले बदलावों का आकलन किया जा सकता है। इस तरह की निगरानी से उन संरचनाओं की जांच में सहायता मिल सकती है, जहां पारंपरिक तरीकों से निरीक्षण करना कठिन या जोखिम भरा होता है।

दिल्ली में वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए विशेष अभियान, पोलिंग बूथों पर लगेंगे शिविर

एजेंसी, नई दिल्ली



मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जनरेटेड

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय की ओर से मतदाता सूचियों को अपडेट करने और नए मतदाताओं का पंजीकरण करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज न होने के कारण अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए। इसके तहत दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां नागरिक मतदाता सूची से संबंधित आवश्यक कार्य करवा सकेंगे।

इस विशेष अभियान के अंतर्गत नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने, पहले से दर्ज विवरण में सुधार करवाने और सूची से संबंधित अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने का अवसर मिलेगा। निर्वाचन कार्यालय की इस पहल से उन लोगों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है, जो किसी कारणवश अब तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाए हैं या जिनकी जानकारी में संशोधन की आवश्यकता है। अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और समावेशी बनाना है, ताकि सभी पात्र नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें। इसके लिए नागरिकों को निर्धारित शिविरों में पहुंचकर अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं के अनुसार आवेदन करने की सुविधा दी जा रही है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है, जहां हाल के समय में पुनर्विकास या विध्वंस के कारण लोगों को प्रभावित होना पड़ा है। इनमें बेला एस्टेट, जेलर वाला बाग, नरेला, बवाना, मंगोलपुरी और वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र जैसे इलाके शामिल हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए विशेष शिविर लगाए गए हैं, ताकि मतदाता सूची से जुड़ी उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। पुनर्विकास और विध्वंस के कारण प्रभावित परिवारों के लिए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज रखना या आवश्यक सुधार करवाना महत्वपूर्ण है। ऐसे में यह अभियान पात्र नागरिकों तक निर्वाचन संबंधी सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, दावों और आपत्तियों की पूरी अवधि के दौरान इन विशेष शिविरों का आयोजन लगातार किया जाता रहेगा।

दिल्ली में 'लहरा दो तिरंगा' पर घमासान, सेंट्रल पार्क बंद; 6,000 से ज्यादा जवान तैनात

सेंट्रल पार्क में नहीं होगा 'लहरा दो तिरंगा' कार्यक्रम, पुलिस ने रखी नई शर्त

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित 'लहरा दो तिरंगा' कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पार्टी ने अपने दो प्रमुख नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के विरोध में इस कार्यक्रम की घोषणा की है। पार्टी शुक्रवार को कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ जुटने की तैयारी कर रही थी। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस कार्यक्रम के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके बावजूद पार्टी के आंदोलनकारी कार्यक्रम आयोजित करने की मांग पर अड़े हुए हैं। **सेंट्रल पार्क दो दिन के लिए बंद** सीजेपी ने अपने समर्थकों से 'लहरा दो तिरंगा' कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की थी।

इसके मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर को बंद रखने का निर्णय लिया है। वहीं, दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस और मध्य दिल्ली के आसपास के इलाकों में



कनॉट प्लेस में सुरक्षा के भारी इंतजाम।

6,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। पुलिस और प्रशासन का उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, बाजारों में सामान्य गतिविधियों को प्रभावित होने से बचाना और आम नागरिकों को किसी तरह की परेशानी से दूर रखना है। इसी वजह से कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।दिल्ली पुलिस की जनसंपर्क अधिकारी और डीसीपी नेहा यादव के अनुसार, पुलिस ने किसी बड़े मार्च के आयोजन की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने बताया कि कनॉट प्लेस और आसपास के क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है।

नेहा यादव ने यह भी कहा कि एनडीएमसी पहले ही सेंट्रल पार्क को दो दिनों तक बंद रखने की सूचना दे चुकी है। पार्क में किसी भी तरह के अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए एनडीएमसी ने पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, व्यापारिक और बाजार संगठनों ने भी दुकानों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की मांग की है।हालांकि, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों की मांग को खारिज करने के बजाय सीमित विकल्प पर विचार कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, कुछ चुनिंदा प्रदर्शनकारियों को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर मार्च निकालने की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए प्रदर्शनकारियों की संख्या और स्थान को लेकर शर्तें रखी जा सकती हैं।

मेरठः एक करोड़ की लागत से बनी नई सड़क, जाम और हादसों से मिलेगी राहत

एजेंसी, नई दिल्ली

पल्लवपुरम में स्थानीय निवासियों और व्यापारियों को जर्जर सड़क से राहत दिलाने के लिए करीब एक करोड़ रुपये की लागत से नई सड़क का निर्माण कराया गया है। लगभग 900 मीटर लंबी यह तारकोल की सड़क पल्लवपुरम फेस-दो और फेस-वन को जोड़ती है। इसके बनने से लोगों का आवागमन आसान होने और सड़क पर हादसों की आशंका कम होने की उम्मीद है। यह सड़क पल्हैड़ा पैंठ बाजार चौक से एलआइसी कार्यालय तक बनाई गई है। पल्लवपुरम फेस-दो के डिवाइडर मोड़ से फेस-वन की ओर जाने वाला यह मार्ग पल्हैड़ा की मुख्य सड़क को भी जोड़ता है। यहां साप्ताहिक पैंठ बाजार लगने के कारण लोगों और व्यापारियों की आवाजाही बनी रहती है। स्थानीय लोगों के अनुसार, सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में थी। जगह-जगह गड्ढे होने और बजरी बिखरी रहने से वाहन चालकों को परेशानी होती थी। फिसलन के कारण कई दोपहिया वाहन चालक और साइकिल सवार चोटिल भी हो चुके थे। कुछ महीने पहले सड़क के एक ओर नाले का निर्माण कराया गया था।

न्यूज ब्रीफ

नवनियुक्त पार्षद सन्नी ने मुख्यमंत्री का जताया आभार, कांग्रेस महासचिव दीपक से की मुलाकात



भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। नवनियुक्त नगर निगम पार्षद श्री सन्नी ईपन ने पार्षद मनोनीत किए जाने पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसके लिए वे उनके आभारी हैं और जनसेवा की भावना से कार्य करते हुए जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। इस अवसर पर सन्नी ईपन ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव दीपक शर्मा से भी मुलाकात की और उनका आभार व्यक्त किया। कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे सन्नी ईपन का नवनियुक्त पार्षद बनने पर स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस दौरान उन्हें शॉल, टोपी और मफलर पहनाकर सम्मानित किया गया। दीपक शर्मा ने सन्नी ईपन को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि वे नगर निगम क्षेत्र के विकास, जनसमस्याओं के समाधान और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देंगे तथा अपनी जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ निर्वहन करेंगे।

धर्माणी करेंगे बाल विज्ञान कांग्रेस का समापन

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। नगर व ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी 17 अक्तूबर को जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस के समापन समारोह में मुख्यातिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दधोल में सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मंत्री बाल विज्ञान कांग्रेस के समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यह जानकारी शुक्रवार को एक सरकारी प्रवक्ता ने दी।

बिलासपुर में आर्ट ऑफ लिविंग ने करवाया दुर्गा होम

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। शारदीय नवरात्र के अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की ओर से बिलासपुर में नवरात्र पूजन व दुर्गा होम (हवन) का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की आराधना कर सुख-समृद्धि, शांति और जनकल्याण की कामना की। अनुष्ठान स्वामी आदित्य की देखरेख में पंडित अंशु और अरुण के सहयोग से विधिवत संपन्न हुआ। जिला मीडिया प्रभारी अरुण डोगरा रीतू ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य ध्यान, मंत्रोच्चार और हवन के माध्यम से समाज में सकारात्मक चेतना तथा मानसिक शांति का प्रसार करना है। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रचना मेहता, शिक्षक विकास भट्टा, सदर विधायक त्रिलोक जमवाल की पत्नी जोगेंद्रा जमवाल, सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक मीरा भोगल सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे।

ततापानी में जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस शुरू, 526 विद्यार्थी दिखाएंगे प्रतिभा



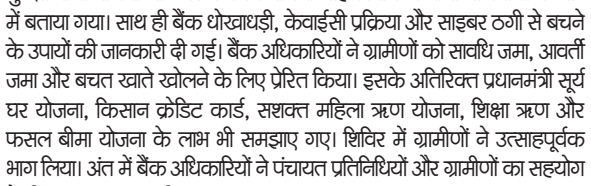
भारतेन्दु संवाददाता, सरकाघाट। एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल, अनंत नगर, ततापानी में शुक्रवार को जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस-2026 का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव पवन ठाकुर ने किया। दो दिवसीय आयोजन में मंडी जिले के विभिन्न विद्यालयों के लगभग 526 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार, तार्किक चिंतन और अनुसंधान की भावना विकसित करना है। प्रतियोगिता में विद्यार्थी विज्ञान प्रश्नोत्तरी, वैज्ञानिक परियोजनाओं और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। मुख्यातिथि पवन ठाकुर ने विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बनाए रखने और नवाचार एवं अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और वैज्ञानिक सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालय के चेयरमैन सुरेंद्र कुमार राणा, प्रबंध निदेशक प्रेम चंद ठाकुर और प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार गौतम ने आयोजन को गौरवपूर्ण अवसर बताया। बाल विज्ञान कांग्रेस का समापन 17 अक्तूबर को होगा। समापन समारोह में मंडी के उच्च शिक्षा उपनिदेशक डॉ. सुनील दत्त ठाकुर मुख्यातिथि होंगे।

मां बज्रेश्वरी मंदिर में छठे नवरात्र पर 6700 श्रद्धालुओं ने नवाया शीश



आशीष दमीर, भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। शक्तिपीठ मां बज्रेश्वरी मंदिर कांगड़ा में शारदीय नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। छठे नवरात्र पर लगभग 6700 श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में शीश नवाकर सुख-समृद्धि की कामना की। वहीं, पांचवें नवरात्र पर श्रद्धालुओं ने मंदिर में 4,50,244 रुपए का चढ़ावा अर्पित किया। मंदिर अधिकारी प्रकाश चंद ने बताया कि एसडीएम कांगड़ा डॉ. अंजलि गर्ग के दिशा-निर्देशों के अनुसार श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से दर्शन करवाए जा रहे हैं। मंदिर परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि नवरात्र के अवसर पर मंदिर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। रोशनी से मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। मां के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय बना हुआ है। मंदिर प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

एफपीओ और स्वयं सहायता समूहों को मजबूत कर बढ़ाएंगे ग्रामीणों की आय



भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-द्वितीय (एचपीसीडीपी-द्वितीय) के तहत किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) तथा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सशक्त बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला परियोजना प्रबंधन इकाई मंडी ने 14 और 15 अक्तूबर को केहड़, सियांह री कुहल तथा कंसा खड्ड-प्लाहोटा में बैठकें आयोजित कीं। बैठकों में अधिकारियों ने किसानों को सामूहिक विपणन, बेहतर बाजार संपर्क और पारदर्शी प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित किया। एफपीओ की कार्यप्रणाली, संगठनात्मक मजबूती और निदेशक मंडल की जिम्मेदारियों पर भी चर्चा की गई। वहीं, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को उत्पादों की गुणवत्ता, आकर्षक पैकेजिंग और बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि संगठित विपणन और महिला उद्यमिता से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण आजीविका को मजबूती मिलेगी।

पट्टा गांव में सहकारी बैंक ने ग्रामीणों को वित्तीय योजनाओं के प्रति किया जागरूक

भारतेन्दु संवाददाता, सरकाघाट। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की चंदेश शाखा ने नाबार्ड के सौजन्य से ग्राम पंचायत गहर के पट्टा गांव में वित्तीय जागरूकता शिविर आयोजित किया। इसमें शाखा प्रबंधक कुलदीप कुमार और बैंक कर्मचारी नंद लाल ने ग्रामीणों को बैंक की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में सपनों का संचय, बचत खाता, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना सहित विभिन्न बीमा योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही बैंक धोखाधड़ी, केवाईसी प्रक्रिया और साइबर ठगी से बचने के उपायों की जानकारी दी गई। बैंक अधिकारियों ने ग्रामीणों को सावधि जमा, आवर्ती जमा और बचत खाते खोलने के लिए प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सशक्त महिला ऋण योजना, शिक्षा ऋण और फसल बीमा योजना के लाभ भी समझाए गए। शिविर में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अंत में बैंक अधिकारियों ने पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

स्मार्ट हैकाथॉन युवाओं की तकनीकी प्रतिभा और नवाचार को देगा नई उड़ान

नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता : धर्माणी

भारतेन्दु संवाददाता, सुंदरनगर। जवाहरलाल नेहरू राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुंदरनगर में शुक्रवार को राज्य स्तरीय स्मार्ट हैकाथॉन-2026 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के शुभारंभ में ग्राम एवं नगर नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने मुख्यातिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर पूर्व मुख्य संसदीय सचिव सोहन लाल ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा राज्य स्तरीय स्मार्ट हैकाथॉन स्मारिका का विमोचन भी किया। राजेश धर्माणी ने कहा कि स्मार्ट हैकाथॉन युवाओं की रचनात्मक सोच, तकनीकी दक्षता और समस्या समाधान की क्षमता को विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को कक्षा में प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग करते हुए समाज की वास्तविक समस्याओं के समाधान तलाशने चाहिए। किसी भी परियोजना में सफलता हासिल करने के लिए पूरी लगन, समर्पण और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के साथ अन्य शैक्षणिक एवं रचनात्मक गतिविधियों में भी भाग लेने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन फंड का प्रावधान किया है। संभावनाओं वाले विचारों का विशेषज्ञों से मूल्यांकन करवाकर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा सकती है। इसके तहत पात्र नवाचारों के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान है। उन्होंने विद्यार्थियों से नए विचारों के साथ आगे आने और भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार में योगदान देने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में टीम भावना, आत्मविश्वास और उद्यमिता की सोच विकसित करने के साथ रोजगार के नए अवसर तलाशने में भी सहायक हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि तीन वर्ष पहले शुरू किया गया स्मार्ट हैकाथॉन अब विद्यार्थियों की सोच और दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस मंच पर विद्यार्थियों ने तकनीकी मॉडल के माध्यम से विभिन्न जनसमस्याओं के समाधान प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इनमें से कुछ विचार भविष्य में स्टार्टअप का रूप लेंगे और समाज के लिए उपयोगी तकनीक एवं प्रक्रियाओं के विकास में सहायक बनेंगे। हैकाथॉन में प्रदेश के विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों की 16 टीमों के 64 विद्यार्थियों ने भाग लिया।



◆ सुंदरनगर में स्मार्ट हैकाथॉन शुरू, 16 टीमों के 64 विद्यार्थी ले रहे भाग

महिला कबड्डी टीम की स्वर्णिम सफलता पर अनुराग सिंह ठाकुर ने किया सम्मानित



सुरेंद्र कटोच, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेल 2026 में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम की खिलाड़ियों को नई दिल्ली स्थित अपने निवास पर सम्मानित किया।

इस अवसर पर टीम की कप्तान पुष्पा राणा सहित स्टार खिलाड़ी रितु नेगी, भावना ठाकुर और ज्योति ठाकुर उपस्थित रहीं। अनुराग ने हिमाचली परंपरा के अनुरूप खिलाड़ियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। अनुराग ने खिलाड़ियों की ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हिमाचल की इन बेटियों ने अपनी प्रतिभा, मेहनत, अनुशासन व संकल्प के दम पर देश का मान बढ़ाया है। उनकी सफलता केवल खेल जगत की उपलब्धि नहीं, बल्कि देश के युवाओं और उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की बेटियां आज अपनी प्रतिभा के बल पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की पहचान मजबूत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय महिला कबड्डी टीम की यह शानदार सफलता देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। खिलाड़ियों की उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है और उनका सम्मान करना राष्ट्र के प्रति उनके योगदान का अभिनंदन है। अनुराग ने कप्तान पुष्पा राणा और टीम की सभी खिलाड़ियों को भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे इसी उत्साह, समर्पण और उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ आगे भी भारत के लिए गौरव हासिल करती रहेंगी। उन्होंने आशा जताई कि हिमाचल प्रदेश की प्रतिभाशाली खिलाड़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेंगी और भारतीय खेल जगत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में योगदान देंगी।

केंद्र सरकार से 1800 करोड़ रुपए स्वीकृत होने के बावजूद एसकेटीटी सड़क निर्माण में देरी क्यों : रवि

धनेश गौतम, भारतेन्दु संवाददाता, केलांग। एसकेटीटी सड़क परियोजना के लिए केंद्र सरकार से 1800 करोड़ रुपए स्वीकृत होने के बावजूद निर्माण और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में हो रही देरी पर लाहौल-स्पीति के पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रवि ठाकुर ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रदेश की सुक्खू सरकार से लंबित औपचारिकताएं जल्द पूरी कर निर्माण कार्य आगे बढ़ाने की मांग की है।

रवि ठाकुर ने कहा कि एसकेटीटी सड़क सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी, सामरिक सुरक्षा और स्थानीय विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए इतनी बड़ी राशि स्वीकृत होने के बाद प्रदेश सरकार और संबंधित प्रशासन को भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि प्रभावित भूमि का मुआवजा केलांग में लागू सर्कल रेट, भूमि की श्रेणी और निर्धारित कानूनी मानदंडों के अनुसार तय किया जाए।



◆ मकानों, गोशालाओं और दुकानों का उचित मुआवजा सुनिश्चित करे सरकार

सड़क निर्माण से प्रभावित होने वाले मकानों, गौशालाओं, दुकानों और अन्य संरचनाओं का उचित मूल्यांकन कर नियमानुसार मुआवजा दिया जाए। रवि ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू, राजस्व एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी और स्थानीय विधायक से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लंबित प्रस्ताव और दस्तावेज संबंधित केंद्रीय प्राधिकरण को शीघ्र भेजे जाएं तथा समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर सड़क निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।

मनाली में बेली ब्रिज से एनएचएआई ब्रिज तक यातायात बंद

भारतेन्दु संवाददाता, मनाली। मनाली में बेली ब्रिज से नए एनएचएआई ब्रिज तक सड़क पर इंटरलॉक पेवर ब्लॉक बिछाने का कार्य दोबारा शुरू किया जा रहा है। इसके चलते इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही 12 से 16 अक्तूबर तक पूरी तरह बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। उपमंडलीय मजिस्ट्रेट मनाली ने लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता की रिपोर्ट के आधार पर जनहित में यह आदेश जारी किया है। निर्माण कार्य के दौरान यातायात एनएचएआई ब्रिज से एनएच-03, लोक निर्माण विभाग के बेली ब्रिज और एमडीआर-29 मार्ग से संचालित किया जाएगा। प्रशासन ने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों से निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने और सहयोग बनाए रखने की अपील की है।

मुख्यमंत्री की नीति कोयलपंथी, पुरानी योजनाओं का श्रेय लेने का प्रयास कर रहे: सुधीर शर्मा

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। भाजपा के वरिष्ठ नेता व धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के धर्मशाला दौरे पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पूर्व सरकारों के कार्यकाल में स्वीकृत योजनाओं का शिलान्यास कर राजनीतिक श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यशैली को 'कोयलपंथी नीति' करार दिया।



सुधीर शर्मा ने कहा कि धर्मशाला में आइस स्केटिंग रिंक और रोलर स्केटिंग रिंक के लिए बजट का प्रावधान उनके मंत्री रहते हुए पिछली सरकार के कार्यकाल में किया गया था। उन्होंने सवाल किया कि वर्तमान सरकार ने धर्मशाला के लिए कौन-सी नई बड़ी विकास परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय के देहरा परिसर के निर्माण का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने बिजली और पानी के खर्च को लेकर भी सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्मशाला बस अड्डे की स्थिति दयनीय है और चेतडू स्थित आईटी पार्क पर ताला लटका हुआ है। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और धर्मशाला-मैक्लोडगंज सड़क की स्थिति पर भी उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सराह से बाहल गांव को जोड़ने वाले पुल के पुनर्निर्माण में देरी से लोगों को परेशानी हो रही है, जबकि इसके लिए नाबार्ड के माध्यम से बजट का प्रावधान किया गया था।

सुधीर शर्मा ने कहा कि सरकार विकास कार्यों की गति बढ़ाने के बजाय राजनीतिक प्रचार को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने रोजगार और स्वरोजगार के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री से जवाब मांगा। उनके अनुसार, युवाओं को रोजगार देने के वादों पर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

कुल्लू में सर्किट हाउस से मियां बेहड़ तक नो पार्किंग जोन

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। जिला प्रशासन ने सर्किट हाउस कुल्लू से शेर सिंह की दुकान (मियां बेहड़) तक सड़क को 30 दिनों के लिए नो पार्किंग जोन घोषित किया है। यह व्यवस्था 16 अक्तूबर से 15 नवंबर, 2026 तक प्रभावी रहेगी। उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. अमित कुमार शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 117 के तहत अधिसूचना जारी की है। सड़क संकरी होने के कारण किनारे वाहनों की पार्किंग से यातायात बाधित होता है और पैदल चलने वालों को परेशानी होती है। इससे एंबुलेंस और अग्निशमन वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो सकती है। प्रशासन ने आम जनता से निर्धारित अवधि में सुझाव, आपत्तियां और दावे प्रस्तुत करने का आग्रह किया है। इसके बाद आपत्तियों पर विचार कर अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।

नेरचौक में आल्टो कार की टक्कर से व्यक्ति की मौत, चालक फरार

भारतेन्दु संवाददाता, नेरचौक। नेरचौक में 15 अक्तूबर की रात तेज रफ्तार सफेद आल्टो कार की टक्कर से 41 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार, रात करीब 10 बजे शिकायतकर्ता नेरचौक स्थित मनाली स्वीट के बाहर खड़ा था। इसी दौरान नेरचौक की ओर से तेज रफ्तार में आ रही सफेद आल्टो कार ने मंडी की तरफ सड़क किनारे पैदल चल रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान महेश कुमार (41), निवासी जिला कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है और हादसे के कारणों की जांच जारी है।

ग्रामीण युवाओं को कौशलयुक्त बनाकर नियमित रोजगार उपलब्ध करवाने पर दें विशेष ध्यान : अनिरुद्ध

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई) के तहत ग्रामीण युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है।



उन्होंने कहा कि आर्थिक अभाव के कारण तकनीकी शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण से वंचित रहने वाले युवाओं के लिए यह योजना विशेष रूप से लाभकारी है। उन्होंने परियोजना कार्यान्वयन समितियों से आग्रह किया कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ-साथ युवाओं को नियमित रोजगार उपलब्ध करवाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम, धर्मशाला में आयोजित डीडीयूजीकेवाई की उत्तरी क्षेत्रीय कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश सहित जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड तथा मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएं विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को अपने अनुभव सांझा करने तथा आपसी संवाद के माध्यम से योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां विकास कार्यों एवं आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है और देश में पेपरलेस विधानसभा की दिशा में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। प्रदेश के युवाओं में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा एवं क्षमता के बल पर आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं।

विद्यार्थियों को आधुनिक खेती की दी जानकारी



भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश विविधीकरण फसल प्रोत्साहन परियोजना के तहत जायका (कृषि) ने राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बजौरा में 'अगली पीढ़ी के लिए जागरूकता कार्यक्रम' आयोजित किया। इसमें विद्यार्थियों को आधुनिक कृषि तकनीकों, पोषण, पर्यावरण संरक्षण और कृषि आधारित रोजगार के अवसरों की जानकारी दी गई। खंड परियोजना प्रबंधक डॉ. जयंत रत्ना ने विद्यार्थियों को प्राकृतिक एवं टिकाऊ खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, नवाचार और उद्यमिता से कृषि क्षेत्र में रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं। कार्यक्रम में संतुलित आहार, जलवायु अनुकूल खेती, पॉलीहाउस तकनीक, जल संरक्षण और कृषि विपणन पर चर्चा की गई। नर्सरी तैयार करने, वर्मी कम्पोस्ट बनाने और पोषण वाटिका स्थापित करने जैसी गतिविधियों पर भी जोर दिया गया। कुल्लू और लाहौल-स्पीति के पांच विद्यालयों के 150 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

तीन माह में शुरू होगी गाहलियां-ठाकुरद्वारा पेयजल योजना : पवन काजल



भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष एवं विधायक पवन काजल ने कहा कि गाहलियां-ठाकुरद्वारा पेयजल योजना का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। करीब साढ़े आठ करोड़ रुपये की लागत से बन रही इस परियोजना को तीन माह के भीतर शुरू कर ग्रामीणों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना के तहत पानी के टैंक तैयार हैं और पाइप बिछाने का काम जारी है। शुक्रवार को जनसंपर्क अभियान के दौरान काजल ने गाहलियां में पूर्व भाजपा सरकार के समय शुरू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बंद करने पर कांग्रेस सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर इसे दोबारा शुरू करवाया जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार पर चुनावी गारंटियां पूरी नहीं करने और टांडा मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का आरोप भी लगाया। इससे पहले काजल ने सहोड़ा और जमानाबाद की रामलीलाओं में भाग लिया तथा 250 बच्चों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने युवाओं से मोबाइल से दूरी बनाकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ने की अपील की।

राहुल गांधी को निशाना बनाने के बजाय विफलताओं का जवाब दे भाजपा : संजीव

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता संजीव गांधी ने भाजपा पर राजनीतिक बयानबाजी से जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा राहुल गांधी को निशाना बनाने के बजाय शासन, पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही से जुड़े सवालों का जवाब दे। संजीव गांधी ने कथित गोपनीय सूचना लीक होने के मामले में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि सूचना लीक हुई है तो निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष पर हमले करके भाजपा असहज सवालों से बच नहीं सकती। उन्होंने चुनावी पारदर्शिता, लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता और परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने जैसे मुद्दे उठाते हुए कहा कि प्रशासनिक विफलताओं का खामियाजा विद्यार्थियों को नहीं भुगतना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और राजनीतिक हमलों के बजाय तथ्यों के आधार पर जवाब देना चाहिए।

दस गारंटियों का हिसाब नहीं, अब 11वीं गारंटी का शिगूफा छोड़ रही सुक्खू सरकार : बिक्रम ठाकुर

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री व जसवां-परागपुर के विधायक बिक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि दस चुनावी गारंटियों को पूरा करने में विफल रही कांग्रेस सरकार अब नए जिलों के गठन की चर्चा के जरिए जनता का ध्यान बुनियादी मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार वास्तव में नए जिले बनाने को लेकर गंभीर थी, तो सत्ता में आने के चार साल बाद ही इस विषय की याद क्यों आई?



बिक्रम ठाकुर ने कहा कि स्थानीय निकाय व पंचायतीराज चुनावों में कांग्रेस को मिली हार के बाद सरकार नए जिलों के गठन जैसे संवेदनशील विषय को चर्चा में ला रही है। उनके अनुसार, अगले विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दों को उठाना सरकार की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई, विकास कार्यों में देरी और चुनावी गारंटियों की स्थिति पर उठ रहे सवालों से बचना चाहती है। उन्होंने कहा कि नए जिलों का गठन अपने आप में गलत नहीं है, जिन क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों, जनसंख्या, दूरी और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर अलग जिले की मांग उठ रही है, वहां सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, लेकिन इसके लिए स्पष्ट नीति, ठोस आधार और समयबद्ध कार्ययोजना जरूरी है। केवल आयोग बनाने की चर्चा करना या संभावनाएं जताकर जनता में उम्मीदें जगाना पर्याप्त नहीं है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि प्रदेश में नए जिलों के गठन की आवश्यकता का आकलन करने के लिए पिछले चार वर्षों में सरकार ने क्या कदम उठाए। क्या विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त मांगों का व्यवस्थित अध्ययन किया गया? क्या प्रशासनिक सुविधाओं, भौगोलिक परिस्थितियों और वित्तीय संसाधनों को लेकर कोई रिपोर्ट तैयार की गई?

एग्रीवेट-2026 में कृषि नवाचार व जलवायु अनुकूल पशुपालन पर मंथन

भारतेन्दु संवाददाता, गोहर। अभिलाषी विश्वविद्यालय, चैलचौक में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'एग्रीवेट-2026' के दूसरे दिन कृषि, पशुपालन और जलवायु अनुकूल तकनीकों पर शोध प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में 45 से अधिक युवा वैज्ञानिकों और शोधार्थियों ने मौखिक शोध पत्र प्रस्तुत किए, जबकि 40 से अधिक प्रतिभागियों ने पोस्टर सत्र में अपने शोध प्रदर्शित किए। गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, लुधियाना के डॉ. यशवंत सिंह ने टिकाऊ डेयरी उत्प

न्यूज ब्रीफ

रामलीला में सुरिंदर ने भेंट किए 11 हजार रुपए



भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। नगर परिषद मैदान कांगड़ा में आयोजित रामलीला की पांचवीं संध्या में उत्सव पैलेस के प्रबंध निदेशक सुरिंदर कुमार ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने रामलीला सभा को 11 हजार रुपए भेंट किए और लोगों से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि परिवार सहित रामलीला देखने से बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित होते हैं। पांचवीं संध्या में राम के राजतिलक की घोषणा, मंथरा-कैकेयी संवाद, कैकेयी-दशरथ संवाद, राम को वनवास, कौशल्या-राम संवाद और राम के वनगमन सहित अयोध्यावासियों के उनके साथ जाने के दृश्य मंचित किए गए। रामलीला देखने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आयोजन में रामलीला से जुड़े सवालों के सही जवाब देने वाले प्रतिभागियों के लिए रोजाना दस पर्चियां निकालकर पुरस्कार दिए जा रहे हैं। बच्चों में इसे लेकर खास उत्साह है। मैदान में खानपान के स्टॉल और बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं। इस दौरान रामलीला सभा के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।

अर्की रामलीला में लगाया जलेबियों का भंडारा



भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। अर्की के चौगान मैदान में आयोजित रामलीला के दौरान युवाओं ने सेवा भावना का परिचय देते हुए दूसरी बार जलेबियों का भंडारा लगाया। तरुण गुप्ता, नोजू गुप्ता, गौरव अग्रवाल व कमल ने इस आयोजन में सहयोग किया। उन्होंने रामलीला देखने पहुंचे श्रद्धालुओं को जलेबियां वितरित कर सभी का मुंह मीठा करवाया। इस पहल की शुरुआत वर्ष 2025 में तरुण गुप्ता व नोजू गुप्ता ने की थी। युवाओं ने अपनी इस पहल को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन किया। खास बात यह रही कि इस बार अन्य लोगों ने भी इसमें सहयोग दिया, जिससे यह प्रयास सामूहिक सहभागिता का उदाहरण बन गया। युवाओं की इस अनूठी पहल से रामलीला के माहौल में उत्साह देखने को मिला। साथ ही, इस आयोजन ने सेवा, सामाजिक सहयोग और आपसी भाईचारे का संदेश भी दिया। स्थानीय स्तर पर युवाओं के इस प्रयास की सराहना की जा रही है।

सोलन में कांग्रेस ने निकली बाइक रैली लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा का संदेश



भारतेन्दु संवाददाता, सोलन। 'लोकतंत्र बचाओ, वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान के तहत शुक्रवार को ब्लॉक कांग्रेस और शहरी कांग्रेस सोलन की ओर से विशाल बाइक रैली निकाली गई। इसमें महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रैली सुबह 11:30 बजे पुराने विश्राम गृह से शुरू होकर कोटलानाला पहुंची। इसके बाद पुराने डीसी कार्यालय चौक से होते हुए मिनी सचिवालय तक निकाली गई, जहां इसका समापन हुआ। रैली का नेतृत्व अमित ठाकुर, पुनीत शर्मा, संजय शांडिल, विकास कालटा, विजय पुरी और सीमा शर्मा ने किया। इस दौरान प्रतिभागियों ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और मताधिकार सुरक्षित रखने के समर्थन में नारे लगाए। आयोजकों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य नागरिकों को उनके मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक करना है। रैली में शामिल सभी प्रतिभागियों ने हेलमेट पहनकर यातायात नियमों का पालन किया। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

राजस्थान पुलिस के 472 आरक्षियों ने ली कर्तव्यनिष्ठा की शपथ



भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के शमशी प्रशिक्षण केंद्र में शुक्रवार को राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल (आरएसी) के 472 नव आरक्षियों की दीक्षांत परेड आयोजित की गई। नौ माह का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद नव आरक्षियों ने कर्तव्यनिष्ठा और सेवा की शपथ ली। समारोह में राजस्थान पुलिस के प्रशिक्षण निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक एचजीआर सुहास मुख्यातिथि रहे। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और जवानों के अनुशासित मार्च पास्ट की सराहना की। इस दौरान नव आरक्षियों ने योग, शारीरिक प्रशिक्षण, दंगा नियंत्रण, निशस्त्र युद्धकला, जूडो तथा हथियारों को खोलने और जोड़ने का प्रदर्शन किया। प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आरक्षियों को सम्मानित भी किया गया। एचजीआर सुहास ने कहा कि पुलिस सेवा समाज और राष्ट्र के प्रति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जवानों को सेवाकाल में अनुशासन, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और संवेदनशीलता बनाए रखनी चाहिए। समारोह में एसएसबी के उपमहानिरीक्षक अजय कुमार सहित विभिन्न अधिकारी और नव आरक्षियों के परिजन उपस्थित रहे।

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा: 21 से 27 अक्तूबर तक हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव-2026 के दौरान शांति, कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी डॉ. अमित कुमार शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। आदेश के अनुसार, 21 से 27 अक्तूबर तक कुल्लू, मनाली और भुंतर पुलिस थाना क्षेत्रों में ड्यूटी पर तैनात पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सेना के जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। प्रशासन ने नगर निकायों, ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और मकान मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में आने वाले नए व्यक्तियों, विदेशी नागरिकों, प्रवासी मजदूरों, शॉल विक्रेताओं और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के आगमन या ठहरने की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को दें। हथियार मिलने पर भी पुलिस को सूचित करना अनिवार्य होगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

चेतना संस्था में चयनित शिक्षकों को सम्मान



भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। बिलासपुर की चेतना संस्था में शुक्रवार को विशेष शिक्षक के पदों पर चयनित पूर्व विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्य के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। समारोह का मुख्य आकर्षण डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के प्रवक्ता राकेश कुमार रहे, जिनका चयन पीआरटी और टीजीटी दोनों पदों के लिए हुआ है। उनके साथ संस्था की पूर्व छात्राओं कृतिका, कंचन कुमारी, आंचल शर्मा और प्रियंका देवी तथा अभिनव गौतम को भी सम्मानित किया गया। कृतिका का चयन प्राथमिक और उच्च स्तर के पदों के लिए हुआ है। संस्था के निदेशक अरुण कुमार गौतम ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनकी सफलता का श्रेय मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। संस्थापिका डॉ. मल्लिका नड्डा ने नवनियुक्त शिक्षकों से दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए संवेदनशीलता एवं निष्ठा से कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर सचिव हरीश नड्डा और प्रशासनिक अधिकारी कश्मीर सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे।

भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं, पार्टी का आदेश सर्वोपरि : विशाल नेहरिया

हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। इसी बीच धर्मशाला के पूर्व विधायक व भाजपा नेता विशाल नेहरिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा में गुटबाजी की चर्चाओं को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं है, बल्कि पार्टी का एक ही गुट है और सभी कार्यकर्ता संगठन के फैसलों के अनुसार काम करते हैं। भारतेन्दु शिखर की एंकर 'रीत वशिष्ठ' के साथ डिजिटल साक्षात्कार में उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस), महिला सम्मान राशि, रोजगार, धारा 118 और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी बात रखी। प्रस्तुत हैं बातचीत के प्रमुख अंशः



सवालः भाजपा में गुटबाजी की चर्चाएं होती रहती हैं। धर्मशाला में भी अलग-अलग नेताओं के गुट होने की बात कही जाती है। आप इसे कैसे देखते हैं?

जवाबः मुझे नहीं लगता कि भाजपा में कोई गुटबाजी है। भाजपा का एक ही गुट है और वह भारतीय जनता पार्टी का गुट है। पार्टी की ओर से जो भी निर्णय लिया जाता है, सभी कार्यकर्ता उसके अनुसार काम करते हैं। धर्मशाला में सभी नेता और कार्यकर्ता मिलकर पार्टी के लिए काम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे।

सवालः धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है। आपके विधायक रहते इस दिशा में क्या प्रयास किए गए और अब देहरा में परिसर जाने को लेकर आप क्या कहेंगे?

जवाबः मेरे लगभग ढाई साल के कार्यकाल के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़ी कानूनी औपचारिकताओं और कागजी कार्रवाई को पूरा करवाया गया था। वन मंजूरी से जुड़ी प्रक्रिया भी आगे बढ़ी। इसके बाद प्रदेश में सरकार बदल गई। उस समय करीब 30 करोड़ रुपए से कम की प्रतिपूरक वनीकरण संबंधी राशि जमा करवाने का विषय सामने आया था। प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार को अपना योगदान देना चाहिए था। मेरा मानना है कि उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए थी।

सवालः प्रदेश में ओपीएस लागू होने के दावों के बावजूद कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। आप इसे किस रूप में देखते हैं?

जवाबः आज प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी अपनी तनख्वाह को लेकर भी चिंतित हैं। महंगाई भत्ते (डीए) का भुगतान लंबे समय से लंबित होने की बात सामने आती रही है। कर्मचारी प्रदेश की व्यवस्था की रीढ़ होते हैं, लेकिन वे भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कर्मचारियों को उनके अधिकारों और सुविधाओं का लाभ किस तरह दिया जा रहा है। केवल दावे करने से कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

सवालः कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह देने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने का वादा किया था। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

जवाबः कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया था, लेकिन मेरे अनुसार महिलाओं को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिला है। चार वर्षों के हिसाब से 1,500 रुपए प्रतिमाह की राशि 72,000 रुपए बनती है। इसी तरह युवाओं को पांच लाख नौकरियां देने का वादा भी किया गया था। सरकार को बताना चाहिए कि कितने युवाओं को रोजगार मिला और स्वरोजगार के लिए क्या कदम उठाए गए। मेरा मानना है कि प्रदेश की जनता आने वाले चुनावों में इन मुद्दों पर जवाब मांगेगी।

सवाल : हिमाचल प्रदेश में धारा 118 को लेकर समय-समय पर चर्चा होती रहती है। इस कानून को लेकर आपका क्या मत है?

जवाबः हिमाचल प्रदेश में धारा 118 के प्रावधानों को संरक्षित रखना बेहद जरूरी है। इसमें ऐसी ढील नहीं दी जानी चाहिए, जिससे प्रदेश की पहचान और स्थानीय लोगों के हित प्रभावित हों। यह हिमाचल की जमीन और अधिकारों से जुड़ा संवेदनशील विषय है। इस पर गंभीरता से विचार करने और नियमों का सही ढंग से पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

सवालः वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। क्या भाजपा आपको दोबारा धर्मशाला से टिकट देगी या शाहपुर से चुनाव लड़ने की चर्चाएं सही हैं?

जवाबः मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, उसे निभाऊंगा। शाहपुर मेरा जन्मस्थान है और वहीं के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कल्याणा से मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। आगामी चुनाव में मेरी क्या भूमिका होगी, यह मुझे नहीं मालूम। पार्टी जो आदेश करेगी, उसका पालन करूंगा।

सवालः आप खुद को पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का सिपाही बताते हैं। उनके मार्गदर्शन को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? साथ ही, प्रदेश में भाजपा की आगामी चुनावी रणनीति को लेकर क्या कहेंगे?

जवाबः शांता कुमार भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और उनका मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। उनके आदर्शों से हमें लोगों के बीच जाकर ईमानदारी और अच्छी नीयत से काम करने की प्रेरणा मिलती है, जहां तक आगामी चुनावों की बात है, भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। मुझे विश्वास है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार के कामकाज का आकलन करेगी। कांग्रेस सरकार ने महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों से जो वादे किए थे, उनका जवाब जनता को देना होगा।

हिमाचल ग्रामीण बैंक ने नुक्कड़ नाटक से स्वच्छता व वित्तीय साक्षरता का दिया संदेश



भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की सुंदरनगर शाखा की ओर से भोजपुर मुख्य बाजार में राष्ट्रव्यापी अभियान 'स्वच्छता ही सेवा 2026' के तहत नुक्कड़ नाटक व वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इसका उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के महत्व, साइबर धोखाधड़ी से बचाव और केंद्र सरकार की विभिन्न वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी देना रहा। कार्यक्रम में आकार थियेटर सोसायटी, गांव एवं डाकघर सेहली, तहसील कोटली, जिला मंडी के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। बैंक की ओर से यह कार्यक्रम निशुल्क आयोजित किया गया। कलाकारों ने सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने, कूड़ा-कचरा निर्धारित स्थानों पर डालने और आसपास के वातावरण को साफ रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के प्रति भी जागरूक किया गया। उन्हें अनजान लिंक पर क्लिक न करने और अपना ओटीपी, एटीएम पिन तथा बैंकिंग से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करने की सलाह दी गई। साथ ही साइबर धोखाधड़ी होने की आशंका पर सतर्क रहने का आह्वान किया गया। बैंक अधिकारियों ने खातों में नामांकन संबंधी जानकारी अद्यतन करवाने और निष्क्रिय बैंक खातों को नियमानुसार दोबारा सक्रिय करवाने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के लाभों की जानकारी देकर पात्र लोगों को इनसे जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। बैंक अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जनभागीदारी बढ़ाने, वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करने और सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक सुंदरनगर शाखा के प्रबंधक भूपेंद्र सिंह, सहायक प्रबंधक प्रताप मीणा और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। पुंघ शाखा के प्रबंधक नीरज वर्मा ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

बदलते शैक्षणिक परिवेश में अध्यापक की भूमिका चुनौतीपूर्ण : प्रो. एनएन शर्मा

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। रोटरी क्लब धर्मशाला ने लिटरेसी मिशन के तहत अवस्थी शिक्षा महाविद्यालय दाड़ी में 'प्रभावी शिक्षा कौशल : बदलाव व चुनौती' विषय पर कार्यशाला आयोजित की। इसमें रोटरी जिला 3070 के डिस्ट्रिक्ट चेयर लिटरेसी एवं शिक्षाविद प्रोफेसर एनएन शर्मा ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि तकनीक के बढ़ते प्रभाव और शिक्षा के बदलते स्वरूप में अध्यापकों की भूमिका चुनौतीपूर्ण हो गई है। शिक्षकों को विद्यार्थियों की अपेक्षाओं के अनुरूप शिक्षण पद्धति अपनाते हुए शिक्षित भारत के निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने नैतिक शिक्षा, अनुशासन, मेहनत, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी पर जोर देते हुए राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कार्यशाला में विद्यार्थियों को अध्यापन क्षेत्र की चुनौतियों से अवगत करवाया गया और उपयोगी सुझाव दिए गए। महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. दिनेश धीमान ने आयोजन को शैक्षणिक विकास की दिशा में सराहनीय पहल बताया। इस अवसर पर रोटरी क्लब सचिव सुभाष शर्मा, तेज सिंह और हरि सिंह सहित महाविद्यालय का स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया।

द्रोणाचार्य कॉलेज में टैलेंट हंट प्रशिक्षुओं ने दिखाई प्रतिभा



भारतेन्दु संवाददाता, रैत। द्रोणाचार्य स्नातकोत्तर शिक्षण महाविद्यालय रैत में बीएड प्रथम वर्ष के प्रशिक्षुओं के लिए 'टैलेंट हंट मेरी प्रतिभा, मेरी पहचान' कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में कॉलेज के कार्यकारी निदेशक डॉ. बीएस पठानिया ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। महाविद्यालय परिसर में पहुंचने पर उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षुओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इनमें पेंटिंग, कैलीग्राफी, गायन, मॉडलिंग, भाषण, चित्रकला, पाक कला, शायरी, नृत्य, रंगोली, खेलकूद, वाद-विवाद, मंच संचालन, वीडियोग्राफी और अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी सामग्री बनाने जैसी गतिविधियां शामिल रहीं। विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता, कलात्मक कौशल और आत्मविश्वास का परिचय दिया। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. प्रवीण शर्मा ने कहा कि टैलेंट हंट जैसे आयोजन विद्यार्थियों को अपनी छिपी प्रतिभा पहचानने और उसे निखारने का अवसर देते हैं। ऐसी गतिविधियां आत्मविश्वास, रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के साथ व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में भी सहायक हैं। मुख्यातिथि डॉ. बीएस पठानिया ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी में कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है। जरूरत उसे पहचानने और उचित मंच प्रदान करने की है। उन्होंने प्रशिक्षुओं को पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक व रचनात्मक गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया।

चम्मयौन गांव में सेवानिवृत्त शिक्षक लक्ष्मण दास वर्मा ने परिजनों संग मनाया जन्मदिन



अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। कोल डैम क्षेत्र के चम्मयौन गांव निवासी व सेवानिवृत्त शिक्षक लक्ष्मण दास वर्मा ने अपना 84वां जन्मदिन परिजनों और शुभचिंतकों के साथ हर्षोल्लास से मनाया। 15 अक्तूबर 1942 को जन्मे वर्मा ने इस अवसर पर अपने जीवन के संघर्षों और शैक्षणिक सफर की यादें साझा कीं। उन्होंने बताया कि वर्ष 1961 में पंजगाईं स्कूल से दसवीं की बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद उन्होंने सुंदरनगर पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एनडीएसआई प्रशिक्षण लेकर शारीरिक शिक्षक के रूप में करियर शुरू किया। नौकरी के साथ ही उन्होंने 1973 में पंजाब यूनिवर्सिटी से इतिहास में एमए ऑनर्स की डिग्री हासिल की। वर्तमान में वह राष्ट्रीय अनुशासन योजना प्रशिक्षक अध्यापक संघ की कार्यकारिणी में सचिव हैं। पुराने दौर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि तब शिक्षा के साधन सीमित थे और आर्थिक अभाव के चलते पढ़ाई करना बेहद कठिन था, लेकिन कड़ी मेहनत व दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर वह आगे बढ़ने में सफल रहे।

एसपी विनोद ने एनएचएआई अधिकारियों के साथ बनाई यातायात सुधार की योजना



भारतेन्दु संवाददाता, सोलन। आगामी त्योहारी सीजन के दौरान बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने और लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए बद्दी पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों और संबंधित विभागों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव भाटिया, डीएसपी योगराज चंदेल, गणपति भारत प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ओमप्रकाश शर्मा, बिजली विभाग के अधिकारियों, बद्दी थाना प्रभारी और यातायात प्रभारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। एसपी विनोद कुमार ने कहा कि त्योहारी सीजन में बाजारों और प्रमुख सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ने से जाम की समस्या पैदा हो सकती है। अधूरे निर्माण कार्य, खराब सड़कें और संकरे मार्ग भी यातायात प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने एनएचएआई और निर्माण कंपनी को राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों में तेजी लाने तथा यातायात बाधित करने वाले स्थानों को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से उन स्थानों पर सुधार करने को कहा, जहां सड़क संकरी होने या एक ही लेन से वाहनों की आवाजाही के कारण जाम लगता है। उन्होंने सभी विभागों से आपसी समन्वय के साथ काम करने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। एनएचएआई और निर्माण कंपनी के प्रतिनिधियों ने चिह्नित स्थानों पर कार्य तेज करने का भरोसा दिया।

प्रभावित स्थानों का किया निरीक्षण

बैठक के बाद एसपी बद्दी सहित अधिकारियों ने रेडलाइट चौक, संडोली और किशनपुर समेत प्रमुख यातायात प्रभावित स्थलों का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क की स्थिति और निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेकर आवश्यक सुधार जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। पुलिस के अनुसार, चिह्नित स्थानों पर निर्माण एवं सुधार कार्य शुरू कर दिए गए हैं। बद्दी पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने, सड़क किनारे अनावश्यक पार्किंग से बचने और यातायात पुलिस का सहयोग करने की अपील की है।

सरकाघाट को जिला बनाने की मांग, पुनर्गठन आयोग के गठन का पूर्व सैनिकों ने किया स्वागत

भारतेन्दु संवाददाता, सरकाघाट। हिमाचल प्रदेश में जिलों और उपमंडलों के पुनर्गठन के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी की अध्यक्षता में आयोग गठित करने पर क्षेत्र के पूर्व सैनिकों ने खुशी जताई है। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन (जेसीओ एवं ओआर) हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष सेवानिवृत्त कैप्टन जगदीश वर्मा और सरकाघाट इकाई के कैप्टन अशोक ने संयुक्त बयान में उम्मीद जताई कि आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकाघाट को जिला बनाने का रास्ता खुलेगा। कैप्टन जगदीश वर्मा ने कहा कि सरकाघाट, धर्मपुर, संधोल और बलद्वाड़ा सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को जिला मुख्यालय मंडी पहुंचने के लिए 70 से 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इससे समय और धन दोनों खर्च होते हैं तथा सरकारी कामकाज प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1968 के बाद जिलों के पुनर्गठन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, जबकि क्षेत्र की आबादी में काफी वृद्धि हुई है। सरकाघाट को जिला बनाने से प्रशासनिक सुविधाएं बेहतर होंगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी। पूर्व सैनिकों ने आयोग को पत्र लिखकर मांग उठाने और जरूरत पड़ने पर आयोग के सदस्यों से मुलाकात करने की बात भी कही।

धौलरा मंदिर में शारदोत्सव की धूम, गरबा में अर्शिया और मुक्ता ने मारी बाजी



भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। शहर के ऐतिहासिक धौलरा मंदिर में आयोजित शारदोत्सव के छठे नवरात्र पर मां कात्यायनी की विधिवत पूजा-अर्चना की गई। शिमला से पहुंचे पुजारी सुधांशु शेखर भट्टाचार्य और अशोक कुमार भट्टाचार्य के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने पूजन किया। उत्सव के दौरान आयोजित गरबा प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में अर्शिया ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का खिताब जीता, जबकि सीनियर वर्ग में मुक्ता गुप्ता सर्वश्रेष्ठ रहीं। जूनियर वर्ग में रिद्धि, सोनाक्षी, इशिता, वेदांशी और मुस्कान ने जूनियर फिट एंड फायर का खिताब हासिल किया। वहीं, सीनियर वर्ग में बिनता गुप्ता को सर्वश्रेष्ठ परिधान के लिए चुना गया। दुर्गा पूजा उत्सव की संस्थापिका डॉ. मल्लिका नड्डा ने बताया कि 17 अक्तूबर को सुबह आठ बजे सप्तमी पूजा और नवपत्रिका स्थापना होगी। सुबह साढ़े दस बजे पुष्पांजलि और शाम सात बजे मां दुर्गा की आरती की जाएगी।

नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए 22 तक करें आवेदन

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा-2027 के तहत कक्षा नौवीं और ग्यारहवीं की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 22 अक्तूबर कर दी गई है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर निर्धारित थी। जवाहर नवोदय विद्यालय बंदरोल, कुल्लू के प्राचार्य ने बताया कि वर्तमान में कक्षा आठवीं और दसवीं में पढ़ रहे विद्यार्थी प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कक्षा नौवीं के लिए अभ्यर्थी की जन्म तिथि 1 मई, 2012 से 31 जुलाई, 2014 के बीच होनी चाहिए। वहीं, कक्षा ग्यारहवीं के लिए जन्म तिथि 1 जून, 2010 से 31 जुलाई, 2012 निर्धारित है। चयन परीक्षा 10 अप्रैल, 2027 को होगी। अधिक जानकारी के लिए अभिभावक विद्यालय के दूरभाष नंबर 9418538510 पर संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है।

मोटे अनाज से मफिन और जैम बनाने का प्रशिक्षण, स्वरोजगार पर दिया जोर



भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। उपमंडल अर्की की ग्राम पंचायत चम्यावल में डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन के खाद्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से आरकेवीवाई परियोजना के तहत मिलेट्स प्रसंस्करण व उद्यमिता पर एकदिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें किसानों, ग्रामीण महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को मोटे अनाज के पोषण संबंधी महत्व, प्रसंस्करण तकनीकों और स्वरोजगार की संभावनाओं की जानकारी दी गई।

विश्वविद्यालय की विशेषज्ञ डॉ. मनीषा कौशल और डॉ. अनिल कुमार वर्मा ने प्रतिभागियों को श्री अन्न से मूल्य संवर्धित खाद्य उत्पाद तैयार करने और छोटे उद्यम स्थापित करने के बारे में बताया। शिविर में मोटे अनाज से मफिन और फलों का जैम बनाने का व्यावहारिक प्रदर्शन भी किया गया। विशेषज्ञों ने खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय शुरू करने के लिए एफएसएसएआई पंजीकरण व लाइसेंस की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, उचित पैकेजिंग, खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन और प्रभावी विपणन उद्यम की सफलता के लिए आवश्यक हैं। स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नए साधन विकसित किए जा सकते हैं। इस अवसर पर पंचायत प्रधान भावना, उपप्रधान परमिंदर ठाकुर, पंचायत सचिव, वार्ड सदस्य और ग्रामीण उपस्थित रहे। पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी पहल ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में सहायक है।

बिलासपुर कॉलेज में 55 विद्यार्थियों ने चलाया स्वच्छता अभियान

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर के पर्यटन एवं यात्रा विभाग की ओर से महाविद्यालय परिसर के खुले बैठने वाले क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्राचार्य डॉ. पी.एस. कटवाल के मार्गदर्शन और विभागाध्यक्ष डॉ.

एना इवानोविक का खूबसूरत अंदाज

सर्बिया। सर्बिया की टेनिस खिलाड़ी एना इवानोविक भी खूबसूरती में किसी से पीछे नहीं हैं। वह दुनिया की नंबर वन टेनिस खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। उनकी सुंदरता के आगे कई मॉडल्स फेल हैं। वह अपने आक्रामक खेल के लिए जानी जाती हैं।



श्रीलंका में 14 नवंबर से शुरू होगा मिक्स्ड-जेंडर टूर्नामेंट 'टेस्ट ट्वेंटी'

क्रिकेट में टेस्ट, एकदिवसीय और टी20 के बाद एक और प्रारूप का होगा आगाज

एजेंसी, मुंबई/कोलंबो

क्रिकेट में करीब 150 वर्षों के इतिहास में पहली बार लड़कियों और लड़कों के रन मिलकर एक ही टीम का परिणाम तय करेंगे। क्रिकेट के नए प्रारूप 'टेस्ट ट्वेंटी' का पहला सत्र 14 से 29 नवंबर तक श्रीलंका की राजधानी कोलंबो स्थित सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब (एसएससी) मैदान पर आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में दुनिया भर के 13 से 21 वर्ष की आयु के 160 युवा क्रिकेटर हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

टेस्ट ट्वेंटी को क्रिकेट का चौथा प्रारूप बताया जा रहा है। अब तक क्रिकेट में टेस्ट, एकदिवसीय और टी20 प्रारूप प्रचलित रहे हैं। इस नए प्रारूप की खासियत यह है कि इसमें प्रत्येक टीम की ओर से लड़कियों और लड़कों की अलग-अलग एकादश



मैदान पर उतरेगी, लेकिन दोनों के बनाए रन एक ही स्कोर में जोड़े जाएंगे। मैच का फैसला दोनों टीमों के संयुक्त स्कोर के आधार पर होगा।

80 ओवर का मुकाबला, दो गेंदें और एक संयुक्त स्कोर

टेस्ट ट्वेंटी का प्रत्येक मुकाबला एक ही दिन में खेला जाएगा। इसमें प्रत्येक टीम दो बार बल्लेबाजी करेगी और कुल 80 ओवर का खेल होगा। पहले 40 ओवर दिन में लाल गेंद से सफेद कपड़ों में खेले जाएंगे, जबकि अंतिम 40 ओवर रंगीन कपड़ों में सफेद गेंद से एसएससी मैदान की फ्लडलाइट्स के नीचे होंगे। इस प्रारूप में लाल और सफेद गेंद का इस्तेमाल एक ही मैच में किया जाएगा। पहले सत्र में बनाए गए रन दूसरे सत्र में भी कुल स्कोर का हिस्सा बने रहेंगे। यानी दिन में बनाया गया हर रन रात के खेल में भी टीम के परिणाम को प्रभावित करेगा। मुकाबले का फैसला उसी दिन संयुक्त स्कोर के आधार पर होगा।

लड़कियों-लड़कों के रन तय करेंगे जीत

टेस्ट ट्वेंटी के चार महाद्वीपीय दलों में से प्रत्येक में 40 खिलाड़ी होंगे। इनमें 20 लड़कियां और 20 लड़के शामिल होंगे। प्रत्येक मुकाबले में लड़कियों की टीम लड़कियों के खिलाफ और लड़कों की टीम लड़कों के खिलाफ खेलेगी। हालांकि, दोनों के प्रदर्शन को जोड़कर ही टीम का अंतिम स्कोर तैयार किया जाएगा। इस प्रारूप में 'पैरिटी रूल' यानी समानता नियम लागू होगा। टॉस से यह तय होगा कि कौन-सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और उसकी ओर से पहले लड़कियों की एकादश उतरेगी या लड़कों की। दिन में लड़कियों द्वारा बनाए गए रन रात में लड़कों की जीत या हार का फैसला प्रभावित करेंगे।

श्रीलंका को इसलिए मिली मेजबानी

आयोजकों ने श्रीलंका को इस नए प्रारूप के पहले सत्र के लिए चुना है। देश में स्कूली क्रिकेट की लंबी परंपरा रही है। रॉयल-थॉमियन क्रिकेट मुकाबला पहली बार 1879 में खेला गया था और इस वर्ष मार्च में इसका 147वां संस्करण एसएससी मैदान पर आयोजित हुआ। श्रीलंका ने विश्व क्रिकेट को सनथ जयसूर्या, मुथैया मुरलीधरन, कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने जैसे दिग्गज खिलाड़ी दिए हैं। वर्ष 2006 में एसएससी मैदान पर संगकारा और जयवर्धने ने टेस्ट क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी करते हुए 624 रन जोड़े थे।

संजय मांजरेकर बोले-पिच फ्लैट बनाएं, बाउंड्री छोटी करें

एजेंसी, नई दिल्ली

'मुझे लगता है कि पिचों को और फ्लैट बनाने, बाउंड्री छोटी करने और गेंदबाजों के खिलाफ नियम और सख्त करने की गुंजाइश है, ताकि टी-20 में नियमित रूप से 20



ओवर में 300 रन बन सकें।' यह कहना है पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर का। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पोस्ट के जरिए कही। मांजरेकर की पोस्ट ऐसे समय आई है, जब फ्लैट भारतीय पिचों पर सवाल उठ रहे हैं। गौतम गंभीर, युजवेंद्र चहल जैसे कई दिग्गज क्रिकेटर्स पिचों को बॉलिंग फ्रेंडली बनाने की मांग कर रहे हैं।

चेतन शर्मा ने बॉलिंग पिचों की मांग की थी



एक दिन पहले भारतीय टीम के पूर्व चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने कहा- 'टी-20 क्रिकेट में बैटिंग पिचों से बल्ले और गेंद के बीच संतुलन बिगड़ रहा है।' नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में चेतन ने कहा- 'मैं मानता हूं कि गेंदबाज रन देने के लिए मैदान पर आते हैं। लेकिन उन्हें इतना मत मारिए कि वे दोबारा मैदान पर आना ही न चाहें।'

गंभीर ने हफ्ते में 2 बार पिच पर उठाए थे सवाल



भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने 9 अक्टूबर की रात को रांची में दूसरे टी-20 के बाद कहा था- 'फ्लैट पिचों पर गेंदबाजों के करियर दांव पर लगे हैं। सरफेस में बैट और बॉल के बीच बराबरी का मुकाबला होना जरूरी है।' 3 अक्टूबर को गुवाहाटी में दूसरे वनडे के बाद गंभीर ने कहा था कि 'यह क्रिकेट नहीं था, सिर्फ बल्लेबाजी थी।' उस मुकाबले में भारत ने 406 रन का लक्ष्य हासिल किया था। इस मुकाबले में 811 रन बने थे।

स्पोर्ट्स विंडो

अमृता अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में, कोमल को कांस्य

एजेंसी, लास वेगास। भारत की अमृता पुजारी ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 72 किलो फाइनल में प्रवेश कर लिया। अमृता ने कजाखस्तान की साबिरजानोवा को 7-1 से हराने के बाद सेमीफाइनल में चीन की वेंजिन कियू को 10-8 से मात दी। महाराष्ट्र के सोलापूर की अमृता का सामना अब यूक्रेन की इरिना जाब्लोत्स्का से होगा। कोमल ने महिलाओं के 59 किलो वर्ग में कजाखस्तान की विक्टोरिया के को 7-2 से हराकर कांस्य पदक जीता। इससे पहले वह सेमीफाइनल में यूक्रेन की एलिना फिलिपोविच से तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हार गई थी। उन्होंने कनाडा की एला फाइंडिंग को हराया था। स्वीटर 53 किलो वर्ग में रेपेशॉज के जरिये कांस्य पदक की दौड़ में है। वह क्वार्टर फाइनल में क्रिस्टेले रौढ्रिगेज डोबलर से 2-11 से हार गई थी। डोबलर के फाइनल में पहुंचने से स्वीटी को रेपेशॉज खेलने का मौका मिला है जिसमें वह चीन की शियापटोंग झेंग से खेलेगी। वैष्णवी पाटिल भी 65 किलो वर्ग में रेपेशॉज के जरिये पदक की दौड़ में है। वह जापान की हारूका कोबारू से खेलेंगी।

डेनमार्क ओपन : त्रीसा-गायत्री की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची

एजेंसी, ओडेंस। भारत की त्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने डेनमार्क ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला युगल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने गुरुवार को राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में इंडोनेशिया की पांचवीं वरीयता प्राप्त रेचल अलेस्स्या रोज और फेबी सेटियानिंगरम को सीधे गेमों में 21-16, 21-17 से हराया। भारतीय जोड़ी ने शुरुआती गेम में कड़े मुकाबले के बाद नियंत्रण हासिल किया। दूसरे गेम में इंडोनेशियाई खिलाड़ियों ने वापसी की कोशिश की, लेकिन त्रीसा और गायत्री ने संयम बनाए रखते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। त्रीसा ने पिछले कोर्ट से आक्रामक खेल दिखाया, जबकि गायत्री ने नेट पर मजबूती से मोर्चा संभाला। भारतीय खिलाड़ियों ने शुरुआती संघर्ष के बाद अपनी रक्षापंक्ति को बेहतर किया और गलतियों पर अंकुश लगाते हुए पहला गेम 21-16 से जीता। दूसरे गेम में भी उन्होंने इसी लय को बरकरार रखा और 21-17 से जीत दर्ज की। त्रीसा और गायत्री ने राउंड ऑफ 32 में चीनी ताइपे की चेन यान फेई और हिसएह पेई शान को 22-20, 21-14 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया था।

मैनचेस्टर यूनाइटेड की आलोचना करने पर मार्टिनेज ने मांगी माफी

एजेंसी, मैनचेस्टर। मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडर लिसांद्रो मार्टिनेज ने एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ चैंपियंस लीग में हार के बाद क्लब के शीर्ष अधिकारियों की आलोचना करने के लिए गुरुवार को माफी मांगी। उन्होंने मुख्य कोच माइकल कैरिक और क्लब के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात के बाद यह माफी मांगी। मार्टिनेज ने मंगलवार को 0-2 की हार के बाद कहा था कि टीम को सर्वोच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्लब को अधिक निवेश करने की जरूरत है। प्रशिक्षण सत्र के बाद मार्टिनेज ने कैरिक और क्लब के अधिकारियों से बातचीत की। साक्षात्कार के बाद यह उनका दूसरा सार्वजनिक बयान था। उन्होंने सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर कहा कि बातचीत सकारात्मक रही और इसमें मंगलवार के मैच के बाद हुई घटनाओं पर खुलकर विचार साझा किए गए। मार्टिनेज ने अपने बयान में कहा, 'आज मैंने क्लब के नेतृत्व और मुख्य कोच से मुलाकात की। यह बातचीत बहुत सकारात्मक रही, जिसमें हम अपने विचार साझा करने और मंगलवार के मैच के बाद जो कुछ हुआ, उस पर खुलकर बात करने में सक्षम रहे। 'अर्जेंटीना के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मार्टिनेज ने स्वीकार किया कि हार के बाद उनकी निराशा उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए गलत समय चुनने पर माफी मांगी।

ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत, जो अपने ही काम सवाल उठाएं: बिंद्रा

एजेंसी, नई दिल्ली। भारत के महान निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने शुक्रवार को कहा कि देश को ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है जो अपने ही काम पर, उन्हें बताई गई प्रक्रिया पर और उस ढांचे पर सवाल उठाए, जिसमें वह काम करते हैं। बीजिंग ओलंपिक 2008 में व्यक्तिगत स्पर्धा का ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बिंद्रा ने कहा कि उन्हें सफलता इसीलिये मिली क्योंकि वह सवाल पूछने का सामर्थ्य रखते थे। उन्होंने संदर्भ का जिक्र नहीं करते हुए खिलाड़ियों को एक्स पर सलाह देते हुए कहा ,' मेरे पूरे खेल कैरियर में मैने कोचों से सवाल पूछे, सुझावों को चुनौती दी और उत्सुकता नहीं छोड़ी। इसलिए नहीं कि मैं सम्मान नहीं करता था बल्कि इसलिये कि मैं समझकर सीखना चाहता था।' उन्होंने कहा ,'मुझे चिंता है कि जब खिलाड़ियों को लगता है कि वे खुलकर अपनी बात नहीं कह सकते, तो समय के साथ कुछ कहीं ज्यादा चिंताजनक स्थिति पैदा हो जाती है। वे धीरे-धीरे अपने मन में भी सवाल पूछना बंद कर देते हैं। और जब ऐसा होता है, तो हम खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जरूरी एक अहम चीज खो देते हैं।' बिंद्रा ने कहा ,'' हमें ऐसे खिलाड़ी चाहिये जो अपने काम, अपने कोचों और उन्हें बताई गई प्रक्रिया पर सवाल उठा सकें । विद्रोह के लिये नहीं बल्कि बेहतर प्रदर्शन की वास्तविक इच्छा के लिए। कुछ को यह अनुशासनहीनता लग सकती है लेकिन विकास के लिये जरूरी है।'

बैडमिंटन : तन्वी शर्मा डेनमार्क ओपन के क्वार्टर फाइनल में

एजेंसी, ओडेंस

भारत की 17 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने डेनमार्क ओपन 2026 के महिला एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने वीरवार देर रात खेले गए राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में जर्मनी की यवोन ली को 21-17, 21-19 से हराया।

अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना पहली बार विश्व की नंबर एक खिलाड़ी दक्षिण कोरिया की आन से यंग से होगा। तन्वी ने यवोन ली के खिलाफ केवल 39 मिनट में जीत दर्ज की। दूसरे गेम में कड़ी चुनौती मिलने के बावजूद भारतीय खिलाड़ी ने धैर्य बनाए रखा और सीधे गेमों में मुकाबला अपने नाम किया। तन्वी ने पहले गेम की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। यवोन ली लगातार पिछड़ने के बाद वापसी की कोशिश करती रहीं, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने 21-17 से गेम जीत लिया।

दूसरे गेम में जर्मनी की खिलाड़ी ने अधिक चुनौती पेश की। मुकाबला अंक-दर-अंक



विश्व नंबर एक आन से यंग से होगा मुकाबला

आगे बढ़ा और कई मौकों पर यवोन ने बढ़त भी हासिल की। हालांकि, 16-16 की बराबरी के बाद तन्वी ने लगातार चार अंक जुटाकर निर्णायक बढ़त बना ली। यवोन ने फिर संघर्ष करते हुए स्कोर 19 तक पहुंचाया, लेकिन तन्वी ने लगातार दो अंक हासिल कर 21-19 से गेम और मैच जीत लिया।

एशियाई पैरा गेम्स में भारत के खिलाड़ियों को अपने शुरुआती मुकाबलों में मिली कामयाबी

बैडमिंटन में सुहास, टेबल टेनिस में भाविना का जीत से आगाज

एजेंसी, नागोया

दो बार के पैरालंपिक रजत पदक विजेता और गत चैंपियन सुहास एल वाई ने एशियाई पैरा खेलों की बैडमिंटन स्पर्धा में जीत के साथ आगाज करते हुए पुरुषों के एकल एसएल4 ग्रुप ई मैच में बांग्लादेश के जॉयतू धर को सीधे गेम में हराया। प्रशासनिक अधिकारी सुहास ने टोक्यो और पेरिस पैरालंपिक में रजत पदक जीता था, जबकि पिछले एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया था। उन्होंने यह मुकाबला 21-8, 21-11 से जीता। वहीं, टोक्यो पैरालंपिक रजत पदक विजेता भाविना पटेल ने एशियाई पैरा खेलों में अपने अभियान का आगाज कुवैत की अहद अलरशीदी पर महिला टेबल टेनिस स्पर्धा के पहले दौर में जीत के साथ किया। भाविना ने महिला एकल ग्रुप ए के क्लास 4-5 मैच में 11-6, 11-3, 11- 6 से जीत दर्ज की। पैरा टेबल टेनिस में क्लास चार और क्लास







पांच व्हीलचेयर खिलाड़ियों (क्लास 1-5) के बीच उच्च-कार्यशील स्तरों को दर्शाते हैं, जहाँ खिलाड़ियों के पास बैठने के संतुलन और कोर या हाथ के नियंत्रण की अलग-अलग डिग्री होती है। बेबी सहाना रवि ने महिला एकल क्लास नौ ग्रुप बी के मैच में वियतनाम की थि होआ फुओंग एंगुयेन को 11- 6, 11- 5, 11- 4 से हराया। पैरा टेबल टेनिस में क्लास नौ उन एथलीटों के लिए एक स्टैंडिंग स्पोर्ट्स क्लास है जिनके पैरों या खेलने वाले हाथ में हल्की शारीरिक दिक्कतें हैं, या जिनके न खेलने वाले हाथ में गंभीर दिक्कतें हैं। शुभम वाधवा ने पुरूष एकल क्लास तीन ग्रुप मैच में नेपाल के केशव थापा को 11-6, 11- 4, 11 . 9 से हराया । जेहान मदान ने हमवतन संदीप डांगी को 11-8, 12-10, 10-12, 11 -6 से मात दी ।

पुरुषों के एकल एसएल4 वर्ग में अभिजीत सखुजा ने चीनी ताइपै एन चुआन येह को 21 -17, 21-12 से मात दी। तोक्यो पैरालम्पिक स्वर्ण पदक विजेता और एशियाई पैरा खेलों के रजत पदक विजेता कृष्णा नागर ने चीनी ताइपै के जिया सियांग लिंग को 21- 5, 21 -4 से हराकर जीत के साथ आगाज किया। एसएच6 वर्ग में एक और भारतीय सिवराजन सोलाइमलाइ ने ग्रुप डी में फिलीपींस के जॉन साइरस मेकलांग को 21-7, 21-6 से हराया।

पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय रणनीतिक व्यापार कमान केंद्र का किया उद्घाटन

भारत के व्यापार तंत्र की निगरानी करेगा नया कमान केंद्र

एजेंसी, नई दिल्ली

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को वाणिज्य भवन स्थित मंत्रालय के मुख्यालय में राष्ट्रीय रणनीतिक व्यापार कमान केंद्र (एनएसटीसीसी) का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और विदेश व्यापार महानिदेशक लव अग्रवाल भी उपस्थित थे। गोयल ने कहा कि यह केंद्र आंकड़ों पर आधारित व्यापारिक निर्णय लेने और देश की अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों से संबंधित 'स्कोमेट' डैशबोर्ड की समीक्षा करते हुए लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटारे पर जोर दिया। उन्होंने सभी आवेदनों पर समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति की नियमित बैठकें आयोजित करने की सलाह दी।

आयात-निर्यात प्रक्रियाओं पर बढ़ेगी निगरानी



वाणिज्य विभाग की ओर से विकसित यह कमान केंद्र विभिन्न व्यापार-संबंधी प्रणालियों के आंकड़ों को एक मंच पर उपलब्ध कराएगा। इसके माध्यम से वरिष्ठ नीति निर्माता और सरकारी अधिकारी देश के व्यापार प्रदर्शन, निर्यात संवर्धन योजनाओं, नियामकीय मंजूरियों, लंबित आवेदनों और परिचालन गतिविधियों की निगरानी कर सकेंगे। इसमें उपलब्ध संवादात्मक डैशबोर्ड प्रमुख व्यापार संकेतकों, योजनाओं के प्रदर्शन, आवेदन निपटारे की समयसीमा, क्षेत्रीय रुझानों और अनुपालन संबंधी मानकों की जानकारी देंगे। इससे व्यापारिक गतिविधियों में आने वाली बाधाओं की पहचान कर समय रहते आवश्यक कदम उठाने में मदद मिलेगी। प्रारंभिक चरण में केंद्र में विदेश व्यापार महानिदेशालय के प्रमुख कार्यों से संबंधित डैशबोर्ड शामिल किए गए हैं। इनमें आयात-निर्यात कोड, अग्रिम प्राधिकरण, निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना, उत्पत्ति प्रमाणपत्र, स्कोमेट और प्रतिबंधित आयात-निर्यात सहित विभिन्न नियामकीय प्रक्रियाएं शामिल हैं। इनके माध्यम से क्षेत्रीय प्राधिकरणों के प्रदर्शन, योजनाओं के उपयोग और निर्यात दायित्वों की निगरानी की जा सकेगी।

टेस्ला की नई रोडस्टर हवा में भरेगी उड़ान

एजेंसी, नई दिल्ली। अमेरिकी उद्योगपति इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने 16 अक्टूबर को अपनी दूसरी पीढ़ी की रोडस्टर कार का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार एक घुमावदार रैंप पर चढ़ने के बाद हवा में उछली, पलटी और सुरक्षित जमीन पर उतर गई। कंपनी के अनुसार, कार में रॉकेट तकनीक पर आधारित थ्रस्टर्स लगाए गए हैं, जो इसे हवा में उठने और कलाबाजियां करने में मदद करते हैं। मस्क ने इसे टेस्ला और स्पेसएक्स के इंजीनियरों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम बताया। उनके मुताबिक, कार में उच्च दबाव वाली हवा के टैंक और दिशा नियंत्रित करने वाले थ्रस्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी का दावा है कि यह कार महज 0.81 सेकेंड में 97 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। मस्क ने बताया कि रोडस्टर का उत्पादन 2028 में शुरू करने की योजना है। इसकी बुकिंग के लिए 50 हजार डॉलर जमा करने होंगे।

सेंसेक्स 413 अंक चढ़कर 74,729 पर बंद, निफ्टी में 148 अंकों की तेजी

एजेंसी, मुंबई

शेयर बाजार में शुक्रवार, 16 अक्टूबर को तेजी देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 413 अंक चढ़कर 74,729 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी में भी 148 अंकों की बढ़त दर्ज की गई और यह 23,146 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में आई तेजी के पीछे आईटी और मीडिया कंपनियों के शेयरों में हुई जोरदार खरीदारी प्रमुख वजह रही। निवेशकों की सकारात्मक भागीदारी से दोनों प्रमुख सूचकांकों में मजबूती देखने को मिली। भारतीय बाजार के साथ एशियाई बाजारों में भी तेजी का रुख रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 114 अंक यानी 2.05 प्रतिशत चढ़कर 5,668 के स्तर पर पहुंचा। जापान का निक्केई 898 अंक यानी 1.39 प्रतिशत की बढ़त के साथ 65,324 पर बंद हुआ, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग 124 अंक यानी 0.52 प्रतिशत बढ़कर 24,187 के स्तर पर रहा।



घरेलू निवेश से बाजार को संबल

इससे पहले गुरुवार को अमेरिकी बाजारों में भी तेजी दर्ज की गई थी। डाउ जोन्स 556 अंक यानी 1.08 प्रतिशत चढ़ा, जबकि नैस्डैक में 0.08 प्रतिशत और एसएंडपी 500 में 0.33 प्रतिशत की बढ़त रही। हालांकि, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की बिकवाली बाजार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। पिछले सात कारोबारी दिनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 10,157 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की। वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने इसी अवधि में 11,474 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की। बीते 30 दिनों में भी एफआईआई की शुद्ध बिकवाली 89,516 करोड़ रुपये रही।

तमिलनाडु का 1.755 टन जैविक ताड़ गुड़ पहली बार बुल्गारिया पहुंचा

एजेंसी, नई दिल्ली। भारत का पारंपरिक ताड़ का 1.755 मीट्रिक टन गुड़ का पाउडर तमिलनाडु से बुल्गारिया के बाजार में पहुंचा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने जैविक ताड़ के गुड़ के पाउडर के निर्यात में सहायता प्रदान की है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने 15 अक्टूबर को तमिलनाडु के इरोड जिले स्थित गोबिचेट्टीपलयम से बुल्गारिया के वर्ना के लिए 1.755 मीट्रिक टन एनपीओपी और यूरोपीय संघ द्वारा प्रमाणित जैविक ताड़ के गुड़ पाउडर (ताड़ के फूल का रस) की पहली निर्यात खेप को एपीडा के अध्यक्ष अभिषेक देव ने 15 अक्टूबर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्रालय के मुताबिक 1.755 मीट्रिक टन जैविक गुड़ पाउडर का निर्यात की गई यह खेप भारत के ताड़ के पेड़ से बने पारंपरिक उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पेश करने और देश के जैविक निर्यात उत्पादों में विविधता लाने की दिशा में अहम कदम है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस खेप का निर्माण और निर्यात ईरोड स्थित मेसर्स वेलबीइंग फूड्स द्वारा चेन्नई स्थित मेसर्स चेट्टी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया गया है। यह खेप चेन्नई बंदरगाह के माध्यम से समुद्री मार्ग से भेजी जाएगी।

- **भारतीय ताड़ उत्पादों के लिए खुला यूरोपीय बाजार**
- **ताड़ गुड़ के निर्यात से बढ़ेगी किसानों की आय**

व्यापार भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मिल सकती है गति

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जल्द पूरा होगा: सीतारमण

एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीद जताई है कि वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने और भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के हित में व्यापार समझौते को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच इस समझौते को लेकर बातचीत अभी जारी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी गुरुवार को बताया था कि समझौते का पहला चरण तय हो चुका है और फिलहाल इसका कानूनी मसौदा तैयार किया जा रहा है।

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी पोस्ट में बताया कि सीतारमण ने थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान दक्षिण एशिया के रेजिडेंट सीनियर फेलो माइकल कुगेलमैन के साथ आयोजित संवाद सत्र में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता दोनों साझेदार देशों के आर्थिक हितों के साथ-साथ वैश्विक व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे जल्द पूरा करने की उम्मीद है। सीतारमण ने चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बीजिंग के साथ कई वर्षों की बातचीत के बावजूद व्यापार असंतुलन बढ़ रहा है।

संसाधनों तक सबकी पहुंच

सीतारमण ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि समाज के सभी वर्गों को संसाधनों तक पहुंच मिले और युवाओं को कौशल विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। इसके साथ ही आर्थिक विकास की प्रक्रिया में वित्तीय अनुशासन बनाए रखना भी जरूरी है। उन्होंने सार्वजनिक धन के विवेकपूर्ण इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को लेकर सजग है और बेतहाशा खर्च नहीं कर सकती। हालांकि, अर्थव्यवस्था के कमजोर तबकों की जरूरतों का ध्यान रखना भी आवश्यक है।



सीतारमण ने चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बीजिंग के साथ कई वर्षों की बातचीत के बावजूद व्यापार असंतुलन बढ़ रहा है।

बैंकॉक में वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर हुई चर्चा

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी पोस्ट में बताया कि सीतारमण ने थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान दक्षिण एशिया के रेजिडेंट सीनियर फेलो माइकल कुगेलमैन के साथ आयोजित संवाद सत्र में यह बात कही।

आर्थिक वृद्धि की राह पर भारत

वित्तमंत्री ने भारत की आर्थिक वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि विभिन्न चुनौतियों के बावजूद देश अपनी विकास दर बनाए रखने में सफल रहा है। कोविड महामारी के बाद पिछले चार-पांच वर्षों में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन सरकार की ओर से लगातार किए जा रहे प्रयासों के अनुरूप है। इसमें समावेशी विकास की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। सीतारमण ने चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों पर भी चिंता जताई।